

आर्थिक संगठन

समाजवाद या पूँजीवाद



“ मानव समाज के उद्धार का एक मात्र उपाय
समाजवाद है ”



लेखकः—

ठाकुरप्रसाद सक्सेना

बी० काम०, एल एल० बी०



१९३६

प्रथम संस्करण १०००]

[मूल्य ॥॥]

मुद्रक— ऐंग्लो अरेबिक प्रेस, नौबस्ता, लखनऊ ।

—
Jokhiram Baijnath.
173, Harison Road;
Calcutta.

भारत के सवे प्रथम समाजवादो नेता
पं० जवाहर लाल नहरू
को सेवा में सादर
समर्पति
ॐ

भूमिका

—:०:—

आज पूँजीवाद प्रति क्रिया के रूप में हो जीवित रह सकता है। उसके विकृत रूप फ्रैसिज्म और समाजवाद में आज संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष के नतीजे पर संसार का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है। समाजवाद आज केवल वाद विवाद का विषय नहीं रह गया है। संसार के एक बड़े भूभाग में समाजवाद की स्थापना हो गई है। वहाँ समाजवाद के मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार नूतन समाज का निर्माण हो रहा है। यह प्रयोग अत्यन्त शिक्षाप्रद है। रूस ने एक नए आधार पर दुनियाँ बसाने का विराट आयोजन किया है और इस कार्य में उसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। आज समाजवाद के सम्बन्ध में धनी हुई नाना प्रकार की मिथ्या धारणाओं का सहज हो खण्डन हो जाता है। आज आप इस दो प्रकार की पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि मानव समाज के कल्याण और अभ्युदय के लिये कौन सी पद्धति श्रेयस्कर है।

प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति को जो आज की दुनियाँ से अपरिचित रहना नहीं चाहता इन दो प्रधान विचार धाराओं का अध्ययन करना चाहिए। हम एक क्रान्तिकारी युग में रह रहे हैं। चारों ओर हमारे सामने ही बड़े-२ परिवर्तन हो रहे हैं। दुनियाँ तेजी से बदल रही है। इस जमाने में आज के बड़े-२ मसलों के प्रति उपेक्षा भाव रखना भारी पाप है। नई-२ शक्तियाँ आज संसार को हिला रही हैं, हमें उनको समझने की कोशिश करना चाहिए और बुद्धिपूर्वक अपना मार्ग स्थिर करना चाहिए।

प्रस्तुत पुस्तक मे पूँजीवाद के दोष दिखाए गए हैं और यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि पूँजीवाद की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। लेखक ने समाजवाद के सिद्धान्तों का अच्छा निरूपण किया है और यह दिखाया है कि वह समस्त साधन आज उपलब्ध हैं जिन का आश्रय लेकर हम समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार समाज का नया संगठन कर सकते हैं। समाजवाद के विरुद्ध जो तर्क आम तौर से पेश किए जाते हैं उनका उत्तर देने की भी चेष्टा की गई है। समाजवाद की क्या विशेषताये हैं, उसके द्वारा समाज की कैसे उन्नति हो सकती है, समाजवाद की स्थापना का प्रकार क्या है, समाजवादों संगठन का क्या रूप है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर आपको इस पुस्तक में मिलेगा। एक अध्याय में लेखक ने सोवियट रूस के नवीन आर्थिक संगठन का भी वर्णन किया है।

पुस्तक प्रमाणिक ग्रन्थों की सहायता से तैयार की गई है। शैली सुगम और रोचक है। आशा है हिन्दी पाठक पुस्तक से लाभ उठावेगे।

नरेन्द्रदेव



दो शब्द

—:०:—

देश की दरिद्रता और बढ़ती हुई बेकारों के कारण आर्थिक संगठन के प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक हो गया है । संगठन छोटे २ दैहाती धन्धों के आधार पर हो, अथवा बड़े २ कारखानों के रूप में, इन कारखानों का आधिपत्य व्यक्ति विशेष के हाथ में रहे अथवा शासन के, इन प्रश्नों पर भिन्न २ विचार प्रकट किए गए हैं । रूस की क्रान्ति के प्रभाव में साम्यवाद का भी प्रचार हो रहा है । अल्प शिक्षित जन-समूह के सम्मुख इन सिद्धान्तों को सरल भाषामें रखना ही इस प्रकाशन का ध्येय है ।

हिन्दी भाषा में इस विषय पर पुस्तकों का अभाव देखकर और उसकी आवश्यकता अनुभव करके, अल्प योग्यता होने पर भी मैंने यह पुस्तक लिखने का साहस किया है और देश की उद्योगिक उन्नति के मूल सिद्धान्तों की मोटी २ बातें सरल उदाहरण द्वारा समझाने की चेष्टा की है । देशवासियों को इन जटिल प्रश्नों के समझने में यदि थोड़ी भी सहायता दे सका, तो अपना परिश्रम सफल समझूंगा ।

पुस्तक में दोष बहुत रह गए हैं योजना और लेखन की ये त्रुटियाँ ऐसी हैं कि यदि अधिक अवकाश मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता तो उनमें कुछ कमी अवश्य की जा सकती थी । परन्तु काम बहुत थोड़े समय में ही करना पड़ा है । आशा है पाठक क्षमा करेंगे ।

इस पुस्तक को भूमिका लिखने तथा समय २ पर उत्साह और अमूल्य परामर्श देने के लिए मैं श्री आचार्य्य नरेन्द्रदेव का विशेष आभारी हूँ । लखनऊ विश्व विद्यालय के अर्थ विभाग के अध्यापक श्री शीतला प्रसादजी सक्सेना को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अधिक व्यस्त होते हुए भी इस पुस्तक को पुनरावृत्ति और संशोधन करने में विशेष सहायता दी ।

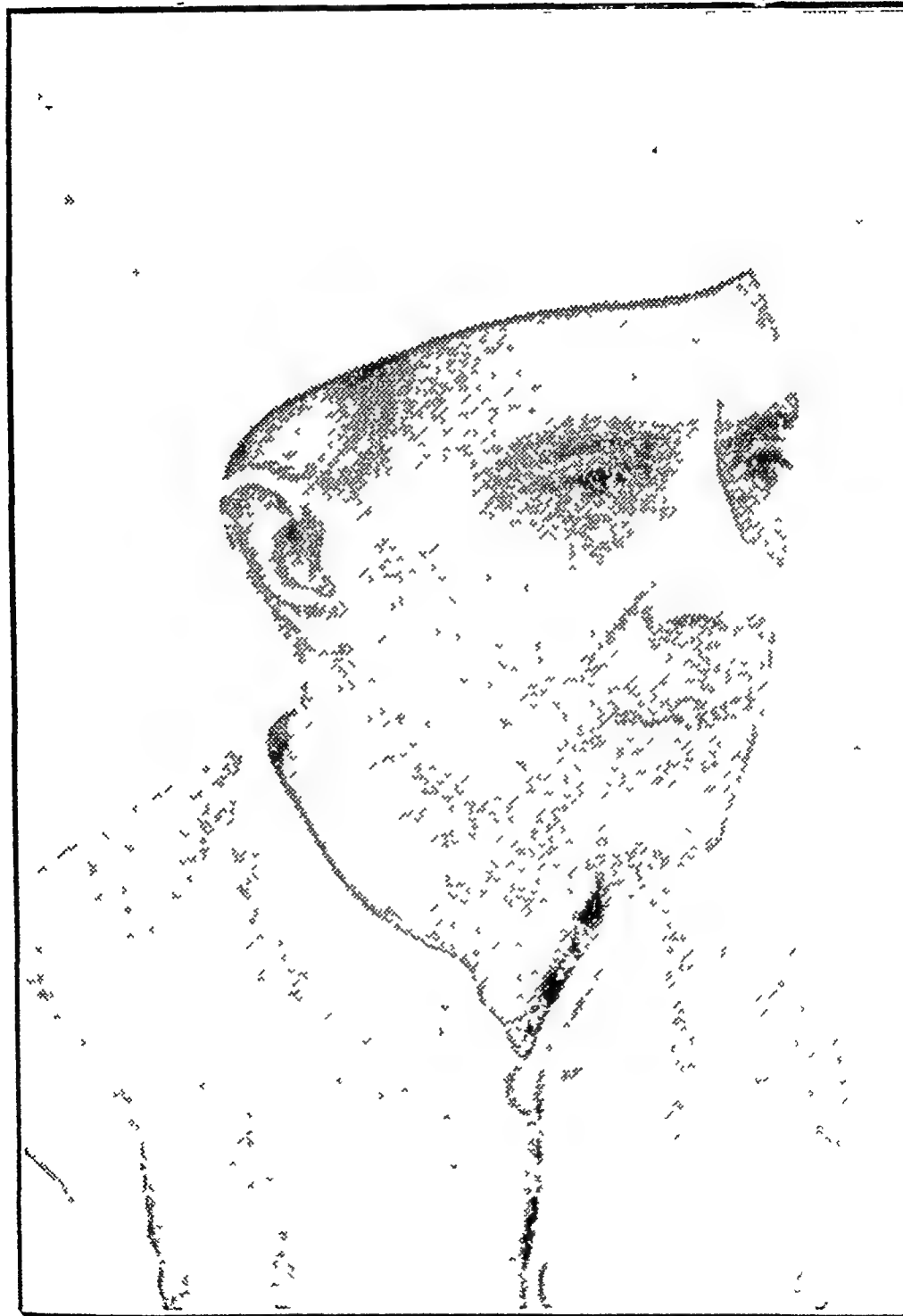
ठाकुरप्रसाद सक्सेना

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
१—पूँजीवाद और उसके दोष	१
२—समाजवाद की ओर	११
३—समाजवाद क्या है	२०
४—समाजवाद और साम्यवाद	२८
५—समाजवादी संगठन	३८
६—योजना	५४
७—प्रचलित समाजवादी ढंग (रुस का इतिहास)	६५
८—समाजवाद और पूँजीवाद	८०
९—उपज का बटवारा	८८
१०—पूँजीवाद का परिवर्तित रूप	९६
११—वर्ग अथवा श्रेणी संघर्ष	१०७
१२—बटवारे का समाजवादी ढंग	११५
१३—वर्गों का अन्त	१२६
१४—काम करने की प्रेरणा (पूँजीवाद)	१३६
१५—काम करने की प्रेरणा (समाजवाद)	१४३

आर्थिक संगठन

समाजवाद या पूँजीवाद



पं० जवाहरलाल नेहरू

पूँजीवाद और उसके दोष

इस समय संसार के अधिकांश देशों में वह आर्थिक और सामाजिक संगठन प्रचलित है जो पूँजीवाद के नाम से विख्यात है। पूँजीवाद शब्द से हमारा अभिप्राय उस आर्थिक संगठन से है जिसमें खेत, कारखाने और कानों का आधिपत्य एक अथवा कुछ थोड़े से धनी मनुष्यों के हाथ में रहता है, उपज के इन साधनों पर (means of productions) जो लोग काम करते हैं वे इन के मालिक नहीं बल्कि मजदूरी लेकर मालिकों के लाभ के लिये काम करने वाले होते हैं।

लाभ का आधार

पूँजीवादी संगठन में लाभ की इच्छा ही समाज को चलाती है, लाभ की इच्छा ही इन मालिकों को उपज के साधनों का प्रयोग करवाने के लिये प्रोत्साहित करती है। केवल इतना ही नहीं बरन उपज को रोक थाम भी इसी लाभ की इच्छा के आधार पर होती है। उपज का पहिला आधार भी यही रहता है, अर्थात् केवल वे ही चीजें बनाई जानी हैं जिन से लाभ हो सके। क्योंकि लाभ न देनेवाली चीजों का बनाने वाला कभी न कभी प्रबन्ध निर्धन तथा दीवालिया हो जावेगा, उपज के साधनों का आधिपत्य न्यो छेड़ेगा और इस प्रकार उनमें स्वाधीनता पूर्वक वस्तु बनवाने की शक्ति हो न सके जायेगी। दूसरे शब्दों में, पूँजीवाद में किसी वस्तु को बनाने प्रथवा न बनाने का परम केवल एक ही मान में होता है और वह यह कि उसके बनाने में लाभ होता है या नहीं। वस्तु की संख्या भी इसी एक आधार पर निश्चित की जाती है।

अस्तू, इस आधार पर केवल वे ही चीजें बनाई जा सकेंगी जो जनता में बिक सकें । क्योंकि उन्हीं के बनाने से लाभ हो सकता है, या यों कहे मानो लाभ एक तारा है जो उपज को मांग की ओर खींचता रहता है, क्योंकि लाभ उन्हीं वस्तुओं के बनाने में है जिनकी बिक्री हो और जिनकी बिक्री नहीं, ऐसी वस्तु बनाना स्पष्टतया लाभप्रद नहीं ही सकता । परन्तु वास्तव में ऐसी स्थिति होती नहीं । प्रत्येक वस्तु की कुछ न कुछ माँग अवश्य होती है । किसी की कम किसी की अधिक और फिर यह माँग समय के फेर तथा अन्य कारणों से घटती बढ़ती भी रहती है ।

पूँजीवाद में यह अधिक लाभप्रद होता है कि ऐसी वस्तुयें अधिक बनाई जावें जिनकी बिक्री अधिक हों, और वे कम बनाई जावें जिनकी बिक्री कम हो । इस प्रकार हमारी उपज की शक्ति बारबार लाभ की इच्छा द्वारा लगातार उन वस्तुओं को बनाने के लिये बढ़ाई जाती है जिनकी बिक्री अधिक है और इसी नियम से जिन चीजों की बिक्री कम है उनकी उपज घटा दी जाती है ।

पूँजीवाद में इसी प्रकार से काम होता है । अब देखना यह है कि इस प्रकार के संगठन का चलना अच्छा है या बुरा, और यदि बुरा है तो क्यों, और उसमें क्या क्या बुराइयाँ हैं । साधारणतया हर एक यही मानेगा कि इस प्रकार का संगठन अवश्य अच्छा होगा और भली प्रकार चलेगा क्योंकि इसमें लाभ की इच्छा से प्रेरित उपज और बिक्री में घनिष्ठ सम्बन्ध रक्खा जाता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग अधिक से अधिक लाभ के साथ किया गया होगा ।

अनियमित पैदावार

पूँजीवाद के समर्थकों की यही दलील है । उनका कहना है कि इस प्रकार के संगठन में वे ही वस्तुयें और सेवायें होती हैं जिनके लिये अधिक मूल्य मिलता है । अन्य चीजों की उपज नहीं होती । उनका तो यह दावा है कि किसी अन्य आर्थिक संगठन में इससे अधिक इच्छित लाभदायक फल होना सम्भव ही नहीं है ।

यदि उनका कहना सच हो तो फिर यह प्रश्न उठता समाजवादी ऐसे पूँजीवाद का अन्त क्यों करना चाहते उनका तो यह विश्वास है कि पूँजीवाद को यह प्रशंसा उपयुक्त नहीं। वास्तव में वे वस्तुएँ जिन्हें अधिक मनुष्य अधिकतर चाहते हैं, बनाई ही नहीं जाती वरन् उनके स्थान पर ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जिन्हें केवल मुट्ठी भर मनुष्य चाहते हैं। इतना ही नहीं, वरन् ऐसे पदार्थ भी, जिनके बिना सहस्रों मनुष्यों के प्रायः जीवन तक चले जाते हैं, केवल थोड़े से लाभ के लोभ के कारण नहीं बनाए जाते और मानव समाज का इस निर्दयता और कठोरता से नाश किया जाता है। लाभ के आगे पूँजीवाद में मानव समाज के हित का विचार तथा मनुष्यता के भावों का पतन हो जाता है और मनुष्य एक निर्जीव काठ के पुतले की भाँति केवल लाभ रूपी कड़ियों के सहारे ही काम करने लगता है, उदाहरण के लिये, इंग्लैंड तथा अमेरिका ऐसे उन्नतिशाली पूँजीवादी देशों को ही लेली जिये। अन्य देशों की बात छोड़ दोजिये स्वयं इन देशों के वासियों को भी रोटी, मांस, दूध, कपड़ा, तथा रहने के लिये घर इत्यादिक आवश्यक वस्तुओं की आज भी उत्सुकता से चाह है। ऐसे पदार्थ आवश्यकतानुसार उत्पन्न ही नहीं किये जाते क्यों कि इनके उत्पन्न करने में अधिक लाभ नहीं होता, चाहे इनके बिना सहस्रों देशवासियों का जीवन उत्सर्ग ही क्यों न हो जाय। इनके स्थान पर ऐसी अनावश्यक तथा व्यर्थ की वस्तुएँ बनाई जाती हैं जिन्हें थोड़े से धनी केवल अपने आनन्द विलास, सजधज इत्यादि के लिये चाहते हैं। उनसे पूँजीपतियों को अधिक मूल्य मिलता है। जिस समय तक लाभ के सिद्धांत पर उपज की संख्या निश्चित की जावेगी, अनावश्यक वस्तुएँ बनती ही रहेगी और उसके फलस्वरूप जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं की कमी रहेगी इसी से यह कहना पड़ता है कि जिस संगठन का परिणाम जन साधारण के लिये हानिकारक है, उसमें अवश्य बुराई है और वह कभी भी उचित तथा वांछनीय नहीं कहा जा सकता।

इस के अतिरिक्त पूँजीवाद में, कभी कभी ऐसे पदार्थ इतनी

अधिक संख्या में बन जाते हैं कि धनी लोगों को उन की मांग नहीं रहती और निर्धन उन का मूल्य दे नहीं पाते और यह फालतू संख्या नष्ट कर दी जाती है। कितना घोर अन्याय है कि एक ओर तो सहस्रो मनुष्य भोजन, कपड़ा, इत्यादि के अभाव से भूखे और नंगे रहे और दूसरी ओर देश की उपजाऊ शक्तियों का इस प्रकार दुरुपयोग किया जावे, और उन से उत्पन्न की गई वस्तुओं का नाश हो। क्या इस प्रकार की व्यवस्था लाभदायक कही जा सकती है? अथवा क्या ऐसा संगठन वांछनीय हो सकता है? कदापि नहीं।

शक्ति का अपव्यय

पूँजीवाद में इस से भी अधिक अवगुण एक यह भी है कि इस प्रकार के संगठन में बहुत से मनुष्यों को काम करने का अवसर ही नहीं मिलता। वे वस्तु बना ही नहीं पाते और भिन्न २ उपायों द्वारा उन के काम करने में बाधाएँ डाली जाती हैं। बड़े बड़े पूँजीवादी देशों में यह बहुत मात्रा में ठीक भी है वहाँ के देशवासी अपनी उपजाऊ शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। उन की यह असमर्थता की मात्रा स्थान तथा वातावरण के अनुसार न्यूनाधिक अवश्य है। उदाहरण के लिये अमेरिका ही को ले लीजिये। अमेरिका में सन् १९२६ ई० में देश की उपजाऊ शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। सम्भवतः पूँजीवादी किसी अन्य देश में इतना प्रयोग न किया गया होगा, और यदि यह कहा जावे कि उस समय उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया तो भी अनुपयुक्त न होगा। परन्तु बहुत से अर्थशास्त्रज्ञों (economists) और संख्याशास्त्रज्ञों (statisticians) का जिन्होंने सतर्कता से आँकड़ेलिये हैं कहना है कि उस वर्ष भी उपज की शक्तियों का केवल ८१ प्रतिशत ही उपयोग किया गया और उस के दूसरे वर्ष यह प्रयोग केवल ५० प्रतिशत ही रह गया। बाद के वर्षों में (अर्थात् सन् १९३०, ३१, ३२, तथा ३३, में) तो इन का प्रयोग और भी कम रह गया। इन वर्षों में अमेरिका वासी अपनी उपजाऊ शक्तियों का १६ से ५० प्रति शत से अधिक प्रयोग नहीं कर पाये।

ब्रिटैन के सन्वन्ध में इस प्रकार के आँकड़ों तो नहीं मिलते परन्तु वहाँ भी बेकारों की संख्या से ब्रिटैन की उपजाऊ शक्तियों के प्रयोग का अनुमान लग सकता है। सब बातों पर विचार करने से यह पता चलता है कि ब्रिटैन में भी गत महा युद्ध के पश्चात् कभी भी २१ प्रतिशत से अधिक उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ। गाँ। कि वहाँ कभी ५० प्रतिशत से कम भी प्रयोग नहीं हुआ है, जैसा कि सन् ३१ व ३२ में अमेरिका में इस प्रकार के आँकड़ों में दानो देशों में भिन्नता अवश्य मिलती है।

परन्तु यह बात तो विशेष महत्व की नहीं कि कितनेसही आँकड़ों में इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सका। महत्व की बात तो केवल इतनी है कि एक पर्याप्त संख्या में इस प्रकार इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सका और यह बात भी स्पष्ट है कि यदि इन शक्तियों का प्रयोग हुआ होता, और इतने मनुष्य तथा कल कारखाने बेकार न रहते, तो उनकी सहायता से बहुत से लोगों का मकान, खाना, कपड़ा, शिक्षा तथा औषधियों की सुविधा दी जा सकती, जिस के बिना वहाँ के देशवासी कष्ट उठा रहे थे।

बढ़ती हुई बेकारी

पूँजीवाद में सब से अधिक खटकने वाली वस्तु उपजाऊ शक्तियों के प्रयोग की असमर्थता है और यह असमर्थता अब इंगलैंड और अमेरिका में बहुत बढ़ गई है। बेकारी तथा विशेष कर मजदूरों की बेकारी के रूप में यह दिखाई पड़ती है। लाखों करोड़ों योग्य, परिश्रमी तथा काम के इच्छुक मजदूरों का इस प्रकार बेकार रहना बड़े दुःख की बात है। इस के फलस्वरूप होने वाली हानि का तो कहना ही क्या इस बेकारी से केवल यही नहीं कि वे पदार्थ जाँ कि यह बेकार मजदूर बना, बन नहीं पाते वरन् इन मजदूरों का भी निर्धनता, बेकारी तथा समाजिक ग्लानि के कारण धीरे धीरे काफी ह्रास होता जाता है। यही कारण है कि अमेरिका और ब्रिटैन में इस समय भी पूँजीवाद के आधार पर उपज्जाने हुए भी अन्याय तथा अनुपयोग के कारण इस

प्रकार का संगठन असहनीय हो रहा है, पूँजीवाद में लाखों और करोड़ों मनुष्य न केवल थोड़े से धनी मनुष्यों की मूर्खता की माँगों को पूरा करने के लिये प्रति दिन कठिन परिश्रम ही करते हैं, वरन् किसी को भी उन वस्तुओं के बनाने की, जैसे खाना, कपड़ा, घर इत्यादि जिनकी अधिक लोगो को माँग है, पर्याप्त सुविधा नहीं और रुब से बुरी बात तो यह है कि इस प्रकार के संगठन में लाखों व करोड़ों मजदूर वस्तु बनाने तथा काम करने से ही रोक दिये जाते हैं। इस आर्थिक संगठन की असफलता का ही यह परिणाम है कि दिन प्रति दिन निर्धनता तथा गरीबी बढ़ती जाती है।

जनता की दरिद्रता

विख्यात पूँजीवादी अर्थशास्त्रज्ञ जान स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) का स्वयं यह कहना है कि पूँजीवादी संगठन में किसी एक मजदूर का काम करने का एक घंटा भी कम नहीं हो सका, वरन् बहुत से वर्तमान पूँजीवादी देशों के लिये तो यह भी कहा जा सकता है कि उन देशों की अधिकतर जनता को न तो एक गज कपड़ा ही अधिक मिल सका और न एक कौर रोटी ही। इस के विपरीत इंग्लैंड और अमेरिका में, जो संसार के दो सबसे बड़े धनी व पूँजीवादी देश हैं, अधिक तर जनता निर्धन ही हो गई है।

इंग्लैंड में ही सम् १९३६ ई० में दो तिहाई जनता की वार्षिक आय लगभग २५ पौंड प्रति मनुष्य थी। ओ.आर. होलिसन (O.R. Holson) सुविख्यात अर्थशास्त्री की गणना के अनुसार जो सम् १९३४ ई० के जुलाई मास में प्रकाशित हुई है, सम्भवतः उन लोगो के लिये जिनकी आय अधिक है यह समझना कठिन है कि इतनी कम आय में मनुष्य को जीवन की आवश्यक समग्री प्राप्त करने में रुकावट इत्यादि से कितना कष्ट होता है, परन्तु हम भारतवासी तो इस बात को केवल भलीभाँति समझते ही नहीं वरन् विशेषरूप से अनुभव भी करते हैं। यहाँ की निर्धनता तो इससे भी अधिक है, यहाँ तो अधिकतर मनुष्यों को दोनो समय खाने को पैट भर भोजन तक भी नहीं मिल पाता।

निर्धनता द्वारा होने वाली यह असह्य यातना अनावश्यक है और इस का निवारण हो सकता है। वास्तव में इस निर्धनता का कारण यह नहीं है कि आवश्यकतानुसार काम तथा पदार्थ उत्पन्न नहीं किये जा सकने, वरन् प्रचलित आर्थिक संगठनकी अजफलता तथा खोखलापन है, क्योंकि इस संगठन में उपजाऊ शक्तियों के एक बड़े भाग का प्रयोग ही नहीं होता और दूसरे भाग का इस प्रकार दुरुपयोग होता है कि उस के द्वारा सांसारिक आवश्यकताएँ अधिकतर पूरी ही नहीं की जा सकती।

समाज की उत्पादन शक्ति

वास्तव में इस समय पूँजोवादी देश अमेरिका तथा इंग्लैंड में भी पर्याप्त संख्या में पदार्थ उत्पन्न किये जा सकते हैं जिनसे वहाँ की साधारण जनता सुखी तथा प्रसन्न रह सके। इस का ठीक ठीक अनुमान तो नहीं लग सकता कि यदि अमेरिका और ब्रिटैन में उपजाऊ शक्तियों का पूरा प्रयोग जनता की आवश्यकताओं को उनकी माँग के अनुसार पूरा करने में लगातार किया जावे तो वहाँ के देशवासियों के रहन सहन में कितना अन्तर पड़ जावेगा। परन्तु यह निश्चय है कि जनता के कष्ट बहुत कुछ कम हो जावेगे। अमेरिका के सम्बन्ध में इस विषय के आँकड़े भी मिलने हैं, वहाँ सन् १९३४ ई० में देश के कल कारखानों और खेती की उपजाऊ शक्तियों का अनुमान करने के लिये सरकार ने एक जाँच कमेटी नियत की थी उस को रिपोर्ट सन् १९३५ के फरवरी मास में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि अमेरिका की उपजाऊ शक्तियों का पूरा प्रयोग किया जावे और उपज सब कुटुम्बों में बराबर बाँटी जावे तो प्रत्येक चार मनुष्यों के कुटुम्ब की आय १६२६ ई० के मूल्य के आधार पर ४४०० डालर (६१५ पौंड) प्रतिवर्ष होगी। कहाँ तक यह अनुमान ठीक है और किन परिस्थितियों में यह सम्भव है, इसका विचार इस स्थान पर न करके हम इस अनुमान को सही मान लेते हैं क्योंकि अमेरिका के कई योग्य अर्थशास्त्रज्ञ कई महीनों के कड़े परिश्रम तथा सब आवश्यक बातों को विस्तार पूर्वक जाँच करने के

पश्चात् ही इस परिणाम पर पहुँचे हैं ।

अमेरिकावासियों की आय ६१५, १००० अथवा ७०० ही पौंड हो, इससे हमें अधिक प्रयोजन नहीं । हमारा तो इतना ही कहना है कि इस प्रकार उन्नतिशाली देश, जैसे ब्रिटैन व अमेरिका, केवासियों को भी निस्संदेह इतनी निश्चित आय हो सकती है जब कि इन देशों में इस समय साधारणतया एक कुटुम्ब की आय ७५ से २०० पौंड तक है । अतः यह कहा जा सकता है कि उच्च कौंट के उन्नतिशाली पूँजीवादी देशों में भी उपज की वृद्धि, समान आय की व्यवस्था, और ७५ पौंड से २०० पौंड प्रतिवर्ष आय के स्थान पर ७०० अथवा १००० पौंड आय होना अब भी सम्भव हो सकता है ।

जीविका की अनिश्चितता

पूँजीवाद के दुरुपयोग का परिणाम केवल अनावश्यक निर्धनता ही नहीं । उपज की अधिकता से ज्यादा मनुष्यों को अपने जीवन निर्वाह की संरक्षता की इच्छा होती है । उन्हें लगातार यह भय रहता है कि उनकी वर्तमान आय कहीं कम अथवा नष्ट न हो जावे । कुछ थोड़े से धनी और नितान्त निर्धनों को छोड़ कर अमेरिका तथा ब्रिटैन जैसे उन्नतिशाली देशों की भी अधिकांश जनता बेकारी व निर्धनता के भय से काँपा करती है । कारखानों में साप्ताहिक बेतन पानेवाले, छोटे स्वतंत्र मालिक, जैसे किसान इत्यादि और सर्वसाधारण मजदूरों के लिये तो कम से कम यह बात समान है । इन सब को निरन्तर अपनी बेकारी का भय रहता है । वर्तमान व्यापार पद्धति में, अचानक तथा विप्लवकारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिन से छोटे छोटे स्वतंत्र धन्ये प्रायः विलकुल दब जाते हैं और बहुधा नष्ट भी हो जाते हैं, जिसतरह कि बड़े समुद्रों के नौकानों से छंटी छोटी नावों उलट जाती हैं । अस्तु, वर्तमान आर्थिक संगठन का परिणाम जनता के लिये अनिश्चितता तथा अरक्षिता होती है और इन की मात्रा प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है ।

किसी मनुष्य की जीविका चली जाने से, उन्नतिशाली देशों में

उसके बाल बच्चे तुरन्त ही भूखे मरने तो नहीं लगते परन्तु उन पर काफ़ी संकट पड़ जाता है। कुछ स्वतंत्र देशों में बेकारों को रोटी कपड़े के लिये सहायता का भी प्रबन्ध है परन्तु तो भी सहायता के धन की कमी, उसके मिलने की अनिश्चितता, तथा उन शर्तों के कारण जिन पर वह मिलता है बेकारों के संकटों में कोई विशेष कमी नहीं होने पायी। वे शीघ्र मर तो नहीं जाते परन्तु उनके जीवन इतने संकटमय हो जाते हैं कि बेकारी का भय उन्हें हमेशा भूत की तरह सताता रहता है।

जीविका की लगातार चिन्ता का जनता के चित्त पर भी बुरा प्रभाव होता है। बहुत से अपने जीवन का विलकुल निस्तहाय तथा निरर्थक समझने लगते हैं। प्राचीन काल में जंगलों में वास करने वाले मनुष्य भी इस प्रकार अनिश्चितता और विवशता के बशो भूत नहीं होते थे ! उन्हें केवल प्राकृतिक संकटों का ही भय रहता था। और वह इस प्रकार के सामाजिक संकटों से कहीं कम दुःखदाई होते थे।

परिवर्तन से लाभ

जो कुछ भी हो, यह तो सिद्ध ही है कि यदि उपजाऊ शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग किया जावे तो जन समाज के रहने सहने के लिये एक निश्चित व्यवस्था हो सकती है। यह भी स्पष्ट है कि उपजाऊ मशीनों को इतना सुस्त रखने तथा करोड़ों मनुष्यों को बेकार और निर्धन रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। इतने पर भी देश पूँजीवादी संगठन को नहीं छोड़ते।

हमारे लिये केवल यही समस्या नहीं है कि हम वर्तमान स्थिति में ही पड़े रहे अथवा उसकी उन्नति करें। सच तो यह है कि या तो उपजद्वे और जीविका निश्चित हो नही तो जीविका हरण तथा निर्धनता से होने वाले कष्टों को सहे जिनके द्वारा इस समय भी बहुत

सी जीव हत्याये हो चुकीं हैं। समाज की वर्तमान बुराइयाँ पूँजीवादो संगठन के फलस्वरूप हो हैं और इस संगठन को परिवर्तित किये बिना वे दूर भी नहीं की जा सकती, वे दिन प्रति दिन बढ़ती हो जावेंगी। पूँजीवाद का तो स्वभाव ही यही है कि उस में अनिश्चितता तथा अनावश्यक निर्धनता हो। इस से भी अधिक हानिकारक परिणाम घरेलू झगड़े और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध होता है। यह युद्ध पूँजीवाद का अनिवार्य फल हैं जो मानव समाज का ही नाश कर देता हैं। पूँजीवाद का तो स्वभाव ही ऐसा है। इसीलिये तो समाजवादी चाहते हैं कि इस पूँजीवादी संगठन से समाज का छुटकारा हो।



समाजवाद की ओर

पूँजीवाद और उसके दोषों से पाठक अब अनभिज्ञ नहीं इन्ही दोषों को देखकर तथा उनसे प्रभावित होकर ही जन समाज समाजवाद की ओर आकर्षित होता है ; पूँजीवाद के स्थान में अन्य किसी दूसरे आर्थिक संगठन की खोज करता है और धीरे धीरे दिना जाने बूझे निश्चित रूप से समाजवादी संगठन की ओर खिंचता है और उसे ही अपनाने लगता है । सर्व प्रथम तो इन परिस्थितियों का प्रभाव मजदूर तथा अन्य शोषित वर्गों पर पड़ता है और वे पूँजीवादी संगठन से उकताकर समाजवाद की ओर अग्रसर होते हैं । पूँजीवाद से होने वाली हानि भी सब से अधिक इसी वर्ग पर पड़ती है और वे ही उससे बचने के लिये सर्वप्रथम उपाय करते हैं । परन्तु इससे यह अभिप्राय नहीं कि अच्छे वेतनवाले तथा धनी मनुष्यों पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता और न वे इस पूँजीवादी संगठन से उकताते ही हैं । पूँजीवादी संगठन का दुःप्रभाव धीरे धीरे इन वर्गों पर भी पड़ता जाता है और वे भी इसके खोखले और जन समाज के घातक परिणामों को भली भाँति महसूस करने लगते हैं ।

समाजवाद उसके उद्देश्य और कार्यक्रम आदि केवल मजदूरों और नीची श्रेणी के वर्गों के लिये ही विचारणीय नहीं है वरन् उन लोगों के लिये भी है जिनकी अधिक स्थिति कुछ सुधरी हुई है । कुछ भाग्यशाली अल्पसंख्यक लोगों के लिये ऐसे प्रश्न, जैसे उपज लाभ के लिये हो या उपभोग के लिये, किस सिद्धान्त पर आर्थिक संगठन हो भले ही

उनके व्यवहारिक जीवन से दूर प्रतीत होते हो परन्तु वास्तव में वे इतने दूर हैं नहीं। वस्तुतः उत्तका इन लोगो से भी घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है और रहना स्वाभाविक भी है क्योंकि आखिरकार समाज के वे भी तो एक अंग हैं और जब सम्पूर्ण समाज ही दुर्दशा को प्राप्त होता है तब उसका कोई अंग भी सुरक्षित रह सके, ऐसा सम्भव नहीं।

आधारभूत प्रश्न

परन्तु तो भी कुछ भाग्यशाली मनुष्य इन प्रश्नों को भुलाने की चेष्टा करते हैं। और सभ्य समाज के मूल भूत आधार पर ही आघात करते हैं। मनुष्य समाज में एक अधिक संख्या की ऐसी भावना रहती है कि जो कुछ भी हा, चाहें जैसी अधूरी और अन्यायपूर्ण व्यवस्था क्यों न हो उसे वैसे ही चलना चाहिये। परिवर्तनों के वे अधिक इच्छुक नहीं रहते। परन्तु उन्हें समझना चाहिये कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था भी अपरिवर्तनशील नहीं और इस समय की सामाजिक लड़ाइयों में भाग न लेकर भी हम उनसे हानेवाली हानियों से बच नहीं सकते, उनका शिकार बनना ही पड़ता है। वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन चाहनेवालों की दशा तो वैसे ही है जैसे किसी जहाज में बठा हुआ एक यात्री जहाज के टूटने पर अपने को बचाने के लिये जहाज के अन्दर के अपने कमरे को बन्द कर ले और इस प्रकार समुद्र में डूबने से अपने को बचाये, परन्तु क्या वह इस प्रकार अपने को बचा सकता है ! जब जहाज ही न रहेगा तो कमरा बन्द रखने से क्या लाभ ? इसी प्रकार जब यह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ही बदलने वाली है और दैर या सबेर अवश्य बदलेगी ही तो ऐसी व्यवस्था में रहनेवाला मनुष्य अपने को सुरक्षित कैसे समझ सकता है। उसे तो एक न एक दिन इन परिवर्तनों का सामना करना ही पड़ेगा फिर उनसे बचने और जो चुराने से लाभ ही क्या ? ऐसी स्थिति में तो इन प्रश्नों का खुल्लमखुल्ला सामना करना ही उत्तम होता है। ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर धनी और भाग्यशाली मनुष्य भी वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था पर गम्भीर विचार करने लगे हैं और उनमें से बहुतों को तो यह प्रतीत भी होने लगा है कि वर्तमान व्यवस्था में उन्हें

मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक शान्ति नहीं मिल सकती। इसके अतिरिक्त धनी लोगों में भी कुछ ऐसे हैं, और सदैव रहते ही हैं, जो अधिक समय तक अपने देशवासियों के कष्टों को शान्ति पूर्वक सहन नहीं कर सकते; फिर ऐसे कष्टों को जिन्हें वे बिल्कुल अनावश्यक समझते हैं। यहाँ तो स्थिति थोड़ी अनोखी सी है, वर्तमान व्यवस्था से तो धनी लोगों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ने लगा है।

पूँजीवाद और बाबू दल

धनी लोगों के अतिरिक्त, ऐसे मनुष्यों को भी एक अधिक संख्या होती है जिनको स्थिर आमदनी रहती है। धनी तो वे नहीं कहे जा सकते परन्तु तो भी उनकी गिनती उच्च श्रेणी के लोगों के साथ ही की जा सकती है, यह लोग भी अब यह प्रतीत करने लगे हैं कि पूँजीवाद के कटघरे के अन्दर उन के लिये भी अब कोई विशेष रचनात्मक कार्य नहीं रहा है। अपने दाप दादों की तरह न तो वे अपने लिये ही कोई विशेष भाग्य दना सकते हैं और न समाज के लिये ही कोई बड़ा लाभकारी धन्धा निकाल सकते हैं धन कमाने के अधिकतर उपाय, वर्तमान कल कारखानों के नियंत्रण को बदलने, कंपनियों को मिलाने, शेयर को धँचने व खरीदने इत्यादि में ही रह गये हैं। जुआ खेलना और धोखा देना ही अधिकतर धनी लोगों के काम और धन्य दिन प्रति दिन होते जाते हैं।

इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्रों, लाभदायक उद्योग धन्धों और साम्राज्य शाही शासनो में शक्ति अधिकतर मौखसी होती जाती है, कारखानों में डाइरेक्टर्स (directers) के बैठे और दामाद या भतीजे ही उन्नतिशाली पदवी पाते हैं, वे ही व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बनते हैं, वेड्गों की मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर्स की कुरसियों पर बैठते हैं तथा साम्राज्याशाही शासन प्रणाली में उच्च आसनों पर सुशोभित होते हैं और ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते हैं गुण और योग्यता का सम्बन्ध इस हक से दिन प्रति दिन कम होता जाता है। योग्य, मूर्खों की सेवा करते हैं, अशिक्षित मूर्ख, तथा असम्य मनुष्य आज्ञा देते हैं और

शिक्षित, योग्य और सभ्य मनुष्यों को उन्हें अन्ध विश्वास से पालन करना पड़ता है।

यह सच है कि बड़े बड़े पूँजीवादी देशों में शासन प्रणाली में अब भी बहुत से ऊँचे ऊँचे और विशेष महत्व के पद योग्य मनुष्यों को मिल सकते हैं और बहुत से ऐसे पदों पर योग्य मनुष्य हैं भी। 'योग्य' कारीगर, वैज्ञानिक, डाक्टर, लिावल सविस के लाग, शासन तथा बड़े बड़े कारपारेशनों में ऊँचे ऊँचे तथा लाभदायक पदों पर रखे गये हैं और उनमें से बहुतसे अपने स्थानों पर संतुष्ट भी हैं और यह समझते हैं कि इन पदों द्वारा वे वास्तविक जन सेवा करके देश का कल्याण कर रहे हैं, परन्तु एक एक करके ये कर्मचारी भी धीरे धीरे इस बात को महसूस करने का विवश होते हैं कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था की दरवादी, उनकी योग्यता तथा संलग्नता के कार्य, या तो उनके काम का अन्त ही कर रही है अथवा उनका घुरे कामों में प्रयोग करा रही है।

वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति

आज कल अच्छी पदवी पर रखे गये तथा अधिक वेतन वाले आविष्कारक विशेषज्ञों के कार्य की क्षति इसका एक प्रचलित उदाहरण है। एक मनुष्य वर्षों के परिश्रम के उपरान्त एक नई कल का आविष्कार करता है जिससे १००० मजदूरों के काम से पैदा होनेवाली वस्तु केवल १०० मजदूरों के काम से बन जाती है, परन्तु ऐसा वैज्ञानिक भी अपने कठिन परिश्रम, धनव्यय और प्रयत्न के फल स्वरूप क्या देखता है कि उस कल से त्सार के धन अथवा उन्नति में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई और न स्वयं वह कल ही उस में कुछ बढ़ती कर सकी, वरन् उसके ६०० भाई और सहकारी देशवासी बेकार और वरवादी के गडबे में फँके दिये गये। इंजीनियर की भी ठीक ऐसी ही दशा होती है। वह एक नई तद्दीर सोचता है जिससे उपज में वृद्धि हो सकती है अथवा उपज का व्यय कम करके धन्य से लाभ बढ़ा सकती

है, वह उसे बाजार में ले जाता है ताकि अपने इस आविष्कार के लिए अच्छा मूल्य पा सके और ऐसे ग्राहक को पावे जो वास्तव में उस का ठीक ठीक प्रयोग कर सके। परन्तु प्रायः ऐसा देखा गया है कि उस को वह तद्बीर एक बड़ा ट्रस्ट मोल ले लेता है इस कारण से नहीं कि उसका प्रयोग करके संसार को लाभ पहुँचावे वरन् इसलिए कि उस तद्बीर के प्रयोग को रोक सके और इस प्रकार वर्तमान कल और कारखानों को मशीनों को बैकार होने से बचा सके। इससे भी अधिक जँचनेवाला उदाहरण औषधियाँ बनाने वाले तथा हकीमों का है। आज कल उनका काम अधिकतर प्राण लेने तथा प्राण लेने की विद्या को पूर्ण बनाने का होता है। भ्रूणहत्या, नवजात शिशु का प्राणान्त, विवाहित जीवन में अन्तमेल दम्पति की आत्महत्या इत्यादि कामों में उन की औषधियों का अधिक प्रयोग होता है।

यही स्थिति दूसरे धन्धों की है। ऐसा सम्भव है किसी किसी धन्धे पर, किन्हीं कारणों से इन सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव कम पड़े। कुछ स्थानों पर और किसी किसी समय में कोई कोई धन्धे अब भी उन्नति पर है। उदाहरणार्थ पूँजीवादी ब्रिटेन के कारीगर बहुत दिनों बेकारी के पश्चात् सन् १९३६ ई० में फिर अधिकतर काम पर लग गये थे परन्तु उस समय काम में लगे रहने पर भी कभी कभी उन्हें यह देखकर अपने कामों से घृणा हो जाती थी कि उन का कैसा घृणित उपयोग किया जाता है। अमेरिका में भी कारीगरों को पहले कुछ समय तक तो संतोष रहा जिस समय उन्होंने देश के लिये बड़ी बड़ी गगनचुम्बी अट्टालिकायें बना बनाकर देश की एक बड़ी समस्या को सुलझाया परन्तु वास्तव में मकान तो रहने अथवा काम करने के लिये ही बनाये जाने हैं और यदि इस प्रकार बने हुए मकान खाली पड़े रहे और उनमें कोई रहे हो नहीं, तब तो उनके बनाने वाले अवश्य निराश तथा हताहत होंगे। पिछले वर्षों का उतका ऐसा ही अनुभव है कि निर्धनता के कारण मनुष्य खुले मैदानों और पैड़ों के नीचे तथा आम सड़कों और रास्तों पर सोते हैं और कारीगरों के बनाये हुए मकान खाली पड़े रहते हैं। इन बातों का उन पर भी काफ़ी प्रभाव

पड़ता है और वे भी इसी परिणाम पर पहुँची हैं कि हो न हो इस आर्थिक व्यवस्था में ही कुछ बुराई है और इसके परिवर्तन किये बिना जिस लाभ को वे कामना करने हैं उसे वे प्राप्त नहीं कर सकती।

शिक्षकों की स्थिति

बुद्धि तथा मस्तिष्क से काम करनेवाले मनुष्यों में अध्यापकों को एक बड़ी संख्या है। अपनी भक्ति और उत्साह के कारण वे अपने काम को, सामाजिक महत्व का समझते हैं और बहूतों का तो ऐसा विचार है कि वे इस प्रकार शिक्षा देकर समाज को भलाई करने हैं तथा उसे आगे बढ़ाने में सहायक हैं और इन्हीं विचारों से वे अपने काम से संतुष्ट भी रहते हैं। किन्हीं मानों में उनका ऐसा विचार सही भी है। किसी भी देश की उन्नति के लिए शिक्षा और शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है। परन्तु सन् १९३६ ई० में ब्रिटैन में होनेवाली कान्फरेन्सों में लगभग प्रत्येक अध्यापक ने बार बार इस बात की सूचना दी कि उनके शिष्यों को इतना कम भोजन मिलता है कि वे अधिक पढ़ ही नहीं सकते। अमेरिका ऐसे उन्नतिशाली पूँजीवादी देश में बड़े बड़े शहरों में भी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही भूखे रहते हैं। उन्हें आवश्यकतानुसार भोजन ही नहीं मिल पाता है, पौष्टिक पदार्थों का तो कहना ही क्या? अमेरिका के शिकागो (Chicago) ऐसे बड़े शहर में भी अध्यापकों को महीनों तक वेतन ही नहीं मिल पाता। इस प्रकार अध्यापकों को भी यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आर्थिक संगठन इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें बच्चों के मस्तिष्क भूख से निर्बल और शक्तिहीन न रहे, तभी वास्तविक शिक्षा भी दी जा सकती है। सबसे पहले सीखने और सिखाने की वस्तु भी यही है।

अन्य धन्ये

एक दो धन्यों में भले ही योग्य और अनुभवी मनुष्य थोड़ी पूँजी से स्वतंत्र रहकर अपने जीवन का निर्वाह कर सके परन्तु अधिकतर धन्यों में स्वतंत्रता का प्रायः ह्रास हो गया है और उनके

स्थान पर संघ (trusts) इत्यादि बन गये हैं जिससे व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करना दुर्लभ नहीं तो कठिन अवश्य है। ऐसा है कि बड़े बड़े बैंकों, कल कारखानों, समाचारपत्रों तथा पुस्तक प्रकाशन इत्यादि धन्धों में इस समय भी नवयुवकों को अच्छे अच्छे पद मिल जाते हैं, परन्तु यह पद प्रथम तो नीची श्रेणी के होते हैं दूसरे इन पदों के द्वारा वास्तविक उन्नति नहीं की जा सकती, क्योंकि इन कल कारखानों का स्वामित्व तथा आधिपत्य धनी कुटुम्बों में मौखसी हक के रूप में ही है और अच्छे वेतनवाले नौकर भी इन कल कारखानों के बड़े बड़े तथा सैद्धान्तिक विषयों में मालिकों से प्रश्न तक नहीं कर सकने, उनमें परिवर्तन कराना तो दूर की बात है। यदि यह मालिक पूर्णरूप से पूँजीवादी अथवा समाजविरोधी हैं तब तो अच्छे वेतन पानेवाले नौकर भी उतने ही विवश रहेंगे जितना कि निम्न श्रेणी का एक साधारण मजदूर। विम्वकारी संशोधनों तथा परिवर्तनों के लिये तो एक प्रकार की बड़ी मजबूत दीवार सी ही खड़ी रहती है।

शासन के उच्च अधिकारी तथा आफिसरों का भी एक बड़ा दल है जो अच्छा वेतन पाते हैं। इन आफिसरों का प्रायः यह विचार होता है कि सम्भवतः वे समाज की सच्ची सेवा कर रहे हैं। बैकारी, रोग तथा अन्य इसी प्रकार की बीमा इत्यादि की योजना रखनेवाले तथा उन्हें कार्यान्वित करने वाले भी यह समझने लगते हैं कि उन्होंने अनेकों जिलों तथा असंख्यों बैकारों और रोगियों की बरबादी से रक्षा की; परन्तु अन्त में उन्हें भी मानना ही पड़ता है कि इस आर्थिक संगठन के ही कारण यह सारी बैकारी और रुग्णावस्था है जिसे दूर करने के लिये उन्होंने इतने प्रयत्न किये हैं, और दिन प्रति दिन करते हैं तथा इस बैकारी और रुग्णावस्था को दूर करने के लिये ही यह आवश्यक है कि इस प्रकार का संगठन ही बदला जावे और उसके स्थान में ऐसा संगठन कायम हो जो इन बुराइयों का अन्त ही कर दे।

साम्राज्यशाही शासनप्रणाली के चलाने वाले बड़े हाकिम तथा

शासक, बड़े परिश्रम से देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने की चेष्टा करते हैं और किसी हद तक करते भी हैं और यह समझते हैं कि सम्भवतः इससे वे देश की एक बड़ी सेवा कर रहे हैं। बहुत से भारतीय सिवल सर्विस के सदस्य अपने इस प्रकार के कार्यों से काफ़ी सन्तुष्ट रहते हैं और अपने जीवन को सफल मानते हैं। परन्तु क्या वे इस समय तक यह समझ नहीं सके हैं उनके इन सब कामों का परिणाम भारतीय जनता के लिये, लगातार रक्तशोषण और रहन सहन में निरन्तर कमी ही हुई है? शान्ति स्थापित करने की चेष्टा में वे उन भावों को ही कुचलने पर उतारू होजाते हैं जिनके जीवन और प्रोत्साहन से ही देश का वास्तविक कल्याण हो सकता है। दूसरे शब्दों में उनकी शान्तिस्थापना की चेष्टा का परिणाम भारत का आर्थिक शोषण उसके उद्योग धन्धों का हास तथा नाश, उसकी स्वतंत्रता का अपहरण और खुले शब्दों में परतंत्रता की बेड़ियों में अधिक पुष्टता के साथ जकड़ जाना ही हुआ है। वे भी अब यह समझने लगे हैं कि इस प्रकार शान्ति स्थापना से वास्तविक शान्ति नहीं हो सकती। जिस समय तक एक देश अथवा जाति दूसरे देश अथवा जाति पर अपना प्रभुत्व कायम किये हुए रहता है और उसे लगातार रखना चाहता है, कभी भी वास्तविक शान्ति नहीं हो सकती। शान्ति स्थापन के लिये सर्वप्रथम आवश्यकता है स्वतंत्रता की; न केवल राजनीतिक, बरन आर्थिक और सामाजिक भी। प्रत्येक देश को अपनी आवश्यकतानुसार और परिस्थितियों के अनुकूल अपने उद्योग धन्धों के जीवन तथा उन्नति करने का अधिकार हो। इन बातों के बिना शान्ति की पुकार केवल ढोंग ही है।

वास्तव में पूँजीवादी व्यवस्था में प्रायः सभी मस्तिष्क से काम करने वालों के कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। समाज की सीमाएँ संकीर्ण होती हैं, रचनात्मक कार्यों के लिए अवकाश कम मिलते हैं और समाज में बरबादी के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। वर्तमान समाज में भी इस प्रकार के चिह्न दिखायी देने लगे हैं। जिन लोगों ने इनको देख पाया है उनसे हमारा केवल यही कहना है कि वे उस समय तक शान्ति

से न बैठें जब तक कि इस नाश के कारणों को जानकर उनके उपायों का प्रयोग करके उन्हें दूर न कर दें।

जो लोग अपने काम को इस आर्थिक संगठन में अब भी लाभदायक और समाज के लिए कल्याणकारी समझते हैं उनके लिए हमारी यही चेतावनी है कि एक न एक दिन उन्हें भी अपने काम में सामाजिक विनाश के चिह्न दिखायी पड़ेंगे और वह दिन अब दूर नहीं है। भले ही वे अभी हमारी बात न मानें, परन्तु स्वयं उनका ही अनुभव उन्हें यह स्वीकार करने का विवश करेगा।

इन सबसे भी अधिक और विशेष डरावनी बात तो युद्ध की निरन्तर आशंका है जो पूँजीवाद का स्वाभाविक आवश्यक परिणाम है। युद्ध छिड़ जाने से सब रचनात्मक कार्य स्वयं ही रुक जाते हैं। उपज के साधनों का युद्ध सम्बन्धी सामग्रियाँ बनाने में अधिकतर व्यय होता है और उन्हीं के द्वारा, बड़े बड़े शहर, थोड़े ही समय में इस प्रकार नष्ट कर दिये जाते हैं कि बहुतों को तो पहचान भी नहीं रह जाती। आखिरकार शहरों की सजावट, मकान इत्यादि, सब व्यर्थ ही तो होंगे यदि उन्हें एक दिन बम, तोपों तथा अन्य विषैली गैसों से गिरना और नाश होना ही है। इस प्रकार के संगठन और ऐसी व्यवस्था से प्रयोजन ही क्या? क्यों न इसके स्थान में ऐसे संगठन की व्यवस्था की जावे जो पूँजीवाद के पजे से छुटाकर समाज को रचनात्मक कार्य करने, और सम्पूर्ण समाज के रहन सहन में वृद्धि तथा उन्नति करने में समर्थ हों।

दूसरे शब्दों में पूँजीवादी संगठन के स्थान में समाजवादी संगठन ही क्यों न स्थापित किया जावे।



समाजवाद क्या है ?

वर्तमान समय में समाजवाद अथवा साम्यवाद की बहुत चर्चा है। न केवल भारतवर्ष में ही, वरन् सारे संसार में इसीकी पुकार है। भिन्न-भिन्न देशों में इसी आशय के राजनैतिक दल बन रहे हैं, और उनका निरन्तर यही प्रयत्न रहता है कि पूँजीवादी संगठन का अन्त करके उसके स्थान में समाजवादी अथवा साम्यवादी ऐसा कोई संगठन स्थापित हो। प्रख्यात पूँजीवादी देश (इंग्लैण्ड, अमेरिका) इत्यादि में भी इस प्रकार के आन्दोलन हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। वास्तव में संसार में समाजवाद की एक लहर-सी चल रही है, और लगभग सभी देशों में कुछ-न-कुछ इस ओर काम हो रहा है वरन् दिन-प्रति-दिन उसकी उन्नति ही होती जाती है।

प्रारम्भ में साम्यवाद अथवा समाजवाद केवल एक सिद्धान्त-प्राय ही था। उसका स्पष्ट रूप जानना असम्भवसां प्रतीत होता था। उस समय वह केवल वर्तमान प्रणाली के दोषों को बतानेवाला तथा भविष्य में होनेवाले अथवा इच्छित सुधारों का द्योतक था। उन दिनों प्रचलित पूँजीवाद की बुराइयाँ ही बताई जाती थीं, और उन्हीं के आधारपर भविष्य के लिए सुधार बताकर नये आर्थिक संगठन की चर्चा मात्र की जाती थी।

परन्तु इस समय संसार के पंचमांश में साम्यवादी शासन स्थापित है, और व्यावहारिक रूप में चल रहा है। इसी कारण साम्यवाद अथवा समाजवाद आज अधिक निश्चिन्, स्पष्ट तथा व्यावहारिक रूप में समझा जा सकता है। साम्यवाद की प्रगति, उसकी उन्नति आज

प्रत्यक्ष है। गन वर्षों में प्रायः यह कहा जाता था कि साम्यवाद तो एक असम्भव-सी वस्तु है और शायद इस प्रकार का शासन कभी सफल शासन हो ही नहीं सकेगा। बहुत से लोग इस प्रकार के संगठन का होना एक स्वर्गीय स्वप्न समझने थे, और ऐसे विचारों का उनके लिए कोई महत्व ही न था। जब कभी भी कोई लेखक समाजवादी संगठन की चर्चा करता, वे उसे आदर्शवादी, दूरदशितापूर्ण संगठन का स्वप्न देखनेवाला आदि नाम देकर हँसा करते थे; परन्तु इस समय तो 'प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्' की लोकोक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती है। अब तो प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रही। आज तो संसार इस बात को भली भाँति जानता है कि साम्यवादी व्यवस्था हो सकती है। यही नहीं उसने तो स्वयं अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था चलते देख ली है।

परन्तु ऐसा होते हुए भी, आज भी संसार के $\frac{1}{3}$ भाग में पूँजीवादी संगठन ही प्रचलित है। एक पर्याप्त संख्या में लोग अब भी इस भ्रम में हैं कि साम्यवाद ऐसी कोई वस्तु संसार-भर में स्थापित हो सकती है! उनका अब भी ऐसा खयाल है कि भले ही एक देश में ऐसी व्यवस्था चल गई हो; परन्तु सब देशों में ऐसा हो सके, अथवा सम्पूर्ण संसार में समाजवादी संगठन हो, यह सम्भव नहीं। भिन्न-भिन्न देशों को भिन्न भिन्न स्थिति और वातावरण का इस सम्बन्ध में वे प्रायः उल्लेख किया करते हैं, और इस तरह की बातों से समाज को समाजवादी संगठन के सम्बन्ध में भ्रमित कर देते हैं, इसी लिए संसार के एक बड़े भाग में प्रत्यक्ष समाजवादी अथवा साम्यवादी शासन रहने हुए भी इस बात की विशेष आवश्यकता है कि समाजवाद या साम्यवाद के उद्देश्य, उसके सिद्धान्त और कार्यक्रम को फिर से दोहराया जाय।

प्राचीन इतिहास

संसार के भिन्न-भिन्न भागों में मजदूर तथा शोषित वर्ग के आधार पर वर्षों आन्दोलन चले हैं। प्रायः इन सभी आन्दोलनों का उद्देश्य पूँजीवाद का अन्त करके समाजवाद स्थापित करना रहा है, इन आन्दोलनों में साम्यवादी साहित्य और अनुभव की कभी कभी नहीं

रही, परन्तु तो भी गत शताब्दी की कुछ ऐसी बातों के कारण इस प्रकार की भावना पैदा नहीं की जा सकी कि संसार के दुःखों को दूर करने का एकमात्र उपाय समाजवाद अथवा साम्यवाद ही है।

सब से आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ पुराने शक्तिशाली समाजवादी आन्दोलन आज भी भ्रम में पड़े हुए हैं। वे सही रास्ते को भूल गये हैं, और इस प्रकार जनता को समाजवादी परिवर्तनों की आवश्यकता समझाने में असमर्थ हैं। क्या कारण है कि वे इस प्रकार भ्रम में पड़ गये, इसे विस्तार पूर्वक यहाँ बताना सम्भव नहीं, परन्तु तो भी किन्हीं देशों के सम्बन्ध में इन कारणों पर थोड़ा प्रकाश डाला जा सकता है। पूँजीवादी देशों में इंग्लैंड और अमेरिका विशेष तया प्रमुख हैं, और वास्तव में इन्हीं देशों के आन्दोलनों के सिंहावलोकन से इस प्रश्न पर अधिक प्रकाश पड़ सकता है।

ब्रिटेन के सम्बन्ध में इन कारणों का समझना अधिक कठिन नहीं है। ब्रिटेन के मजदूर और समाजवादी आन्दोलनों को पहिले १५ वर्षों में कई बार हार सहनी पड़ी है। वे समाजवादी उद्देशों तथा उसे प्राप्त करने के उपायों और साधनों को पूरी तरह से समझ नहीं सके थे। अपने उद्देशों को प्राप्त करने के लिए ठीक रास्ते पर न चल कर उन्होंने ऐसा मार्ग निर्धारित किया, जो उन्हें समाजवाद को ओर ले जाने वाला न था। इसी कारण उन्हें थोड़े समय के लिए हार खानी पड़ी। हार का असर बहुत दिनों तक नहीं रहा, परन्तु तो भी उसने आन्दोलनों को कुछ वर्षों के लिए पीछे अवश्य धकेल दिया। पूँजीवाद के विरुद्ध मजदूर आन्दोलन की पहली लहर सन् १८४८ में चारटिस्ट आन्दोलन में दिखाई दी थी, और उसके पश्चात् आन्दोलन लगभग ५० वर्ष पीछे हट गया। सन् १९३१ एवं १९३६ में फिर मजदूर-आन्दोलन को हार सहनी पड़ी। इससे भी संगठन को कुछ धक्का पहुँचा। परन्तु इन पराजयों से भी आन्दोलन बिल्कुल समाप्त नहीं हो गया और न हो ही सकता है। ब्रिटिश पूँजीवाद के विरुद्ध मजदूर-आन्दोलनका विरोध अब भी है और दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जाता है।

गत पांच वर्षों में ब्रिटैन में पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों में मजदूर आन्दोलन का स्पष्टीकरण एवं मजदूरों में उच्च श्रेणी की जाग्रति पैदा करने के लिए क्राफ़ी साहित्य निकला है। यह साहित्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ब्रिटैन में गत १५ वर्षों का कार्य व्यर्थ नहीं रहा। नवीन जाग्रति से ब्रिटिश मजदूर भी अब यह समझने लगे हैं कि उनका उद्धार समाजवाद ही में है।

परन्तु आज भी ब्रिटैन में इस बात को विशेष आवश्यकता है कि आन्दोलन के नेता और मजदूर-दल का प्रत्येक कार्यशील सदस्य आन्दोलन के उद्देश्य, कार्यक्रम तथा उसके साधनों को भली भाँति समझ ले। वास्तव में आन्दोलन की सफलता इसी पर निर्भर है। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि वर्तमान राजनैतिक लड़ाइयों में नये सिद्धान्तों और उपायों के प्रयोग भी आवश्यक हैं। यह केवल इसीलिये नहीं कि पुराने उपाय अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं, वरन् इसलिए भी कि मजदूर-आन्दोलन की लहर ऐसी परिस्थितियों में बढ़ रही है, जो पुराने आन्दोलनों से अधिक गम्भीर तथा विप्लवकारी है।

अमेरिका में मजदूर-आन्दोलन

अमेरिका की स्थिति इससे भिन्न है। वहाँ पूँजीवाद का अन्त और समाजवाद की स्थापना करनेवाले मजदूर-आन्दोलन का जन्म देनेवाली आर्थिक और सामाजिक शक्तियाँ सन् १९२६ के आर्थिक संकट (crisis) से हो प्रौढ़ हो सकी हैं। मजदूर-आन्दोलन की नींव पड़ चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका में भी शीघ्र ही एक शक्तिशाली मजदूर-आन्दोलन हो जायगा, जो पूँजीवाद का विरोध करके समाजवादी संगठन को पुष्ट करेगा। किसी आन्दोलन की सफलता अथवा असफलता उसके गुण और स्वभाव पर निर्भर रहती है, इसीलिए यह आवश्यक है कि ब्रिटैन से अधिक अमेरिका में समाजवादी सिद्धान्त, उसकी व्याख्या परिभाषा तथा उसे स्थापित करने के उपाय और साधनों का स्पष्टतया प्रचार हो, ताकि आन्दोलन ठीक मार्ग पर चलकर

अपने उद्देश्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सके ।

भारत की स्थिति

जब ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे स्वतन्त्र, सभ्य और शिक्षित देशों के लिए यह आवश्यक है कि समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धान्त की व्याख्या और परिभाषा की जाय, उसे स्थापित करने के उपाय और साधनों को समझाया जाय और उसके उद्देश्यों का भली भाँति प्रचार हो, तो भारतवर्ष का तो कहना ही क्या है । यहाँ तो इस प्रकार का कार्य अनिवार्य ही है ।

देश परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ा है । लगभग ६० प्रतिशत देशवासी अशिक्षित हैं । राष्ट्रीय आन्दोलन, भलीभाँति विस्तृत नहीं है । ऐसी दशामें देश के शोषित वर्गों का संगठन, उनके आन्दोलन को प्रोत्साहन, देश के कल्याण के लिए एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु हो जाती है । वास्तव में राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता भी बहुत कुछ इस संगठन पर ही निर्भर है ।

प्रायः यह कहा जाता है कि परतन्त्र देशों में समाजवाद इत्यादि वर्ग-संघर्ष की बात न उठाकर संयुक्त साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन पर ही देश की सम्पूर्ण शक्तियों का प्रयोग होना चाहिए । कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहने लगे हैं कि इस प्रकार का वर्ग-संगठन राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए घातक सिद्ध होगा । वे इस प्रकार के संगठन के स्थान पर सहयोग तथा सद्भावना की नीति बरतने का आदेश देने हैं ; परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है । समाज में वर्ग तो उपस्थित ही हैं, और उनमें परस्पर संघर्ष ही है । असंगठित होने के कारण शोषित-वर्ग धन तथा प्रभुत्व के बल से दबा दिया गया है । तथा उनके दिन-प्रति-दिन के आर्थिक संकटों से निरन्तर लाभ उठाया गया है । पूँजीपति तथा इस प्रकार के अन्य लोग वास्तव में यह संगठन इसी कारण रोकना चाहते हैं कि संगठित हो जाने पर वे इन अशिक्षित और निर्धन

मजदूरों तथा अन्य शोषित-वर्गों का शोषण न कर सकेंगे। साफ़-साफ़ तो वे ऐसा कह नहीं पाए और न इस प्रकार कहना उन्हें लाभदायक ही हो सकता है। बस, सिद्धान्त सझावना इत्यादिक शुभ शब्दों का बहाना लेकर इस प्रकार बैचारे अज्ञान अशिक्षित मजदूरों और किसानों को भूम में डालना चाहते हैं। साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए इन शक्तियों का संगठन ही विशेष आवश्यक है। वास्तव में देश के लिए लड़नेवाला यही वर्ग है। थोड़े से पूँजी-पति और मध्य-श्रेणी के लोग न अधिक लड़ ही सकते हैं और न उनकी संख्या ही पर्याप्त है। मजदूर किसान तथा अन्य शोषित-वर्गों में जन-संख्या अधिक है। लड़नेवाली वेही वास्तविक शक्तियाँ हैं। उनके संगठित हो जाने से ही परतन्त्र देश अपनी स्वतन्त्रता के युद्धों में विशेष वेग के साथ अग्रसर होसकता है। स्वाधीन देशोंमें भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने में इन्हीं वर्गों का मुख्यतया हाथ रहा है। इनका संगठन तो आवश्यक है ही साथ ही आन्दोलन के प्रमुख तथा कार्यशील सदस्यों को उसके सिद्धान्त, उद्देश्य उसे प्राप्त करने के उपाय तथा साधन भलीभाँति समझ लेना चाहिए। जब तक वे मजदूर आन्दोलन के उद्देश्य तथा उससे होनेवाले परिणामों को भली प्रकार समझ नहीं लेते, न तो आन्दोलन ही ठीक प्रकार से चल सकता है और न सफलता ही मिल सकती है।

इसी कारण सर्वप्रथम साम्यवाद तथा समाजवाद शब्दों की परिभाषा करना आवश्यक है किन्-किन अर्थों में इनका प्रयोग होता है और संगठन को मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं। बहुत से लोग इन बातों से परिचित नहीं। गत शताब्दी में इन शब्दों का बड़ी लापरवाही से प्रयोग हुआ है। मार्क्स (Marx) और एनजिल्स (Engels) ऐसे लेखकों तक ने इनके प्रयोग में असर्तकता से काम लिया है। सन् १९१७ तक स्वयं लेनिन (Lenin) भी अपने को समाजवादी अथवा सोशल डिमाक्रेट (Social Democrat) ही कहता रहा है। सन् १९१७ के अप्रैल मास में ही प्रथम बार उसने अपने दल का नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया था। इसके पूर्व दल के नाम इत्यादि की ओर उसका विशेष ध्यान नहीं गया था। इस समय पहली बार

उसने दल की बैठक में कहा—“हमको अब अपने दल के नाम पर भी विचार करना चाहिए। हम अब अपने को साम्यवादी कहे, जिस प्रकार मार्क्स और इन्जिल्स अपने को साम्यवादी कहते हैं। मनुष्य-समाज पूँजीवाद से सीधे समाजवाद में जा सकता है। पूँजीवाद का अन्त करके तुरन्त ही उसके स्थान में समाजवाद स्थापित हो सकता है। इन दोनों के बीच किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं।

समाजवाद

समाजवादी व्यवस्था का अर्थ ऐसे आर्थिक संगठन में है, जिसमें उपज के साधनों पर समाज का अधिपत्य हो और प्रत्येक मनुष्य को अपने-अपने काम के अनुसार उपज बाँटी जाय। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के संगठन में देश की उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग एक केन्द्रीय योजना-समिति द्वारा निश्चित होता है। उपज के आवश्यक आँकड़े लेकर वस्तु की माँग, उसकी उपयोगिता तथा देश की उन्नति का विचार रखकर वे ही निश्चित कर देते हैं कि कौन-कौन से पदार्थ किन-किन संख्याओं में बनाये जायँ, किसी व्यक्ति विशेष अथवा एक दल-समुदाय को उपज निश्चित करने का अधिकार नहीं रहता। वास्तव में ऐसे संगठन में पूँजी अथवा उपज के साधन व्यक्ति विशेष के हाथों में रहते ही नहीं। प्रायः उन सब पर ही शासन का अधिपत्य रहता है, और उन्हीं के द्वारा उनका प्रयोग भी निश्चित होता है।

समाजवाद और साम्यवाद में अन्तर बताने हुए लेनिन का यह भी कहना था कि उनका दल समाजवाद से भी आगे जाने को है। समाजवाद एक-न-एक दिन वर्गवाद में अवश्य परिणत हो जायगा और उसका उद्देश्य होगा—प्रत्येक मनुष्य से उसकी शक्ति के अनुसार काम लेना और प्रत्येक मनुष्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार उपज का भाग देना।

समाजवाद और साम्यवाद की परिभाषा तथा इनमें परस्पर अन्तर विस्तार पूर्वक तो अगले परिच्छेद में दिया जावेगा। यहाँ पर तो

इतना हो कहना है कि समाजवादी और साम्यवादी दोनों ही पूँजीवाद का अन्त करके समाजवाद ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, भले ही उनके उद्देश्यों और उपायों में थोड़ी बहुत भिन्नता हो। उद्देश्य के प्राप्त करने के साधनों में भी उनमें मतभेद रह सकता है। और प्रत्येक आन्दोलन में थोड़ा-बहुत मतभेद रहता भी है। समाजवादी आन्दोलन में तो विशेष करके नीति तथा संगठन के विषय पर काफ़ी मतभेद है। किन्तु उपायों से तथा किस प्रकार के संगठन से पूँजीवाद के स्थान में समाजवाद स्थापित हो सकता है, यह भी विचारणीय विषय है। परन्तु यह बात तो निश्चित ही है कि किसी भी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके कार्यशील सदस्य उसके उद्देश्य, साधन तथा उपायों को ठीक तरह से समझ लें। ऐसा न होने से कोई भी आन्दोलन कदापि सफल नहीं हो सकता।



समाजवाद और साम्यवाद

प्रगतिशील आर्थिक संगठनों में दो संगठन प्रमुख हैं समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद से अभिप्राय उस संगठन से है जिसमें उपज एक निश्चित योजना के आधार पर होती है और उसका बँटवारा मनुष्यों में उनके काम और उसके गुण के अनुपात से रहता है साम्यवादी संगठन में अन्तर केवल इतना है कि उसमें उपज एक निश्चित योजना के अनुसार तो अवश्य होती है परन्तु बँटवारा, काम के गुण और संख्या के आधार पर न होकर मनुष्यों की आवश्यकता के आधार पर होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपनी योग्यता भर काम करना पड़ता है।

समान वेतन

इस प्रकार समाजवाद में श्रेणी और वर्ग का हो अन्त हो जाता है परन्तु आय में समानता नहीं हो पाती। भिन्न २ मजदूरों की आय उनके काम और गुण के अनुसार भिन्न रहती हैं। मनुष्यों के रहन सहन व आय में भिन्नता का कारण भी यही है। कोई एक निश्चित वेतन नहीं जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य दे दिया जावे। सम्भवतः ऐसा हो नहीं सकता है। समान वेतन की रकम निश्चित करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना भी पड़ेगा। दूसरे यदि भिन्न २ प्रकार के मजदूरों को समान वेतन देने की योजना की जावे, तो न्याय नीति का

खण्डन ही करना होगा । यदि शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के मजदूरों का समान वेतन मिले अथवा तीन चार वर्ष कारोगरी की शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त भी मजदूर को वही वेतन मिले जो एक भगी को मिलता है जितका काम केवल भाड़ लगाना है तब तो अच्छे तथा महत्वपूर्ण काम करने की स्वाभाविक इच्छा का ही अन्त हो जावेगा । वर्तमान समय तथा परिस्थिति में तो विशेषकर यह बात ठीक जँचती है । मनुष्यों की उपजाऊ शक्तियाँ इस समय बढ़ अवश्य गई हैं परन्तु तो भी वे इतनी नहीं बढ़ सकी हैं कि इसी समय से भिन्न २ काम करने वालों को, उनके काम की संख्या व गुण के अनुसार वेतन व पुरस्कार देना ही दन्द कर दिया जावे और उस के स्थान में सब का एक ही निश्चित वेतन दिया जा सके । वर्तमान परिस्थिति में ऐसा करना माना वास्तविक परिस्थिति को दिल्कुल भुलाना अथवा स्वयं अपने का धाँख में डालना ही होगा । समान वेतन की नीति से तो निस्संदेह उपज की भावी उन्नतिही रुक जावेगी वरन सम्भव है कि उसमें कमी भी आवे । प्रस्तुत वातावरण में स्त्री व पुरुष अच्छा और अधिक परिश्रम का काम उस समय तक सम्भदनः नहीं करेंगे जब तक उन्हें यह आश्वासन न हो जावे कि अधिक अच्छे व परिश्रम वाले काम के लिये उन्हें विशेष पुरस्कार मिलेगा । भले ही थोड़े समय के लिये वह इस प्रकार काम करने को तत्पर भी हो जावे परन्तु सदैव के लिये सम्भवतः यह सम्भव नहीं ।

परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे लोग उस समय तक काम ही नहीं करेंगे जब तक उन्हें व्यक्तिगत धन एकत्रित करने का अधिकार न हो अथवा वे स्वयं उपज के साधनों को मोल न ले सकें, अथवा पूर्जापति भी धन सकें वेतनों में असमानता और व्यक्तिगत धनोपार्जन का अधिकार तथा एकत्रित धन से पूर्जापति धन सकना यह दिल्कुल भिन्न २ बातें हैं, और एक को दूसरे से मिलाना ठीक नहीं और न इसमें कोई भ्रम ही रहना चाहिये ।

समान वेतन के सिद्धान्त को अस्वीकार करने का एक कारण और भी है समाजवादी यह भली भाँति जानते हैं कि इस सिद्धान्त को इस समय लागू करना अथवा उसके लिए चेष्टा करने का अर्थ उपज के साधनों और उसी के अनुसार मनुष्य समाज की ऐतिहासिक विचार धारा को जान वृमककर भुलाना अथवा उसे न समझना होगा। दूसरे इस प्रकार की चेष्टा असम्भव सी भी होगी। समान वेतन के सिद्धान्त को अस्वीकार करने का एक कारण और भी है। वेतनों में समानता असम्भव ही नहीं वरन् अवांछनीय भी है। केवल यही नहीं कि इस समय ही इसे लागू नहीं किया जा सकता वरन् अन्तिम ध्येय भी हमारा यह नहीं है और न हो ही सकता है। अन्तिम से हमारा अभिप्राय यह नहीं कि संसार में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक हम इस समय विचार कर सकते हैं भले ही भावष्य में कोई परिस्थिति हो जावे और उसमें ऐसा सम्भव हो क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और उसमें दिन प्रति दिन नए नए अन्वेषण तथा उन्नति के मार्ग निकलते आते हैं।

समान दशा

प्रत्येक मनुष्य की विलकुल समान आर्थिक स्थिति जिसमें किसी की भी किसी से तानिक भी अधिक अच्छी दशा न हो, यह सम्भव ही नहीं है। यदि प्रत्येक मनुष्य को समान वेतन भी दिया जावे तब भी सब की आर्थिक स्थिति समान ही रहेगी यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि साधारणतया अधिकतर मनुष्य कुटुम्बों में रहते हैं। कुटुम्ब की आय का उनके रहन सहन और स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कुटुम्ब की आय का पता केवल मजदूर की मजदूरी की दर से ही नहीं चल सकता वरन् कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या से भी इसका सम्बन्ध है। सब मजदूरों को समान वेतन मिलने पर भी व्यक्तियों की संख्या में भिन्नता के कारण मनुष्यों के रहन सहन में काफी अन्तर पड़ जाता है फिर एक कुटुम्ब में कितने सदस्य आय लाने वाले हैं और कितने नहीं

इसका भी विचार करना आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए चार व्यक्तियों वाले एक कुटुम्ब को रहन सहन जिस में तीन व्यक्ति आय लाते हों उस कुटुम्ब को अपैक्षा कही अच्छी होगी जिसमें केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे वेतन मिलता हो और बाकी तीन सदस्य कुछ आय ही न लाते हों। स्वाभाविक है कि इस सदस्य को अपनी रहन सहन में कमो करनी पड़ेगी ताकि तीनों अन्य व्यक्ति भी एक से ही रह सकें। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार भी समान आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती। और भी लीजिये यदि यह भी प्रबन्ध हो कि एक कुटुम्ब के सब सदस्यों को समान वेतन दिया जाये चाहे वे आय लाने के योग्य हों अथवा न हो तौ भी सब की आर्थिक दशा एक सी नहीं रखी जा सकती। प्रथम तो ऐसा सम्भव होना ही कठिन है और यदि ऐसा प्रबन्ध हो भी, तो भी शारीरिक व मानसिक शक्तियों के भिन्न २ रहने से, प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं भिन्न २ रहती हैं। उसी के अनुसार उसके खर्च रहते हैं। एक रोगी मनुष्य खुली हवा में रहना चाहेगा। वाल - वच्चे वाले आदमी को बड़े घर की आवश्यकता होगी इत्यादि इत्यादि। आवश्यकताओं के भिन्न २ होने से उनके रहन सहन में भिन्नता स्वाभाविक है और इसी कारण प्रत्येक कुटुम्ब अथवा प्रत्येक मनुष्य को समान वेतन देने पर भी सब की आर्थिक स्थिति समान नहीं रखी जा सकती। इसके विपरीत ऐसे विचारों से हानि ही पहुँच सकती है क्योंकि इसके कारण एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य होने में बाधा पड़ेगी। इन्हीं सब बातों को सोचकर पूर्वकाल में मार्क्स और एन्जिल ने सैद्धान्तिक रूप से तथा लेनिन व स्टैलिन ने व्यावहारिक रूप में समानवेतन के सिद्धान्त को अस्वीकार करके प्रत्येक मनुष्य को अपने २ काम की संख्या और गुण के आधार पर वेतन और पुरस्कार देने की ही नीति चरती।

समाजवाद

उपज के साधनों की उन्नति तथा मनुष्य स्वभाव के विचार ने, वर्तमान समय में वैद्वारे का समाजवादी ढंग ही उपयुक्त और आवश्यक

है। पूँजीवादी संगठन में, वर्षों तक रहने से मनुष्यों के स्वभाव भी कुछ वैसे ही ढाँचे में ढल से गये हैं। और इसी कारण उनमें एक बारगी पूरा-पूरा परिवर्तन कराया नहीं जा सकता। काम के लिये वेतन की व्यवस्था पूँजीवाद में है। प्रत्येक मनुष्य लगभग उसका आदमी भी है। वेतन के रिवाज को विल्कुल ही हटा देने से उपज की उन्नति में गड़बड़ी पड़ जावे, ऐसा भय होता है। सम्भवतः उतनी संख्या में उतना अच्छा काम न भी हो सके। इसीलिये, वेतन देने की नीति, पूँजीवादी ढंग की होती हुए भी, उसे रखना ही पड़ेगा। परन्तु इससे यह अभिप्राय नहीं कि यह नीति विल्कुल पूर्ण है और इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं वास्तव में इसमें कई रूकावटें हैं जिन्हें अवश्य ही दूर करना पड़ेगा। परन्तु एक बात यह है कि उपज के साधनों के स्वामित्व के लिये दिये जाने वाले भाग के घातक और घोर अन्याय का अन्त तो इसमें हो ही जाता है। परन्तु काफ़ी असमानता तो भी रह जाती है जो केवल योग्यता के आधार पर नहीं है। फिर असमानता भी इतनी है कि उसे भुलाया भी नहीं जा सकता वरन् इसका मिलान निर्धनों की शिक्षा की सहायता, समान अवसर प्रदान करने की नीति, इत्यादिक उपायों में करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त वेतन की नीति वाले संगठन में अच्छे वेतनवाले स्थानों और पदवियों के लिए परस्पर मजदूरों में प्रतिद्वन्दता भी उत्पन्न हो जाती है, वर्गों की प्रतिद्वन्दता बन्द होकर वैयक्तिक प्रतिद्वन्दता बढ़ने लगती है। माने में यह कितनी लाभदायक भी है क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अच्छा काम कर सकने की चेष्टा करता है परन्तु फिर भी प्रतिद्वन्दता रोकने के लिए नियन्त्रण रखना ही पड़ेगा और बात के लिए न सही, केवल इसी बातके लिए कि इसे सोभाव्य ही रक्खा जा सके। नियन्त्रण रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का दबाव रखना स्वाभाविक ही है क्योंकि दबाव के बिना नियन्त्रण रह ही नहीं सकता। स्वेच्छा पर काम छोड़ देने से तो नियन्त्रण न रहेगा और इसी कारण ऐसा संगठन आदर्श संगठन भी नहीं हो सकता। वर्तमान श्रेणी युक्त संसार में इसके द्वारा उन्नति भले ही हो जावे परन्तु सामाजिक झगड़ों की सम्भावना तो बहुत कुछ रह ही जाती है।

ऐसा भी नहीं कि यही एक प्रकार का ही संगठन सम्भव हो और मनुष्य समाज को इसी पर सन्तोष करना है। इससे भी अधिक अच्छा संगठन हो सकता है। सम्भव है समय के परिवर्तन से वातावरण में परिवर्तित हो और इससे भी अच्छा कोई ढंग निकल आवे परन्तु इस समय उन परिस्थितियों पर विचार नहीं किया जा सकता वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए इस समय किन्तो न्यायोचित संगठित आर्थिक संगठन को स्थापना हो प्रयाप्त होगी।

साम्यवाद

इस दूसरे ढंग के बटवारे में जिसे साम्यवाद कहते हैं, आवश्यक पदार्थ और सेवाओं का बटवारा, मनुष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार होता है और मनुष्यों से उनकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाता है। आशा की जाती है कि प्रत्येक मनुष्य समाज की जितनी भी सेवा कर सकता है करेगा और सामूहिक कोष से अपनी आवश्यकता भर ही पदार्थ लेगा। इससे अभिप्राय क्या है? क्या यह कि प्रत्येक मनुष्य को जितने जितने जो जो पदार्थ वह चाहे मिले और किसी को भी अपनी इच्छा से अधिक काम करने को न कहा जावे? साधारणतया यह बात आश्चर्यजनक तथा असम्भव सी प्रतीत होती है क्योंकि इतने पदार्थ ही न होंगे कि सब लोगों का जितने जितने वे चाहे दिये जा सकें। दूसरे अधिकतर लोग यदि उन्हें जीविका कमाना न हो, तो काम ही न करे।

साम्यवादी संगठन को स्थापना के लिये दो बातें सबसे आवश्यक हैं सर्व प्रथम तो देश में कृषिकौशल को प्रयाप्त वृद्धि ताकि आवश्यक पदार्थ अधिक से अधिक संख्या में बन सकें। इसके लिये आवश्यक है कि उपज के साधनों की वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक उन्नति हो। देश में सब प्रकार की कलें और मशीनें प्राप्त हों जिनके द्वारा कम संख्या में नजदूरों से ही सब मांगें पूरी हो सकें। कम से कम अधिक

परिश्रम कष्टदायक तथा नीची श्रेणी का सब काम तो मशीनों से ही ले लिया जा सके। अधिक कठिन और थकाने वाले भारी तथा प्रारम्भिक काम मशीनों द्वारा हो हो जाना चाहिए ताकि मजदूरों की शक्तियों का व्यर्थ ह्रास न हो। इसमें कोई विशेष कठिनाई भी नहीं होगी वैज्ञानिक ज्ञान का उपजकी वृद्धिके लिये प्रयोग करने से उपजाऊ शक्ति तो अवश्य बढ़ सकती है सोवियट रूस के अनुभव से यह भली भाँति सिद्ध भी होता है कि लाभ का लाभ छोड़कर वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने से उन्नति अवश्य होती है। वैसेही संसार में उद्योगिक उन्नति दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है नए नए आविष्कार होते जाते हैं जिनके द्वारा उपज में वृद्धि स्वाभाविक हो है फिर जब उन आविष्कारों का प्रयोग वर्तमान दोष पूर्ण पूँजीवादी संगठन में न होकर समाजवादी सिद्धान्तों की उन्नति में हो तब तो उन्नति और भी अधिक होगी।

परिवर्तित वातावरण

उपज की वृद्धि के अतिरिक्त, साम्यवादी संगठन होने के लिये वातावरण में परिवर्तन भी आवश्यक है। साम्यवादी संगठन के पूर्व जिसमें प्रत्येक मनुष्य को इच्छानुसार पदार्थ मिले और उसे अपनी इच्छानुसार ही काम करना पड़े मनुष्यों की विचार धारा में प्रयाप्त परिवर्तन आवश्यक है ताकि वे परिवर्तित वातावरण में अपने को आदी कर सकें। वर्षों पूँजीवादी संगठन में रहने से प्रायः उनके स्वभाव भी वैसे ही हो गये हैं और उन्हें उनको बदलने अथवा बदले हुए वातावरण में अपने को रख सकने में काफ़ी कठिनता होगी और काफ़ी समय भी लगता है। इस समय समाज में लगभग १० प्रतिशत मनुष्यों का जीवन अधिक काम और दिनभर की मेहनत में ही बीतता है। काम के आगे उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ता है। १००, १५० वर्ष की उद्योगिक उन्नति भी मनुष्य जीवन के इस ढंग को बदल नहीं सकी क्योंकि उपजाऊ शक्तियों में जो कुछ भी उन्नति इस पूँजीवादी संगठन में हुई प्रायः यह सब पूँजी तथा पूँजीवाद को बढ़ाने और उसकी उन्नति के लिये ही सुरक्षित रखी गई। भले ही उससे

पूँजीपतियों को थोड़ा लाभ हुआ हो जनसाधारण को तो उससे कोई विशेष लाभ हुआ ही नहीं। एक मनुष्य के लिये जो दिनभर कड़ी मेहनत के उपरान्त कठिनता से रूखा सूखा भोजन वस्त्र पाता हो, थोड़े समय के हल्के काम से मनोवांछित पदार्थ मिलजाना मानो एक कायापलट ही होगा। और उसके अनुसार अपने को ढालने में उसे पीढ़ियाँ बीतेगी। परन्तु इस प्रकार का वातावरण समाजवादी संगठन में, पदार्थों की अधिकता और निश्चिन्ता से शीघ्र ही सुलभ हो सकेगा।

समाजवादी संगठन में रहते हुए मनुष्य निस्संदेह शीघ्र ही वातावरण पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूँजीवाद के अन्त के बाद समाजवादी वातावरण कितने वर्षों में हो सकेगा और न इस बात की जाँच में व्यर्थ समय नष्ट करना ही ठीक होगा।

अपव्यय की आशंका

कहा जाता है कि अधिक धन मिलने पर उसे व्यर्थ गँवाने और जीवन निर्वाह के लिये काम की आवश्यकता न होने पर समय नष्ट करने का स्वाभाविक भावना होगी। आसानी तथा परिश्रम प्राप्त धन का अपव्यय तथा दुर्व्यय किया जावेगा। परन्तु ऐसा भी सदैव नहीं हो सकता, प्रारम्भ में भले ही थोड़ा बहुत ऐसा हो कोई स्त्री या पुरुष जिसे अब तक कभी पेट भर खाने व पहनने को न मिला हो भलेही खाना मिलनेपर वर्षों भूखी आत्मा को शान्ति करने के लिये एक बार बहुत-सा भोजन करले। परन्तु दिन बीतनेपर सदैव ऐसी दशा कदापि नहीं रह सकती। प्रति दिन कोई अधिक खाना नहीं खा सकता। और न किसी को ऐसी इच्छा ही होगा समय नष्ट करने के सम्यन्ध में भी यही है। बराबर अधिक समय तक कोई उसे नष्ट भी नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा करने की उसकी इच्छा ही नहीं रह सकती। यदि वह करे भी तो उसके बाल बच्चे तो कभी ऐसा करेंगे ही नहीं और इस प्रकार वातावरण बनता जावेगा। वैसे भी किसी मनुष्य को बिना रोक टोक के

पदार्थोंके लिये मांग करने को कहने से वह इस समय भी असम्भव मांग नहीं रखता। फिर ऐसे देश के लोगों के लिये जहाँ किसी पदार्थ की कमी नहीं, और प्रत्येक मनुष्य को मनोवांछित पदार्थ मिल सकते हैं यह विचार ही बिल्कुल हास्यप्रद है कि वे आवश्यकता से अधिक काई पदार्थ लेंगे भी। और फिर लेकर वे करेंगे भी क्या? ऐसे पदार्थों को संभालेगा कौन उनका प्रयोगहा क्या होगा। मान लो ऐसे वातावरण में भा कोई मनुष्य दसियों मोटर, पचासों सूट, मनो खाना, इत्यादिक ले लता है तो इन चार्जों को देख रख कौन करेगा, व्यक्तिगत नौकर ता होंगे नहीं। फिर उनका प्रयाग कौन करेगा। क्योंकि सब के पास अपनी-अपनी आवश्यकता भर सामान तो होगा ही।

इस समय आवश्यकता से अधिक सामान धनी लोग इस विचार से ही लेते हैं कि उनके द्वारा वे दूसरों को नौकरी करने के लिये विवश कर सकेंगे और उनसे लाभ अथवा आधिक सुविधा उठा सकेंगे। परन्तु उपज की अधिकता और निश्चिन्ता हाने तथा संगठन के नियमों के कारण कोई किसी का नौकर ता रख हा नहीं सकेगा। और इस कारण केवल उतने ही पदार्थ लिये जावेगें। जनको उन्हें स्वयं आवश्यकता हा और वे स्वयं हा उनकी देख रख कर सकेंगे। कि मशीनों के हाने से थोड़ी देख रख उनके द्वारा भी हा जावेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का समाज के माल का रक्षा का भी ध्यान हागा। और इससे भी पदार्थों की मांग में रोक थाम रहेगी। भोजन इत्यादिक पदार्थों में वैसे ही रोक थाम रहता है क्योंकि इच्छा से अधिक इन पदार्थों के प्रयाग ही नहीं हो सकता। अस्तु यह नहीं कहा जा सकता कि लोग आवश्यकता से अधिक पदार्थों की मांग करेंगे।

काम का आनन्द

इसके विपरीत ऐसे संगठन में एक बड़ा लाभ यह है कि मनुष्यों को काम में जीवन के आनन्द का अनुभव हागा, जिसे वे सरलता से छोड़ भी नहीं सकेंगे। क्योंकि संसार में कुछ लोग अच्छा और भलाई का काम करनेवाले आज भी अपने काम में ही जीवन का

संतोष प्राप्त करते हैं और उन्हीं में उन्हें पूरा-पूरा आनन्द भी मिलता है ।

मनुष्य समाज की उन्नति में कितनी संगठन का भी असम्भव ऐसा कह देना उचित नहीं । हमारे पृथ्वी बहुत सी बातों को असम्भव समझते थे जो आज सम्भव ही नहीं, बल्कि वास्तविक हैं । रेल व हवाई जहाज की बातों पर हँसी उड़ाई जाती थी, परन्तु आज हम उन्हें अपनी आँखों देखते हैं । कौन कह सकता है भविष्य में क्या-क्या उन्नति हो जावे, संसार का अभी प्रगत के मार्ग पर ही है । समाज ने तो उन्नति करना प्रारम्भ किया है भविष्य में क्या होगा कौन कह सकता है ।

अस्तु, संक्षेप में दो प्रकार के सामाजिक संगठन बताये गये हैं । प्रथम तो वह जिसमें उपज एक निश्चित योजना के आधार पर हाता है; और उपज का बटवारा मनुष्यों में काम का सच्चा तथा गुण के आधार पर हाता है, यह ही समाजवाद ।

समाजवादी संगठन

—:o:—

प्रयोग के लिये उपज

—:o:—

किसी भी संगठन को हटाने और उसके स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था लाने के लिये यह आवश्यक ही होता है कि उक्त दूसरी व्यवस्था लाभदायक और सुलभ हो। पूँजीवादी संगठन को दूर कर रकने के लिये भी इसी बात की आवश्यकता है। पूँजीवाद के दोष गिनाना व्यर्थ और निरर्थक हो जाएगा यदि यह न बताया जावे अथवा जा सके कि उनके स्थान पर एक दूसरा आर्थिक संगठन भली प्रकार चल सकता है। समाज के आर्थिक जीवन के संगठन का कोई न कोई ढंग अवश्य होगा ही और यदि पूँजीवाद के स्थान पर कोई दूसरा युक्त ढंग हा ही नहीं सकता तब तो विवश होकर पूँजीवाद का ही स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे वह कितना ही अन्यायपूर्ण, व्यर्थ, तथा हानिकारक ही क्यों न हो।

इसी कारण पूँजीवाद और समाजवाद के परस्परिक गुण दोष उनके आध्यात्म तथा सभ्यता से सम्बन्ध रखने वाले विषय, राजनीतिक व सामाजिक संगठन इत्यादि पर विचार करने के पूर्व समाजवादी संगठन के प्रारम्भिक आधारों का विवरण आवश्यक है। मनुष्य समाज को सबसे पहले अन्न, जल, स्थान तथा वस्त्र मिलने का प्रबंध होना चाहिये। राजनीति विज्ञान, कला तथा धर्म इत्यादिक विषयो

का विचार तो उसके बाद की बातें हैं और इसी कारण सबसे प्रथम आर्थिक समस्या पर ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा और इसका संतोषजनक उत्तर मिल जाने पर ही, समाजवादी व्यवस्था के अन्य अंगों पर विचार हो सकेगा।

प्रारम्भिक समस्या

समाजवाद की प्रारम्भिक आर्थिक समस्या तो यह है कि किसी प्रकार उपज लाभ के आधार पर न होकर आवश्यकता के आधार पर हो। समाज में पदार्थ केवल लाभ के आधार पर ही न वनाये जाने वरन् लाभ के अतिरिक्त इस बात पर स्वतन्त्र रूप से निश्चय होना चाहिये कि कौन कौन से पदार्थ बनने चाहिये और किस किस संख्या में। इसका निर्णय किस प्रकार, किस आधार पर और कैसे हो सकता है यही देखना है। क्योंकि पूँजीवादी लाभ के आधार पर होने वाली उपज, को अस्वीकार कर देने के बाद उपज के लिये कोई दूसरा ढंग तो ढूँढ़ना ही होगा।

उपज के दूसरे ढंग पर संगठन करने का एक ही उपाय है और वह यह कि कोई एक केन्द्रीय संस्था समस्त वृत्तकर पदार्थ और उसको उपज की संख्या का निर्णय कर दे और उन्हीं के अनुसार उपज हो। उपज के वश में रखने और उसे देश तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल रख सकने का यही एक उपाय हो सकता है कि जिसमें पूँजीवाद के दोषों ने छुटकारा मिल सके उपज पर इस प्रकार नियंत्रण रखने की योजना आवश्यक भी है क्योंकि कम लाभ देने वाले पदार्थों को बनाने में होने वाली हानि वा सहना भी समाज के लिये उतना ही आवश्यक है जितना कि अधिक लाभ देने वाले पदार्थों को बनाकर लाभ उठाना। यदि केवल वे ही पदार्थ बनाये जायें जिनसे लाभ हो तब तो समाज में एक उथल-पुथल ही मच जायेगा। पूँजीवादी गण्टन के दोषों को बताते हुए यह स्पष्टता कर दी गयी है कि मनुष्यों के जीवन

के लिए परमावश्यक पदार्थों के बनाने में अधिक लाभ नहीं होता क्योंकि उन पदार्थों की भाँग बहुत कुछ सीमित हो रहती है परन्तु ऐसा होते हुए भी यदि यह पदार्थ बनाये न जावे तो समाज जीवित ही नहीं रह सकता। कुछ पदार्थों के विषय में तो स्थिति यहाँ तक है कि लाभ के स्थान में हानि होने पर भी उन पदार्थों का बनाना आवश्यक होता है। जन समाज की सुविधा, उनके कष्टनिवारण और भागों को पूरा करने के लिये, ऐसे पदार्थों का बनाना स्वाभाविक और आवश्यक हो है। और यदि व्यक्तिगत व्यापारी इनके बनाने का प्रवन्ध नहीं करते तो, शासन को स्वयं ही इसका प्रवन्ध करना पड़ेगा।

इस प्रकार उपज के सम्बन्ध में जान वृद्ध कर निश्चयो द्वारा उपज को संगठित करने की रीति को ही प्रयोग के लिये उपज की व्यवस्था कहते हैं। और यही समाजवाद है।

समाजवादी संगठन

समाजवादी संगठन में किस प्रकार और किस सिद्धान्त पर काम होता है, यह बताने का सब से उत्तम उपाय किसी उद्योगशाली देश में इस व्यावहारिक रूप में चलता हुआ दिखाना ही ठीक होगा। केवल शाब्दिक परिभाषा न प्रयाप्त ही होगी, और न उससे अधिक काम ही चल सकेगा, इंग्लैंड, अमेरिका अथवा किसी ऐसे ही उद्योगशाली (Highly Industrialised) देश में इस आधार और सिद्धान्त पर बनाई गई योजना को विस्तार पूर्वक वर्णन करने और उसे व्यवहारिक रूप में रखने से ही इस प्रकार का संगठन भली भाँति समझा जा सकेगा। अभी तक तो इन देशों में आर्थिक जीवन का संगठन पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ के आधार पर ही है। परन्तु तब भी यह असम्भव नहीं कि इन देशों में उपजाऊ शक्तियों को परीक्षा करके इस बात का अनुमान किया जा सके कि प्रयोग के आधार पर उपजाऊ शक्तियों का संगठन करने से परिणाम क्या होगा और उस आधार पर नवीन योजना बनाई जावे।

अमेरिका के सम्बन्ध में तो ऐसी एक योजना तैयार भी है गो कि योजना के बनाने वालों ने अनजाने केवल राष्ट्र की उपजाऊ शक्तियों की परीक्षा करने के लिए ही इतना कष्ट और समय लगाया था। इस प्रकार की चेष्टा देश की उपजाऊ शक्तियों की राष्ट्रीय परीक्षा के लेखकों (authors of the National Survey of the Potential Product capacity) द्वारा ही की गई थी। और वे बड़े परिश्रम के उपरान्त इस परिणाम पर पहुँचे कि अमेरिका के प्रत्येक ४ मनुष्य वाले कुटुम्ब की आय ६१५ पौंड प्रति वर्ष हो सकती है।

अमेरिका के अर्थ शास्त्र ज्ञाताओं का इस दल का ध्यान जो अमेरिका के कल कारखानों तथा खेती की वास्तविक उपजाऊ शक्तियों की जाँच करने के लिए बैठा था किसी विशेष आर्थिक संगठन की ओर न था और इसी कारण उन्होंने अपनी जाँच केवल आकड़ों तक ही सीमित रखी। व्यावहारिक क्षेत्र की ओर वे अधिक आगे नहीं बढ़े और न ऐसा उनका विचार ही रहा।

वास्तव में समाजवादी संगठन, अमेरिका में किस प्रकार चल सकेगा, इसे बताने अथवा फैलाने का विचार न तो उन लोगों के विचार में ही था और न अमेरिका के शासकों का ही ध्यान इस ओर गया जब कि उन्होंने इस जाँच कमेटी की नियुक्ति की थी और उसे अपना काम करने के लिए धन दिया। कमेटी के काम का विचार करने से यह स्पष्ट पता लगता है कि किस प्रकार एक के बाद दूसरे प्रश्न उनके सम्मुख उपस्थित हुए और उन्हें सुलभाते हुए उन्होंने किस प्रकार सम्पूर्ण अमेरिका के लिए एक समाजवादी संगठन की योजना का ढाँचा बना दिया। कमेटी की काररवाई विस्तार पूर्वक जानना विशेष लाभप्रद भी है क्योंकि अमेरिका की भांति अन्य देश भी समाजवादी संगठन में उपस्थित होने वाली समस्याओं को न केवल समझ ही लेंगे वरन् व्यावहारिक रूप में उन्हें सुलभा भी समझें।

अमेरिका के शासन ने इस जांच कमेटी की नियुक्ति देश को सम्पूर्ण उपजाऊ शक्तियों का अनुमान लगाने को की थी। परन्तु उन लोगों ने इसका अर्थ यह समझा कि देश की उपजाऊ शक्तियाँ देशवासियों की आवश्यकताओं को कहां तक पूरा कर सकती हैं। और इसी कारण उन्हें अमेरिकावासियों की आवश्यकताओं की भी जांच करना पड़ी। उन्हें यह कठिन प्रतीत भी नहीं हुआ। सन् १९३३ ई० में जब कि यह जांच प्रारम्भ हुई अमेरिकावासियों को खाना, कपड़ा घर इत्यादिक आवश्यक वस्तुओं में बहुत कमी थी।

घरों का ही उदाहरण ले लीजिए। अमेरिकावासियों के रहने की आवश्यकता पूरी करने के लिये १ करोड़ ५० लाख नए घर चाहिये थे, इतने घरों के हो जाने पर प्रत्येक चार मनुष्यों के कुटुम्ब के लिए प्रचलित सुविधाओं सहित पाँच या छः कमरों वाला एक घर हो सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार दस वर्षीय योजना से प्रति वर्ष १५ लाख ५० हजार घर बनाना आवश्यक होता था परन्तु क्या इतने घर बनाने की आवश्यकता सामग्री देश में थी? क्या प्रयाप्त संख्या में मजदूर ईंटों, लोहा, विद्युत शक्ति इत्यादिक सामग्रियाँ प्राप्त थी? उत्तर स्पष्ट है, कि अवश्य थीं यदि वे अन्य किसी काम में न लगाई जाती परन्तु उनमें से कुछ को तो अवश्य ही दूसरे कामों में लगाना पड़ेगा क्योंकि देश के सब मजदूर केवल घर बनाने में ही तो नहीं लग सकते। यदि ऐसा हो भी तो बहुत से मनुष्यों को भूखे ही मरना पड़े, क्योंकि इन सामग्रियों का बहुत बड़ा भाग अन्य उतनी ही आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे खाना, कपड़ा, व्यावहारिक रूप में शिक्षा, माल ढोने, मनोविनोद इत्यादिक कामों में लगता है। मजदूरों को केवल घर ही नहीं बनाने हैं वरन् वे अनाज भी उपजाते हैं। इसी प्रकार लोहे, विद्युत शक्ति इत्यादि का प्रयोग अन्य मशीनों को बनाने, नल ढालने इत्यादि में भी होगा। इसलिए प्रश्न तो यह रह जाता है घर बनाने की सामग्री की माँगें पूरी करने के पश्चात् क्या दस वर्ष तक १५ लाख ५० सहस्र घर बनाने की शक्ति बाकी रह जाती है और यह प्रश्न स्पष्ट रूप से

इसी बात पर निर्भर है कि उतनी ही आवश्यक माँगें क्या क्या हैं ? अथवा दूसरे शब्दों में 'एक देश की उपजाऊ शक्तियाँ किन किन प्रयोगों में लगाई जावें और इसका निर्णय कौन करे।' यह तो स्पष्ट ही है कि बहुत सी उपजाऊ शक्तियों के कई प्रयोग हो सकते हैं। मजदूरों की कोई एक संख्या घर बनाने, भोजन सामग्री उत्पन्न करने, लिखने पढ़ने अथवा किसी और धन्य में लगाई जा सकती हैं लोहे की एक निश्चित संख्या घर के नल बनाने, इन्जन बनाने तथा बरतन बनाने इत्यादि में लग सकती है विद्युत शक्ति का प्रयोग कल कारखानों को चलाने में हो सकता है अथवा घरों की रोशनी में, परन्तु उसी निश्चित संख्या में एक समय में दोनों प्रयोग नहीं हो सकते।

उदाहरण से यह बात विल्कुल स्पष्ट हो जाती है। प्रति वर्ष आवश्यक संख्या में घर बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में लोहा या इस्पात चाहिये। रिपोर्ट लेखकों को जांच करनी थी कि क्या दूसरे उतने ही आवश्यक कामों में लगने के पश्चात् इतना लोहा बचेगा कि घर बनाने के लिए सामग्री की माँग पूरी की जा सके। तुरन्त ही प्रश्न होता है कि क्या वे सब काम जिसमें यह लोहा लगता है उतने ही आवश्यक हैं जितना कि घर बनाना। सन् १९२६ में अमेरिका में लोहे अथवा इस्पात की उपज का एक बहुत बड़ा भाग कार्यालयों के लिये गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ बनाने में प्रयोग होता था। और रिपोर्ट लेखक यह बात लिखे दिना नहीं रह सके कि अमेरिका वासियों को कार्यालयों के लिये गगनचुम्बी अट्टालिकाओं की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी की छोटे-छोटे घरों की देशवासियों की एक बड़ी संख्या टूटे फूटे गन्दे और भरे हुए मकानों में रहती थी और उसके बहुत दिनों पश्चात् तक भी रही। इसके विपरीत दूसरी और यह भी स्पष्ट था कि किसी को भी कार्यालयों के लिये अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बहुत से नए बने हुए ऊँचे ऊँचे घर खाली पड़े थे और जो किसी किसी में लोग थे भी, वे आस पास के अपने कार्यालयों को छोड़ कर इसमें रहे थे। इतना होने पर भी अमेरिका का

अधिक लोहा नई गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के बनने में ही लगाया जाता था। रिपोर्ट लेखकों का यह बात बड़े आश्चर्य की प्रतीत हुई क्योंकि अन्य मनुष्यों की भाँति उनको भी यही विश्वास दिलाया गया था कि दैशावासियों को उस समय (सन् १६२६ ई० में) कार्यालयों के लिये ऊँचे-ऊँचे मकानों की ही अधिक आवश्यकता है। न को छोटे घरों की। गोकि वास्तव में ऐसे ऊँचे-ऊँचे घर कहीं अधिक संख्या में थे।

जाँच करने के पश्चात्, वे स्वयं भी इसकी आवश्यकता को जान सके। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि सन् १६२६ ऐसे उन्नति वाले वर्ष में भी अमेरिका वासियों ने अपने लोहे की कलौ का उनकी शक्ति से केवल ८४ प्रतिशत ही प्रयोग किया और सन् १६३२ ई० में तो २० प्रतिशत से भी कम यदि १६२६ ई० में अमेरिका वासी अपनी लोहा बनाने की शक्ति का पूरा-पूरा प्रयोग करते तो अन्य प्रकार के लोहे के साथ साथ ८ द्वांसलव ७ लाख मकान बनाने वाला लोहा उत्पन्न कर सकते थे—रिपोर्ट लेखकों के सामने यह भी प्रश्न उठा कि मकान बनाने के लिये लोहा कितना मिल सकेगा। इस बात का अनुमान लगाते समय यह भी विचार आवश्यक हुआ कि यदि आवश्यकता भर लोहा उत्पन्न भी हो गया होता तो क्या इसमें से भी एक बहुत बड़ा भाग कार्यालयों के लिये ऊँचे २ घर बनाने में न लगता, माँग और लाभ के आधार पर तो यह मानना ही पड़ेगा कि ऐसा ही होता। ऐसी स्थिति में घर बनवाने के लिये कभी लोहा बच ही नहीं सकता।

कमेटी के सदस्यों को यह विश्वास असम्भव प्रतीत हुआ कि दैशावासियों को गगनचुम्बी अट्टालिकाओं की अधिक माँग है। निस्संदेह उनकी संख्या बहुत थी। उन लोगों का ऐसा विचार हुआ कि अधिक संख्या में उत्पन्न होने वाला लोहा सम्भवतः घर बनवाने के काम में ही लगाया जाता। वे इस परिणाम पर भी पहुँचे कि अमेरिका का प्रत्येक कुटुम्ब उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकता है जिस प्रकार सन् १६२६ ई० में ६१५ पौंड अथवा ४४०० डालर (dollar) आयवाले

कुटुम्ब वास्तव में व्यतीत करने थे। यों तो यह परिणाम बिल्कुल दोष रहित प्रतीत होता है परन्तु व्याहारिक रूप में ऐसा है नहीं। क्योंकि यदि यह मानलिया जावे कि अधिक उत्पन्न किया गया सब लोहा घर बनाने में ही लगाया जाता, अथवा उसे उन्नत काम में लगाने को कहा जावे तो प्रश्न वहीं आजाता है कि उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग भिन्न २ कामों में किस प्रकार से बाँटा जावे और इसे कौन करे। यदि ऐसा हो भी सके तो भी कठिनाई तो यह है कि प्रचलित संगठन में इस प्रकार का विभाजन करना तो एक अवगुण गिना जाता है क्योंकि ऐसे काम का अर्थ—लाभ के आधार पर माँग और विक्री को स्वयं मिलाने वाली व्यवस्था पृथक् होना ही होगा जो पूँजीवाद का प्रारम्भिक आधार है। इस प्रकार पूँजीवादी संगठन को छोड़ कर दूसरे ही प्रकार के संगठन को मानना और उस पर काम करना होगा। ऐसा संगठन समाजवाद के अनिर्दिष्ट और क्या हो सकता है।

कमेटी ने अन्तिम निश्चय यही किया कि उत्पन्न हुए लोहे की संख्या मकान बनाने में ही अधिक लगना चाहिये और कारखानों के लिये ऊँचो २ मीनारे बनाने में कम, गोकि बड़े २ कारखानों के मालिक तथा व्यापारिक दिग्गज यही कहते रहे कि देशवासियों को घरों से कहीं अधिक मीनारों की आवश्यकता है।

पूँजीवाद के समर्थक सम्भवतः यह आपत्ति रखे कि इन रिपोर्ट लेखकों को किसने शासक तथा न्यायाधीश बनाया कि वे इस प्रकार उपज के प्रयोग पर निर्णय दें। इतना ही नहीं कि लेखक केवल लोहे की उपज का प्रयोग बताकर ही संतुष्ट हो गये हो कि उसका प्रयोग मीनार बनाने में कितना हो और कितना घर बनाने में। चरन् ज्यों ही उन्हें देशवासियों की खाना, कपड़ा, मोटर और सैकड़ों अन्य प्रकार की माँगों और उन्हें पूरा कर सकने की शक्तियों का पता लगा, उन्हें यह प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगा, कि जब तक वे अमेरिका के सब उपजाऊ कल कारखानों की शक्ति तथा इन कारखानों से बनी

वस्तुओं के प्रयोग का पूरा-पूरा पता न लगा ले । उनके लिए यह कहना असम्भव है कि देशवासियों की यह मांगें और कितनी हैं और वह कैसे पूरी हों । इसी लिए उपजाऊ शक्तियों से उत्पन्न होनेवाली सब फ़ालतू सामग्रियां तथा अधवने पदार्थों का फिर से बटवारा करने का उन्होंने निश्चय किया । और यह बटवारा सन् १९२६ ई० में प्रचलित ढंग पर न करके, उसे उन-उन प्रयोगों में बांटा जिसे उन्होंने अधिक आवश्यक समझा ।

परन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि वे इस परिणाम पर किस प्रकार पहुँचे और कैसे उन्होंने यह निश्चय किया कि कौन-कौन से प्रयोग अधिक आवश्यक और कम आवश्यक हैं ।

उनका ध्यान इस बात पर अधिक रहा कि लब्ध उपज का प्रयोग इस ढंग से किया जावे कि इससे मनुष्यों की प्रारम्भिक आवश्यकताये जैसे खाना, कपड़ा, घर इत्यादिक भली भाँति पूरे हो सके । और उनकी दूसरी मांगें ।

जैसे देखने के लिए मीनारे, खेल, तमाशे आमोद प्रमोद की सामग्रियां इसी प्रकार की अन्य मांगों को पूरा करने में देश की उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग कम हो । इस प्रकार उनके लिए मनुष्यों की मांगों को आवश्यकता के पारस्परिक सम्बन्ध का भी निर्णय आवश्यक हुआ दूसरे शब्दों में मनुष्यों की वास्तविक मांगें क्या हैं ।

मांगों का अनुमान

मनुष्यों की मांगों का अनुमान लगाने के लिये देशवासियों के लिये दजट बनाने की आवश्यकता हुई और फिर इस बात की जाँच की कि देश की उपजाऊ शक्ति इन सब मांगों को पूरा कर सकती हैं अथवा नहीं । जाँच के उपरान्त वे इस परिणाम पर पहुँचे कि शक्तियाँ तो काफ़ी हैं परन्तु उनके प्रयोगों में परिवर्तन करना आव-

शक्य है। और वह इस ढङ्ग से होना चाहिए कि वजट में कहे हुए आवश्यक पदार्थों को बनाने में ही उनका विशेष प्रयोग हो।

इसके विपरीत पूँजीवादी शास्त्रज्ञों का कहना है कि इस प्रकार का ऐसा कोई वजट बनाया ही नहीं जा सकता। ब्रिटेन और अमेरिका के विश्व विद्यालय तक इसे असम्भव ऐसा कहने हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। उनका यह कहना कि मनुष्यों की माँगें इतनी भिन्न और अधिक हैं यह कहा ही नहीं जा सकता कि वे क्या-क्या पदार्थ चाहते हैं और कितनी-कितनी सख्या में। उनकी माँगों का कोई वजट बना नहीं सकता। माँगों की परख तो रुपये से होती है कि वे किस पदार्थ के लिए कितना रुपया व्यय कर सकने हैं। उनकी माँगों की यही सच्ची तोल है। उपज को भी इसी आधार पर बढ़ाना व बढ़ाना चाहिये विक्री अधिक होने अथवा मूल्य अधिक मिलने पर किसी पदार्थ की उपज अन्यथा बढ़ाना घटाना ही आवश्यक होगा।

उपरोक्त लोहे के उदाहरण में इस आधार पर फ़ालतू सब उपज ऊँची मोनारों के बनाने में लगाने से तो मनुष्यों को टूटे भोपड़ों में ही पड़े रहना पड़ेगा उनका यह भी कहना है [कि यदि इस आधार पर उपजाऊ शक्तियों का पूरा-पूरा प्रयोग न भी हो सके, तो भी अपना दुर्भाग्य इससे अधिक और कुछ नहीं, अन्य कोई प्रबन्ध हो ही नहीं सकता वजट के अनुसार उपज करने के अर्थ तो मनुष्यों को उन पदार्थों के लेने के लिए विवश करना है जिन्हें वे लेना नहीं चाहते भलेही उन्हें उनकी माँग हो।

यदि इस सिद्धान्त पर साधारण रूप से ही विचार किया जावे तो यह कुछ-कुछ ठीक भी प्रतीत होता है प्रत्येक देशवासी के लिए खाना, कपड़ा, घर इत्यादि पदार्थों का पहले वजट बनाकर फिर यह कहना कि केवल वे ही पदार्थ बनाए जावें थोड़ा नानाशाही सा ही दिखना है।

परन्तु तो भी ठीक यही है कि उपज का निर्णय मनुष्यों की माँगों के आधार पर हो। न कि उनके मूल्य देने करने की शक्ति पर।

साधारण रहन सहन

मनुष्यों का मांगों का अनुमान लगाने में कोई विशेष कठिनाई भी नहीं आश्चर्य की बात भले ही प्रतीत हो। परन्तु वास्तव में दैशवासियों की मांगों का निश्चय करना देश की उपजाऊ शक्तियों के अनुमान से कही सरल है। किती एक मनुष्य के लिये कितना खाना आवश्यक होगा, कितना कपड़ा और स्थान वह चाहेगा, इत्यादिक आवश्यक मांगों का अनुमान लगाना कठिन नहीं क्योंकि एक समय साधारण मनुष्य को अधिक तर समान ही खाना, और खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी। मध्यश्रेणी और बड़े २ शहरों के रहने वालों के इन पदार्थों में वास्तविक व्यय के अनुसार भोजन की माँग का अनुमान लग सकता है। इसी प्रकार निवात स्थान के सम्बन्ध में। स्वभावतः एक मनुष्य ५ या ६ कमरे वाले घर में रहना चाहेगा गोकि उससे कम में भी सम्भवतः उत्का निर्वाह हो सके औषधि, पढ़ाई इत्यदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अध्यापको, डाक्टरों, तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से जाँच करके इन पदार्थों और सेवाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। और इस प्रकार दैशवासियों की मांगों का एक वजट बनाया जा सकता है। ऐसा वजट बन जाने पर उसके अनुसार सुविधा से उपज की व्यवस्था की जा सकती है।

अनुमान लगाने का ढंग

व्योहारिक रूप में भी ऐसा वजट बनाने तथा मांगों का अनुमान लगाने में कोई विशेष कठिनाई न होगी। इस काम में केवल दोही मुख्य बाधाएँ हैं एक तो मनुष्यों की वास्तविक मांगों को जानना और दूसरे उनका केन्द्रीय आधार।

प्रथम के सम्बन्ध में यह तो पता चल ही सकता है कि उनकी मांगें अब तक क्या रही हैं। गत वर्ष इन मांगों का क्या अनुपात रहा। उसमें क्या घटती व बढ़ती होनी चाहिए।

गत वर्ष को माँगों और उनके अनुपात के आधार पर अगले वर्ष के लिए अनुमान लगाया जा सकता है। भले ही पिछले वर्ष की रहन सहन संतोष जनक न रही हो परन्तु उससे अगले वर्ष के लिए आधार तो अवश्य ही मिल सकता है। और फिर उस आधार में आवश्यक घटा बढ़ाकर भविष्य के लिए वजट बनाना कठिन नहीं। गतवर्ष के प्रयोग में देशवासी अगले वर्ष के लिए कितनी वृद्धि चाहेंगे इतना ही अनुमान लगाना रह जाता है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान समाज में अधिकतर कुटुम्बों का रहन सहन असन्तोषप्रद होने पर भी कुछ कुटुम्ब ऐसे अवश्य होते हैं जिनका रहन सहन अच्छा नहीं तो साधारण तथा सन्तोषजनक अवश्य होता है। बड़े बड़े धनी व्यक्तियों का यहाँ उल्लेख नहीं। उनका रहन सहन तो एक अद्भुत प्रकार का मनमाना सा ही होता है। परन्तु मध्य श्रेणी के कुछ कुटुम्बों की पिछली रहन सहन भविष्य के लिये आधार अवश्य मानी जा सकती है। और उस आधार को लेकर यह कहा जा सकता है कि देशवासियों को साधारणतया उस रहन सहन तक तो पहुँचना ही चाहिए। इस प्रकार रहन सहन को एक कम से कम मात्रा (Minimum average standard) स्थापित हो जाती है जिस पर भिन्न भिन्न परिस्थिति के व्यक्तियों अथवा कुटुम्बों को रहन सहन, उनको काम करने की योग्यता, आय, तथा आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित की जा सकती है। यह तर्क उचित तथा न्याय संगत तो अवश्य प्रतीत होता है।

इस प्रकार देशवासियों की आवश्यक माँगों का अनुमान लगा कर फिर उसके आधार पर उपज का बटवारा भिन्न भिन्न पदार्थों में हो ताकि प्रत्येक पदार्थ उतनी ही संख्या में बने जितने कि आवश्यक हों तभी मनुष्यों को सब माँगें पूरी हो सकेंगी। पूँजीवादी व्यवस्था में तो यह हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ तो आधार ही दूसरा है और इसी कारण तो ऐसी व्यवस्था का

अन्त करके नए ढङ्ग पर योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ।

वजट में संशोधन

प्रथम वर्ष तो सम्भवतः माँगों के पदार्थों की सूची ही बन सकेगी और फिर उसमें भी त्रुटियाँ रह सकती हैं । ठीक अनुमान न लग सके यह भी सम्भव है परन्तु बाद के वर्षों में धीरे धीरे त्रुटियाँ दूर होती जावेगी और फिर अनुमान निश्चित आधार पर पूर्ण रूप से बन सकेगा ।

किसी वर्ष के प्रस्तावित वजट में केवल योजना बनाने वालों की त्रुटियों के कारण ही, संशोधनों की आवश्यकता न होगी वरन नए नए अविष्कारों और जनता की इच्छाओं में उनसे होने वाले परिवर्तनों के कारण भी ऐसे वजट में संशोधन करने पड़ेंगे । ऐसा तो है नहीं, और न होही सकता है, कि मनुष्यों के स्वभाव और इच्छाएँ सदैव एक ही सी रहे और उनमें कभी कोई अन्तर ही नहीं पड़े । वास्तव में वे समय समय पर बदलती जाती है । और इसी कारण योजना बनाने वालों को अगले वर्ष के लिये योजना बनाते समय, इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा ।

योजना बनाने वालों से कभी कोई त्रुटि होवेगी ही नहीं, और वे सब ठीक ही काम करते रहेंगे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । प्रारम्भिक काल में अथवा योजना समिति के अयोग्य होने पर त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है परन्तु तो भी यह निश्चित है कि पूँजीवाद के लाभ और विक्रो के आधार पर बनी योजना से इस प्रकार की योजना कहीं अधिक अच्छी और सुचारु रूप से चलनेवाली होगी । ऐसी योजना में यह तो कभी नहीं हो सकेगा कि दैश में, पाउडर, (Powder), स्नो (Snow), अथवा सुन्दतावर्धक अन्य पदार्थ बनने रहे और लाखों स्त्री पुरुष भोजन के अभाव से तड़प २ कर मर जायें, कपड़ा और निवासस्थान के अभाव से शीत लहे अथवा इसी प्रकार के अन्य कष्टों से लगातार दुःखी रहे ।

उपरोक्त योजना में यह भी सम्भव नहीं होगा कि एक ही समय में शहर वासी रोटी के लिये तरसें और उसी समय किसान गेहूँ की उपज की अधिकता से उसे बेचने पर उपज का मूल्य तक न पाकर दुर्दशा को प्राप्त हो । ऐसा तो पूँजीवाद में ही होता है कि एक ओर किसान की अधिक उपज बड़े २ संघों द्वारा सस्ते भाव पर मोल लेली जाती है और दूसरी ओर भूख से पीड़ित देशवासियों को, उनकी माँगों की तोत्रता से लाभ उठा कर केवल लाभ के आधार पर महँगे भाव से बेची जाती है । संगठन शक्ति के अभाव, धन की कमी, और दरिद्रता से प्रेरित होकर और अपनी उपज की विक्री का दूसरा उपाय न पा कर, किसान उसे कम मूल्य पर ही बेचने को विवश होता है । ठीक इसी प्रकार देशवासी भोजन की अधिक आवश्यकता होने, और अन्य उपायों से उसे प्राप्त न कर सकने पर, उस पदार्थ के लिये अधिक मूल्य देने को तय्यार होते हैं । पूँजीवाद में ऐसे आवश्यक पदार्थ अधिक लाभ उठाने के अभिप्राय से संघों द्वारा केन्द्रीय भूत कर लिये जाते हैं । परन्तु समाजवादी संगठन में यह सम्भव ही नहीं ।

पदार्थों का क्रय मूल्य

नुटि रह जाने अथवा माँगों में अन्तर पड़ने का फल यह होगा कि वर्ष के अन्त में कुछ पदार्थ शेष बचेंगे और किन्हीं की संख्या घटेगी । अगले वर्ष योजना बनाते समय पिछले वर्ष के परिणाम का ध्यान रखकर शेष बचनेवाले पदार्थों में से उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग हटाकर कमीवाले पदार्थों में किया जावेंगे जिससे भविष्य में आवश्यक अनुपात ठीक रहे ।

परन्तु महत्व की बात तो यह है कि संगठन में इस परिवर्तन का प्रभाव पदार्थों के क्रय मूल्य पर नहीं पड़ने दिया जाता । ऐसा नहीं होने पाता कि कम पड़ने वाले पदार्थों का

मूल्य दिया जावे और इस प्रकार संख्या की कमी से लाभ उठाया जावे। और न अधिक उपज के पदार्थ के मूल्य को घटाकर उसे कम मूल्य पर बेचकर हानि को पूरा करने की चेष्टा ही की जाती। विक्रो का मूल्य तो उपजके मूल्य (cost of production) पर हो आश्रित रहता है। क्रय मूल्यमे परिवर्तन तो योजना बनानेवालों के भली भाँति विचार और निश्चय के पश्चात् ही होता है।

पदार्थों के माँग में कमी और बढ़ती के अनुसार पदार्थ के क्रय मूल्य में परिवर्तन करना तो पूँजीवादी व्यवस्था का सिद्धान्त है उसी में पदार्थों की माँग व विक्री के आधार पर क्रय मूल्य निश्चित होता है।

समाजवाद में तो पदार्थ के मूल्य का निर्णय उसकी माँग और विक्री पर न रहकर, उसके उपज के मूल्य, समाज में आवश्यकता और पदार्थ की सार्थता पर निर्भर रहता है और इन बातों में परिवर्तन से ही उसके क्रय मूल्य में परिवर्तन हो सकेगा। केवल माँग अथवा विक्री के घटने बढ़ने से नहीं।

परिणाम

अस्तु रिपोर्ट लेखकों ने यह एक बड़े महत्व का काम किया। इस प्रकार बजट बनाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े-बड़े उद्योगशाली देशों के लिये भी देशवासियों की माँगों का अनुमान हो सकता है। तथा इसके द्वारा यह स्पष्ट बता दिया कि समाजवादी संगठन की योजना किस प्रकार चल सकती है। तर्कशास्त्रों की बड़ी-बड़ी पुस्तकें भी इसे इतना स्पष्ट न बता सकती।

रिपोर्ट व्यवहारिक रूप में विस्तार पूर्वक सिद्ध कर देती है कि बड़े-बड़े और पैचीदा आर्थिक संगठन भी किस प्रकार प्रयोग के आधार पर हो सकते हैं और वर्तमान हानिकारक एवं घातक पूँजीवादी लाभ के आधार को हटाकर उद्देश्य की उपजाऊ शक्तियों का संगठन प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है।

रिपोर्ट लेखकों को यह परिणाम भले ही अचानक प्राप्त हो गया हो । परन्तु अकस्मात् ही सही, उन्होंने ऐसी संगठन की व्योहारिकता और उसकी सब से अधिक आवश्यकता का भली भाँति प्रदर्शन तो कर ही दिया, जिसे समाजवादी व साम्यवादी चाहते हैं । और ऐसा ही संगठन समाजवाद है ।



योजना

—:o:—

उपजाऊ शक्तियों का बटवारा

—:o:—

गत परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि समाजवादी संगठन में आवश्यक पदों के बनने का अनुपात किस प्रकार निर्णय हो और योजना समिति भिन्न भिन्न पदार्थों की संख्या कैसे निश्चय करे। इसके अतिरिक्त समिति को एक बात का और भी निर्णय करना रह जाता है, कि किसी वर्ष में देश की उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग उपज के साधनों के बनाने में किस अनुपात से हो। अथवा आवश्यक पदार्थ और साधनों के बनाने में क्या अनुपात रहे।

जनता की आवश्यकता के पदार्थ, दूध, मक्खन, जूते, कपड़ा, घर इत्यादिक वे पदार्थ हैं जो सीधा मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके विपरित उपज के साधन वे हैं जिनके द्वारा ये पदार्थ बनते हैं जैसे मशीन औजार इत्यादि अथवा वे पदार्थ जिनसे मनुष्यों की आवश्यकताएँ सीधे पूरी नहीं होती।

उपज के साधन

प्रत्येक समाज में दोनों प्रकार के पदार्थ बनाना आवश्यक होता है। केवल आवश्यक पदार्थों के बनने से ही काम नहीं चल सकता।

और न केवल साधनों के बनाने से ही। क्योंकि यदि साधन न हुए, तो आगे पदार्थ बनना ही वन्द हो जावेगा। और इसी प्रकार यदि पदार्थ न बने, तो साधनों का बनना और होना व्यर्थ ही है। उदाहरण के लिये यदि मशीन और औजार हो बनाए जावें तो जनता भूखी मर जावेगी। और इस प्रकार यदि खाना कपड़ा, अथवा अन्य आवश्यक पदार्थ हो बनाये गये, तो साधनों के बिना बहुत दिनों तक वे बनने रह ही न सकेंगे और जनता को फिर उनके बिना रहकर कष्ट ही उठाना पड़ेगा।

देश की उपजाऊ शक्तियाँ एक पर्याप्त संख्या में इन मशीनों व औजारों के बनाने में लगाना पड़ेगी ताकि वर्तमान मशीनों, औजारों तथा अन्य साधनों के चित्र जाने या बिगड़ जाने पर उनके स्थान पर काम करने के लिये दूसरे प्राप्त रहे। और यदि सम्भव हो तो वर्तमान साधनों के स्थान पर नवीन प्रचलित ढंग की मशीनों का प्रयोग हो ताकि उपज में दिन प्रति दिन उन्नति होती जावे। परन्तु ऐसा तो तभी सम्भव होगा जब जनता के आवश्यक पदार्थों की उत्पत्ति में कमी हो। तभी तो इस प्रकार बची हुई सामग्री साधनों के बनाने में लगाई जा सकेगी।

किसी देश अथवा समाज में, मजदूरों की संख्या, संगठनशक्ति तथा आवश्यक सामग्री एक निश्चित संख्या में ही होती है। उनका चाहे पदार्थ बनाने में प्रयोग हो अथवा साधन उत्पन्न करने में। एक ही समय में दोनों प्रकार में प्रयोग हो ऐसा सम्भव नहीं। इसी लिये यह आवश्यक है कि इन बातों का पहिले से ही निर्णय हो जावे कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करे और कौन से पदार्थ, कितनी संख्या में बने तथा इन पदार्थों की उत्पत्ति और उपजाऊ शक्तियों के प्रयोग में अनुपात क्या हो।

ऐसी स्थिति में समाज के मन्मुख यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देश की उपजाऊ शक्तियाँ इन दोनों कामों में किस प्रकार बाँटी जावे दूसरे शब्दों में, यह निर्णय करना है कि भाविष्य में अधिक माँगें पूरा

करने के प्रबंध के लिये वर्तमान माँगों और उनके अनुसार बनने वाले पदार्थों में कितनी कमी की जावे और इस प्रकार किस अनुपात से वर्तमान पदार्थ तथा मशीने इत्यादि घनें।

बटवारा

उपजाऊ शक्तियों की वृद्धि चाहने वाले प्रत्येक समाज को उपरोक्त दोनों प्रकार के कामों में देश की शक्तियों का बटवारा करना होगा चाहे किसी भी प्रकार का संगठन क्यों न हो। पूँजीवाद व समाजवाद दोनों में ही ऐसा बटवारा आवश्यक है। बटवारे के भाग और अंगों में भिन्नता आवश्यक है। कुछ का कहना है कि जनता के वर्तमान आवश्यक पदार्थ बनाने से केवल उतनी ही उपजाऊ शक्तियाँ मशीन इत्यादि बनाने में लगाई जावे जिससे वे भविष्य के लिये ठीक रह सके अथवा बिगड़ जाने पर बदली जा सके। इसके विपरीत दूसरा मत यह है कि जनता के आवश्यक पदार्थ बनाने में केवल उतनी ही शक्तियों का प्रयोग हो जिससे मनुष्य केवल जीवित भर रह सके। शेष सब शक्तियों का प्रयोग उपज के साधनों के बनाने (Means of Production) में ही हो।

इस प्रश्न पर यह दोनों अन्तिम सीमाएँ हैं वास्तविक निर्णय तो बीच का ही हो सकेगा। देखें पूँजीवाद में इस प्रश्न का क्या उत्तर है और इसका कैसे निर्णय होता है।

पूँजीवादो संगठन के समर्थकों का यह कहना है कि पूँजीवाद में यह प्रश्न इस रूप में रहता हो नहीं। वह तो एक दूसरे ढंग से ही सुलझ जाता है। पूँजीवाद में उपजाऊ शक्तियों का उपरोक्त दोनों कामों में बटवारा, और उसका अनुपात, मनुष्यों के धन संचय और व्यय शक्ति के अनुपात पर निर्भर रहता है। जितनी ही अधिक व्यय शक्ति मनुष्यों में होगी आवश्यक पदार्थ बनाने की संख्या उतनी ही अधिक रहेगी। और जितना धन वे संचय करेंगे, उतना उपज के साधनों को उत्पन्न करने में लगेगा, क्योंकि क्रय शक्ति की वृद्धि के साथ उनकी माँगों

में वृद्धि और उनके लिये अधिक मूल्य देने को तत्पर होवे जिस से उन पदार्थों के बनाने वालों को लाभ हो और वे इस लाभ के प्रोत्साहन से अधिक संख्या में इच्छित पदार्थ बनावें । इसके विपरीत जितना अधिक धन संचय होगा, उतनी ही उपज के साधनों की वृद्धि होगी । क्योंकि जो रुपया वे संचय करेंगे उसे व्यर्थ तो फेंक नहीं दगे और न उसे सुस्त पड़ा ही रहने देंगे । वह किसी न किसी काम में ही लगेगा । और काम में लगाना ही, उपज के साधनों का उत्पन्न करना है । उदाहरण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है ।

मानलो किसी व्यक्ति ने १००) संचय किया और उससे किसी एक विद्युत कम्पनी के शेयर मोल लिये । जिसके अर्थ यह होते हैं कि खाना कपड़ा इत्यादिक आवश्यक पदार्थों की विक्री कम हुई तभी तो इतना रुपया बच सका । दूसरी ओर इस धन से विद्युत कम्पनी के पूँजी की वृद्धि हुई और व्यक्ति विशेष को कम्पनी में इतने रुपये भर स्वामित्व मिला और उसके द्वारा लाभ । इस प्रकार बचत के अनुपात से पदार्थों के बनने में कमो और उपज के साधनों में वृद्धि हो जाती है ।

धन संचय जितना अधिक होगा, क्रय शक्ति उतनी ही बढ़ेगी और उसी अनुपातसे आवश्यक पदार्थों की उपज भी बढ़ेगी । इसके विपरीत उपज के साधनों में उतनी ही वृद्धि होगी । और इस प्रकार लाभ के आधार पर उपजाऊ शक्तियाँ पदार्थों से हटकर धीरे धीरे साधनों में लगने लगेगी बचत और व्यय के अनुपात से यह समस्या सुज्ञानी सी प्रतीत अवश्य होती है परन्तु ठीक ढङ्ग पर नहीं और न किसी निश्चित आधार पर ही । ऐसी व्यवस्था पूँजीवादी विचार धारा के भी विरुद्ध है । पूँजीवाद समर्थकों का तो यह दावा है कि पूँजीवाद में सब प्रश्न प्राकृतिक नियमों से ही सुज्ञान जाते हैं व्यक्ति विशेष द्वारा अथवा समाज का उन पर कोई अधिपत्य नहीं होता और न उनके निश्चयों पर ही वह आश्रित रहता है । परन्तु वास्तव में क्रय

और संचय का निर्णय भी तो मनुष्य ही करते हैं। और उसका अनुपात उनके निश्चयों के अनुसार ही तो होता है।

फिर इन निर्णयों को भी व्यक्ति विशेष पर न छोड़कर सम्पूर्ण समाज पर ही न डालें और उती के द्वारा देश भर के लिये निर्णय न करा लें। अथवा दूसरे शब्दों में योजना बनाने वालों से ही इस बात का निर्णय करा ले क्योंकि योजना समिति की नियुक्त भी समाज ही करेगा।

अस्तु, पिछले परिच्छेद के उदाहरण में योजना समिति को अब केवल इतना ही निश्चय नहीं करना है कि लोहे की उपज का कितना भाग निवास स्थान तथा गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के बनाने में लगे वरन उन्हें इसका भी निर्णय करना होगा कि किस अनुपात से लोहा इन पदार्थों में पड़ेगा और कितना मशीनों इत्यादि में उपज के साधनों के बनाने अथवा बनवाने में लगे क्योंकि उनही के द्वारा फिर अधिक लोहा बन सकेगा।

१९२६ का आधार

योजना समिति ने इस प्रश्न को भी बड़ी सरलता से समझाया। उन्होंने सन् १९२६ ई० को ही इसका भी आधार बनाया। इस वर्ष के आकड़े लेकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि उपजाऊ शक्तियों का जितना प्रयोग सन् १९२६ ई० में साधनों के उत्पन्न करने में लगा है यदि उतनाही भविष्य में भी लगता रहे अर्थात् यदि अमेरिकावासी अपने उपज के साधनों को वृद्धि और उन्नति प्रति वर्ष इतनी ही करते रहे तौ भी उनकी आय। (सन् १९२६ के मूल्य के) आधार पर २०० पौंड से ६१५ पौंड हो सकती है।

यह वर्ष तो केवल उदाहरण के लिए ही मान लिया गया था। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि अमेरिका, ब्रिटैन अथवा किसी अन्य देश

के लिए योजना बनाते समय इसी वर्ष को ही आधार माना जावे। अथवा प्रति वर्ष का उतना ही अनुपात रक्खा जावे। अनुमान घटाया अथवा बढ़ाया भी जा सकता है। अनुपात घटाने पर जन साधारण के आवश्यक पदार्थों में वृद्धि और बढ़ाने पर उसमें उतनी ही कमी हो जावेगी।

यह तो विशेष महत्व की बात नहीं, कि यह अनुपात क्या हो। परन्तु प्रत्येक समाज के लिए यह परमावश्यक है कि अनुपात का अन्तिम निश्चय उसके हाथ में रहे। अनुपात के निश्चय को लाभ के अन्ध विश्वासी आधार पर छोड़ देना ही समाज की वर्तमान दुर्दशा का एक मुख्य कारण है।

ब्रिटैन, अमेरिका तथा अन्य उन्नति शाली पूँजीवादी देशों के लिये इस अनुपात के निश्चय करने में अधिक कठिनाई नहीं। वहाँ तो मशीनें तथा अन्य साधन प्रयाप्त संख्या में हैं ही। उनका काम तो देश की उपजाऊ शक्तियों का अधिकतर प्रयोग जनता की आवश्यक माँगों को पूरा कराने का ही है जिसकी ऐसे देशों में बहुत कमी है। और यदि किसी समय उन्हें इन साधनों के उत्पन्न कराने की आवश्यकता हुई तो वह तो बड़ी सरलता से हो सकेगा। जन साधारण के रहन सहन में विशेष कमी भी न करनी पड़ेगी। अधिक से अधिक रहन सहन की वृद्धि को थोड़े समय के लिये रोक देना होगा।

पिछड़े हुए देश

परन्तु पिछड़े हुए देशों के लिये जिनमें उद्योग धन्य पूरी तरह विकसित नहीं, इन प्रश्नों के निश्चय करने में अधिक कठिनाई पड़ती है। ऐसे देशों में या तो उद्योगिक उन्नति बहुत धीरे धीरे हो अथवा समाज अपनी माँगों के परमावश्यक पदार्थों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में प्रयाप्त कमी करे। तभी वह मशीनों व कारखानों इत्यादि को अधिक उपज के साधन बनाने में प्रयोग करा सकते हैं।

जैसा कि प्रायः सभी कामों में होता है इस उन्नति में भी प्रारम्भ में कठिनाई पड़ेगी । क्योंकि प्रारम्भिक काल में उपजाऊ शक्तियाँ ही कम होती हैं चाहे उनका प्रयोग माँगों के पूरा करने में हो चाहे साधन उत्पन्न करने में । स्थिति को संभालने के लिये ऐसे समय में यह ही आवश्यक होगा कि शक्तियों का अधिक प्रयोग पुरानी मशीनों को हटाकर उनके स्थान पर नई मशीनों के लाने में हो । चाहे जन साधारण को कुछ समय के लिये क्लेश ही क्यों न उठाना पड़े । अशिक्षित मजदूरों के स्थान पर शिक्षित और पुराने ढंग की मशीनों के स्थान में वर्तमान नए ढंग की उन्नति-शाली मशीनें ही रखना पड़ेगी । अन्यथा उपज दिन प्रति दिन घटती ही जावेगी और देशवासियों को क्षणिक सुख के बदले निरन्तर कष्ट ही भोगना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में उपजाऊ शक्तियों का अधिकतर प्रयोग साधनों को उत्पन्न अथवा प्राप्त कराने में ही होना लाभदायक होगा ताकि उनके द्वारा जनता की माँगों के आवश्यक पदार्थ अधिक संख्या में कम मूल्य पर प्राप्त हो सके । पिछले उदाहरण में पुरानी लोहे की मशीनों से छोटे छोटे घर अथवा बड़ी बड़ी अट्टालिकायें न बनवाकर लोहा इत्यादि बनाने की मशीनें बनाई जावेगी । जो थोड़े बहुत इन्जीनियर (विशेषज्ञ) हों उन्हें उद्योग-शालों से हटाकर विद्यार्थियों को शिक्षित करने का काम सौंपा जावे ताकि ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यक संख्या पूरी हो । ' रेल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जनता की माँगों के पदार्थ न भेज कर' ऐसी कले इत्यादि के बनाने की सामग्री भेजी जायगी ।

रूस का उदाहरण

पुराने पिछले देशों में रूस (Russia) एक जीता जागता उदाहरण है । यहाँ के योजना निर्माताओं को समय २ पर ऐसी ही कठिनाईओं का सामान पड़ा । और वास्तवमें यही ही इस प्रकार की योजना बनो भी है । साधन अथवा पदार्थ के अनुपात का प्रश्न सदैव उनके सामने रहा । एक ओर तो जनता के स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान कि कहीं पदार्थों की कमी से देश वासी भूखे और नङ्गे न रहे

दूसरी ओर राजनैतिक और पर राष्ट्रीय आर्थिक विचार विवश करते थे कि शीघ्राति शीघ्र देशकी उद्योगिक उन्नति हो । ताकि कहीं विदेशियों के हस्तक्षेप से सामाजिक संगठन ही नष्ट भूट न हो जावे । सामग्री तथा शक्ति कम थी परन्तु तो भी उनका प्रयोग, सर्वप्रथम उद्योगिक उन्नति में हो करना पड़ा । प्रारम्भ मे इस नीति से क्लेश भी हुआ । परन्तु धीरे २ ज्यो २ उन्नति होती गई, इस प्रकार के क्लेश से छुटकारा मिलता गया यहाँ तक कि सन् १९३५ ई० मे उनके पास शक्तियाँ बच रहीं । जिनका वे किसी प्रकार प्रयोग न कर सकते थे ।

एक बड़ा भ्रम

परन्तु इस सम्बन्ध में भी कुछ मनुष्यों को ऐसा भ्रम है कि उद्योगिक उन्नति हो जाने पर समाजवादी संगठन में भी उपज के बटवारे इत्यादि में वे ही कठिनाइयाँ पड़ेगी जो पूँजीवाद में ।

पूँजीवाद में प्रायः ऐसा देखा गया है कि बने हुए पदार्थ जनता तक पहुँच नहीं पाते । उनके बिना ही रहना पड़ता है । कुछ अवसरों पर तो बने हुए पदार्थों का बटवारा करने के स्थान पर उन्हें नष्ट भी कर दिया जाता है । वे जला दिये जाते हैं । ऐसे मत वालों का कहना है कि रूस में भी उद्योगिक उन्नति हो जाने पर आवश्यक पदार्थ अधिक संख्या में बनेंगे । वहाँ भी पदार्थों की अधिकता होगी बेकारी बढ़ेगी, और उन्हें भी गेड़, कपड़ा, इत्यादि आवश्यक पदार्थ जलाना पड़ेगा तथा जनता उनके बिना तंगी और भूखी मरेगी ।

परन्तु ऐसे मतदाता यह भूल जाते हैं कि बने हुए पदार्थों का बटवारा न हो सकने का कारण यह नहीं है कि ऐसे पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच नहीं सकते अथवा जन साधारण तक पहुँचाए नहीं जा सकते । वरन वास्तविक कारण यह है कि लाभ के साथ इनकी विक्री नहीं हो पाती । दूसरे शब्दों मे पदार्थों की अधिक संख्या में उपज होने से उनका क्रय मूल्य घट जाता है । और उन्हें बनाने वालों को उन पदार्थों के बेचने में उतना लाभ नहीं होता ।

इसी कारण वे या तो अधिक संख्या में इस प्रकार के पदार्थ बनाते ही नहीं और यदि बन जाते हैं तो उन्हें नष्ट कर देते हैं। पदार्थों का ठीक बटवारा न हो सकना, इस प्रकार के आर्थिक संगठन का ही परिणाम है जो समाजवादी ढंग में हो ही नहीं सकता।

एक स्थान से दूसरे स्थान न पहुँच सकने के कारण भले ही कुछ पदार्थ जनता के पास पहुँचने से रुक जावे, परन्तु उपज की अधिकता के कारण, यह नहीं हो सकता, समाजवादी संगठन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पदार्थ अधिक संख्या में हो उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के साधन भी प्रयाप्त हो, परन्तु तौ भी, जनता को उनके बिना ही रहना पड़े। ऐसा तो पूँजीवाद ही में है जहाँ लाभ ही मुख्य आधार है और वे ही पदार्थ बनाए जाते हैं जिनकी विक्री से लाभ हो।

समाजवादी संगठन में अन्य कठिनाइयाँ भले ही हों, परन्तु उसमें पदार्थों की विक्री में कोई कठिनाई नहीं होती। बने हुए पदार्थ बिक सभी जाते हैं। केवल योजना निर्माताओं को यह ध्यान रखना पड़ेगा किसी वर्ष में बने हुए सब पदार्थ निश्चित मूल्य पर विक्री के लिये रहे, और जनता के पास प्रयाप्त धन हो। इस प्रकार सामाजिक संगठन में पदार्थों की विक्री की एक ही सीमा है। और वह है जनतक की वास्तविक माँग। यदि माँग ही नहीं है तब तो अवश्य वह पदार्थ बच रहेगा और अगले वर्ष उसको उपज कम करना होगा। परन्तु न तो उसका मूल्य ही घटेगा और न अन्य वस्तुओं का बढ़ेगा। जिनकी माँग अधिक है।

पूँजीवादी देशों की दशा

लगभग प्रत्येक पूँजीवादी देश को इस समय अपने देश की धनी वस्तुओं को बेचने के लिये विदेशी बाजार ढूँढ़ना पड़ रहे हैं। जहाँ वे लाभ के साथ उन पदार्थों को बेच सकें। इस लिये नहीं कि

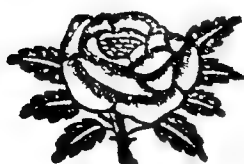
वहाँ के देश वासियों के पास प्रयाप्त संख्या में आवश्यक पदार्थ है और उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं। वरन् उनको उनके मूल्य देने की शक्ति नहीं और वे उनके बिना ही रहने को विवश होते हैं। प्रायः ऐसा भी किया जाता है कि किन्हीं पदार्थों का मूल्य अपने देश में बहुत अधिक कर दिया जाता है ताकि वे अन्य देशों में कम मूल्य पर बेचे जा सकें। और विदेश में उनकी विक्री से होने वाली हानि इस प्रकार देश वासियों से पूरी की जाती है मूल्य न दे सकने के कारण उनकी रहन सहन दिन प्रति दिन घटती जाती है। बड़े २ कारखानों में काम करने वाले सज़दूर छोटे छोटे कमरों में तीन तीन व चार २ एक साथ रहते हैं। उनके भोजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य का भी समुचित प्रबन्ध नहीं। बैचारे काम करनेवालों को संग आकर आये बिन हड़ताल इत्यादि करना पड़ता है।

इसके विपरीत समाजवादी संगठन वाले देश रूस में सबसे बड़ा प्रश्न देशवासियोंकी माँगों को पूरा करने का है।

जार के समय में रूस वासियों के पास केवल एक या एक से कम कमरे वाले घर थे और उन्हीं में अधिकतर जनता रहती थी। भोजन और कपड़े की सामग्री भी बहुत कम थी। शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रयाप्त न थीं मन अधिक अध्यापक थे और न डाक्टर ही। पुस्तकालयों तथा बाचनालयों का भी अभाव था।

संसार के ६ भाग के मनुष्यों को यह सब माँगें कैसे पूरी हों, रूस के योजना समिति के सामने यह एक बड़ी समस्या थी। देश की उद्योगिक उन्नति भी ऐसी न थी और न पूरी आवश्यक सामग्रियाँ ही प्राप्त थी। परन्तु तोभी वे निराश नहीं हुए और अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चलते रहे। जिसका परिणाम यह हुआ कि सन् १९३५ ई० में उनके पास आवश्यक पदार्थ की संख्या इतनी अधिक हो गई जितनी रूस के इतिहास में इसके पूर्व कभी भी न रही होगी। दूकानों से इन पदार्थों की अधिकता हुई। कार्ड रीति हटा कर फुटकर से विक्री का प्रबन्ध किया गया।

इस उन्नति का विशेष विवरण श्रीमती तथा श्रीमान सेड्ज़नी वेव की साम्यवादी रूस नई सभ्यता नामक पुस्तक (Soviet Communism. A new civilization by Mrs. and Mr. Sydney Webb) से मिलता है। उनका कहना है कि उद्योगिक उन्नति होने से सामाजिक संगठन में कठिनाइयाँ होंगी, यह एक भ्रम है और उसे दूर हो जाना चाहिए। देश को उपजाऊ शक्तियों को बढ़ाने से प्रारम्भ में लाभ, और उनके उन्नति हो जाने पर किसी देश को हानि हो, यह तो भ्रमात्मक तथा आश्चर्यजनक बात है। परन्तु तब भी किन्हीं भागों में उद्योगिक उन्नति के प्रारम्भिक काल में पूँजीवादी संगठन अधिक उपयुक्त रहता है क्योंकि उससे उपज के साधनों की उन्नति के साथ साथ, वैयक्तिक परिश्रम से पूँजीपति पदार्थ अधिक संख्या में उत्पन्न कर लेते हैं। परन्तु उसके पश्चात् समाजवादी संगठन उससे भी अधिक आवश्यक है क्योंकि पदार्थ उत्पन्न हो जाने पर देशवासियों को बने पदार्थों का भोग भी मिलना चाहिए। जो पूँजीवाद में भोजी प्रकार नहीं हो पाता और जिसके लिए समाजवाद विशेष उपयुक्त है। इसी कारण उद्योगिक उन्नति भले ही प्रारम्भ में पूँजीवाद के आधार पर हो और ऐसा होने में थोड़ी सुविधा भी है। परन्तु ऐसी उन्नति हो जाने पर जब कि पदार्थ प्रयाप्त संख्या में उत्पन्न हो सकने हैं समाजवादी संगठन अत्यन्त आवश्यक है और उसके बिना देशवासी तथा समाज सुखी रह ही नहीं सकता।



प्रचलित समाजवादी ढंग

रूस का इतिहास

समाजवादी संगठन के भली भाँति चल सकने का अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण रूस के उदाहरण से मिलता है। जहाँ लगभग १० वर्ष से इस प्रकार का संगठन चल रहा है और करोड़ों दैशवासी इस आधार पर रहकर अपने जीवन सुख पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। रूस में किस प्रकार कार्य चलता है, इसका जानना और समझना इस समय अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि यदि रूस में इस प्रकार का प्रयत्न सफल होता है तो न केवल संसार की बढ़ती हुई बेकारी और व्यापारिक उथल पुथल से होनेवाली समाज की दुर्दशा ही रोकी जा सकती है, वरन् इससे जन समाज की सम्पूर्ण शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग भी हो सकेगा और प्रत्येक दैशवासी की आय तथा रहन सहन में पर्याप्त वृद्धि हो जावेगी। संक्षेप में संसार को कठिनाइयाँ और क्लेश दूर करने का सरल उपाय मिल जाता है। अब देखना यह है कि ऐसा संगठन क्या सदैव स्थिर रह सकता है ?

पूँजीवादी नीतिज्ञों का यह कहना है, कि भले ही किन्हीं कारणों से इस समय थोड़ी सफलता रूस में हो गई हो। परन्तु ऐसा संगठन बहुत दिनों चल ही नहीं सकता और अन्त में फिर पूँजीवाद के ही आधार पर संसार को चलना पड़ेगा। देखें, कहाँ तक उनका कहना ठीक है ?

प्राचीन इतिहास

कई कारणों से १९२८ ई० तक सोवियट रूस का आर्थिक संगठन नियमित उपज के आधार पर किया हो नहीं जा सकता। इस ओर सब से पहिला काम उस समय से प्रारम्भ होता है जब कि सोवियट रूस में प्रत्येक संस्था से शासन योजना समिति को गत वर्ष की उपज, सामग्री की खपत, मजदूरों की संख्या इत्यादिक सम्पूर्ण सूचना भेजने को कहा गया, और अगले वर्ष की प्रस्तावित उपज के सम्बन्ध में आवश्यक आकड़े माँगे गये। केन्द्रीय समिति के पास इस प्रकार के आंकड़े जमा होना ही संगठन का प्रथम पद है। नियंत्रित उपज की व्यवस्था के लिए यह परमावश्यक भी है।

ऐसे असंख्य आकड़ों का पूरा प्रयोग करने और उसकी जांच व छांट करने के लिए एक विस्तृत प्रबन्ध की आवश्यकता थी। समिति के पास इस प्रकार के सहस्रों आंकड़े आए और सम्भवतः इसी कारण सन् १९२८ ई० के पूर्व सोवियट रूस में इस प्रकार की नियमित उपज की योजना नहीं बनाई जा सकी। परन्तु तो भी इस वर्ष रूस को शासन योजना समिति जो गोझप्लान (Goz plan) के नाम से विख्यात हैं, संसार के आवश्यक तथा विस्तृत आकड़ों का मुख्य केन्द्र हो गई थी।

योजना का काम

आंकड़े जमा हो जाने पर, योजना का काम प्रारम्भ हुआ। बहुतों का ऐसा विचार है कि समाजवादी संगठन में महत्व पूर्ण आर्थिक विषयों का निर्णय शासन योजना समिति स्वयं ही मनमाने कर देती है। परन्तु वैसा है नहीं, इन निर्णयों में उपज की संस्थाओं को विवश तो नहीं किया जाता। परन्तु प्रायः सभी महत्व पूर्ण विषयों पर उनकी राय ली जाती है। अगले वर्ष उपज कितनी हो, उसके लिए किन किन सामग्री को आवश्यकता होगी इन प्रश्नों के उत्तर पर ही योजना का

ढाँचा बनता है। ढाँचा केवल एक व्यक्ति अथवा संस्था के उत्तर पर ही आश्रित नहीं रहता वरन् लगभग देश को प्रत्येक ऐसी संस्था के उत्तर पर जिनके द्वारा पदार्थ इत्यादि बनते हैं। और वह भी उनके गत वर्ष के आधार पर—

परन्तु इस पर भी हो सकता है कि ढाँचे में त्रुटियाँ रह जावें। और ऐसा हो जाता है। किसी विशेष धन्धे में नियत संख्या से अधिक सामग्री हो जावे। अथवा किसी एक ही धन्धे में भिन्न-भिन्न पदार्थों को सामाहिक माँग उस धन्धे के लिए निश्चित संख्या से कभी बढ़ भी जाती है। और इसी कारण योजना समिति को यह ढाँचा ठीक और नियमानुसार बनाना पड़ता है। वे जाँच करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की माँग उसकी निश्चित संख्या के बराबर रहे।

आवश्यक पदार्थों की उपज निश्चित संख्या के बराबर रखना और उसे नियमानुसार सम्बन्धित करना जन साधारण की आवश्यक माँग को पूरा कराने के लिये प्रथम कार्य है और ऐसा हो जाने पर एक निश्चित ढाँचा बन जाता है। यह ढाँचा उपज संस्थाओं द्वारा ही बनता है।

उपज सहयोगी समितियाँ

यह उपज की संस्थायें कौन सी हैं। यह जानना आवश्यक है क्योंकि समाजवादी संगठन के यह एक विशेष अंग है। ऐसी संस्थायें विशेषतया तीन भागों में विभाजित की जा सकती हैं:—

(१) सरकारी: इनमें सीधी सरकारी व म्युनिसिपल बोर्ड की संस्थायें हैं। उद्योग धन्धों में विशेष कर ऐसी ही संस्थायें अधिक हैं और लगभग ६६० प्रति शत उपज उन्हीं के द्वारा होती हैं।

(२) जन सहयोगी समितियाँ (Consumers Cooperative Societies) यह समितियाँ ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी योरुप के देशों की समितियों की ही भाँति हैं। अन्तर केवल इतना है कि रूस की

समितियों में सदस्यों के पदार्थों की विक्री पर कमीशन धन के रूप में नहीं दिया जाता । ऐसी संस्थाओं का मुख्य कार्य उत्पन्न पदार्थों का बटवारा अथवा फुटकर विक्री ही रहता है । पदार्थ के उपज में इनका काम नहीं के समान ही है । ब्रूटेन तथा अन्य पूँजीवादी देशों में यह संस्थाएँ उपज के क्षेत्र में भी पहुँच गई हैं । और उसमें भी अपना ही आधिपत्य रखना चाहती हैं ।

(३) तीसरे प्रकार की संस्थाएँ उपज सहयोगी समितियाँ (Producer Cooperative Societies) हैं । यह स्वयं कार्य-कर्ताओं की समितियाँ हैं जो अपना एक दल बनाकर उपज के साधन और सामग्रियों का स्वामित्व करते हैं । वे सरकारी कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की तरह केवल वेतन पर ही काम नहीं करते । इन कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिलता वरन् उसके स्थान पर कमीशन अथवा लाभ का एक भाग मिलता है । जो उसके सदस्यों के काम की विक्री से प्राप्त होता है और ,उत्पन्न हुए पदार्थों की विक्री का एक भाग होता है । उन्हें वेतन क्यों मिले क्योंकि वे तो स्वयं अपने स्वामी होते हैं किसी के नौकर नहीं ।

ऐसी संस्थाएँ विशेष कर कृषि धन्य है । बाल्टिक सागर (Baltic Sea) से पैसिफिक महा सागर (Pacific Ocean) तक के लम्बे चौड़े मैदान के सामूहिक खेत (Collective farm) इन्हीं समितियों के आधीन हैं । परन्तु इन संस्थाओं का काम कृषि पर ही सीमित नहीं । अन्य उद्योग धन्यों में भी इनके काम का महत्व है । कारीगर सहयोगी समिति (Artisans Cooperative Society) के भी सदस्य हैं । जो छोटे छोटे घरेलू धन्यों और पदार्थों को बनाती हैं ।

परन्तु इससे यह भी न समझना चाहिए कि कृषि व्यवसाय का पूरा पूरा आधिपत्य (monopoly) इन्हीं संस्थाओं में है । इनके अतिरिक्त लगभग १०,००० सामूहिक क्षेत्र सीधे सरकार के आधिपत्य में

भी हैं जिनमें मजदूर ठोक उसी प्रकार वेतन पर काम करते हैं जैसे किसी कार्यालय में ।

यह उपज सहयोगी समितियाँ ऐसी आर्थिक संस्थाएँ हैं जो पूँजीवाद के समय के अन्त से हो रूस में स्थापित है और बराबर काम करती है । इन्हे स्थापित हुए लगभग २० वर्ष से अधिक व्यतीत हो गये परन्तु केवल छः वर्षों से देश के आर्थिक जीवन में उनका विशेष महत्व रहा है । इस बीच में लगभग ढाई लाख सामूहिक खेत सहयोग उपज के आधार पर बन गये थे । परन्तु उन पर काम होना तो बहुत बाद में हो प्रारम्भ हुआ और इस प्रकार एक पुराना रिवाज फिर से चालू हुआ है ।

मजदूरों का एक दल स्वयं उपज के साधनों का स्वामी हो, उस पर पूरा आधिपत्य रखे, उनके द्वारा जन साधारण की मांगों के पदार्थ बनावे, तथा उन्हें बेचकर बिक्री के मूल्य का परस्पर बटवारा कर ले, ऐसा ही उद्देश्य प्रारम्भ में पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी समाजवादियों का रहा है ।

१६ वीं शताब्दी में बृटेन, फ्रांस, अमेरिका इत्यादिक सभी देशों में इस प्रकार की संस्थाओं और समितियों को स्थापित करने की चेष्टा की गई । परन्तु उन्हें इस कार्य में विशेष सफलता नहीं मिली और मजदूर इस ढंग से पूँजीवाद से छुटकारा पाने से निराश हो ही गये । अपना स्वयं संगठन करके पूँजीवाद से मुक्त हो सकेंगे ऐसी उन्हें आशा न रही थी । परन्तु रूस के उदाहरण ने उन्हें फिर स्वयं संगठन की सार्थता का विश्वास दिलाया । उनका उद्देश्य ठोक है । वे भली भाँति चल भी सकती हैं ।

परन्तु उनके सुचारु रूप से चलने के लिये समाजवादी वातावरण की आवश्यकता है । पुराने समाजवादी नेता जिन्होंने प्रारम्भ में ऐसी स्वतन्त्र सहयोगी समितियाँ स्थापित करने की चेष्टा की थी, उन की धारणा में तो कोई त्रुटि नहीं । केवल उनका ऐसा विचार

था कि सम्भवतः ऐसी समितियाँ पूँजीवादी वातावरण तथा पूँजीवादियों के हाथ में शासन की वागडोर रहते हुये भी चल सकती है। सहयोगी संस्थाओं के भली भाँति कार्य करने के लिये यह आवश्यक है ही भ्रम पूर्ण था कि देश के बड़े बड़े उद्योग धन्धे समाजवादी ढंग पर संगठित हों। और राजनैतिक अथवा आर्थिक कोई भी वागडोर पूँजीपतियों के हाथ में न रहे। समाजवादी वातावरण के अभाव से निस्संदेह इनके काम में कठिनाइयाँ पड़ेगी।

योजना समिति का काम

शासन योजना समिति का यही काम है कि वह इन आर्थिक संस्थाओं के कार्य और उनकी माँगों को नियमित करे। इनके निर्णयों की जाँच करे तथा शासन द्वारा बनाई गई योजनासे उनका मिलान करे। शासन को आर्थिक समस्याओं के साथ अन्य कामों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उनके सन्मुख देश के धन की वृद्धि के अतिरिक्त अन्य जटिल समस्याएँ और भी रहती हैं जैसे देश की रक्षा इत्यादि। देश के चारों ओर पूँजीवादी वातावरण रहने से रूस को सततर उन देशों से अपनी रक्षा की चिन्ता रहती है, और इसी कारण योजना समिति को आर्थिक संगठन के साथ ही साथ रक्षा की सामग्री बनवाने के प्रबन्ध का भी ध्यान रखना पड़ता है। सहयोगी समितियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावित योजना में अन्य विचारों के कारण आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता होती है। देश की सभ्यता और रहन सहन की वृद्धि का भी विचार रहता है ताकि देशवासियों को आवश्यक पदार्थों के अभाव से कष्ट न भेलना पड़े। विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि का समुचित प्रबन्ध, डाक्टर, औषधालय, परीक्षा के यन्त्र इत्यादि स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य पदार्थ, और सबसे अधिक इस बात का ध्यान कि अगले वर्ष उपज के साधन बनाने वाले धन्धों की वृद्धि।

शासन का मत मिल जाने पर प्रारम्भिक योजना बन जाती है। परन्तु रूस की केन्द्रीय समिति उसे ही स्वीकार नहीं कर लेती और न

उस के अनुसार आदेश ही देती है। यह प्रारम्भिक योजना शासन के प्रत्येक विभाग को भेज दी जाती है और वे उसे सम्बन्धित उपज की संस्थाओं के पास विचारार्थ भेज देने हैं। इस काम के लिये योजना कई भागों में विभाजित की जाती है। और प्रत्येक विभाग अपने अपने विषय की विस्तारपूर्वक गम्भीरता से आलोचना करता है। केवल यह ही नहीं कि उसकी जाँच कार्यालयों में काम करने वाले अथवा आकड़ों का ज्ञान रखने वाले ही करते हों वरन यह योजना सब हाथ और मास्तिष्क से काम करने वाले मजदूरों को दिखाई जाती है। कार्यकरताओं के सम्मेलनों में उसपर वाद विवाद होता है तथा उसके फलस्वरूप योजना में आवश्यक संशोधन कर दिये जाते हैं।

ऐसे संशोधनों और सुधारों के साथ यह योजना दोबारा शासन योजना समिति के पास भेजी जाती है ताकि और वे एक बार फिर सब बातों को जाँच लें। कोई परस्पर विरोधी संशोधन न रहे।

इस सब जाँच का परिणाम ही निश्चित और अन्तिम योजना के रूप में आता है। इसके पश्चात् यह योजना जनता के चुने प्रतिनिधियों की कौंसिल और सोवियटरूस को केन्द्रीय कार्यकारिणी के सम्मुख रखी जाती है जोकि रूस का मंत्रिमण्डल व्यवस्थापिका सभा, अथवा काँग्रेस है। उसके द्वारा स्वीकार हो जाने पर यह देश का नियम हो जाता है।

व्यक्तिगत स्वामित्व तथा उपज में लाभ और परस्पर प्रतिद्वन्दता के आधार का अन्त हो जाने पर ऐसे निश्चित आदेशों की आवश्यकता हो ही जाती है कि किस किस संख्या में किस किस पदार्थ को बनाना है। ऐसे ही आदेश निश्चित योजना के संगठन में दिये जाते हैं। और वे ही सरकारी नियम हो जाते हैं। परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है यह नियम सरकार अपने मनमाने नहीं बना देती वरन स्वयं उपज की संस्थाएँ अपने प्रस्तावों द्वारा इसे प्रास्तावित करती हैं और

शासन द्वारा स्वीकार हो जाने पर उन्हीं के अनुसार काम भी किया जाता है ।

योजना पर काम

सरकारी संस्थाओं में तो ऐसे आदेशों के अनुसार काम होना सरलता से सम्भव हो आ जाता है परन्तु सहयोगी समितियों में इन आदेशों के द्वारा काम कैसे सम्भव होता है ऐसा भ्रम हो सकता है । क्योंकि उपज के साधनों पर स्वयं स्वामित्व रखने वाले कारीगर शासन योजना समिति के आदेशों को अस्वीकार भी कर सकते हैं । वैसे यह बात प्रत्यक्षतया ठीक भी जँचती है । परन्तु वास्तव में ऐसी स्थिति होती नहीं । प्रथम तो उपज के क्षेत्र में ऐसी समितियाँ हैं ही बहुत कम और फिर जो हैं वे अधिकतर सरकारी संस्थाओं पर ही आश्रित रहती हैं । इस कारण इस क्षेत्र में तो इस प्रश्न का अधिक महत्व नहीं । परन्तु कृषि व्यवसाय में अवश्य ऐसी समितियों की संख्या अधिक है और उपज का एक बड़ा भाग इसके द्वारा विकला है । बाजारों में भाव तब करने वाले रहते ही हैं और वे शासन द्वारा निर्धारित योजना तथा निश्चित मूल्य पर पदार्थ को मोल लेना अस्वीकार भी कर सकते हैं । निश्चित संख्या में, पदार्थ बनाने को भी वे वाद्य नहीं किये जा सकते । लाभ तथा अधिक मूल्य का लोभ उन्हें ऐसा करने को प्रोत्साहित भी कर सकता है । परन्तु समिति तथा शासन भी अनेक ढंग से उन पर प्रभाव डाल सकती है । कर का बोझ हटाना अथवा हल्का करना सरकारी संस्थाओं को ऐसे आदेश देना कि, अमुक अमुक पदार्थों के लिये अमुक २ मूल्य ही दिया जावे, उद्योगधन्धों के उन पदार्थों की संख्या व मूल्य बढ़ा देना जो अधिकतर देहाती मोल लेते हों इत्यादि । क्योंकि इन्हीं पदार्थों के लोभ में ही तो वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाते हैं तथा उते बेचते हैं । इन पदार्थों के मूल्य बढ़ जाने पर उन्हें अधिक अनाज उपजाने अथवा शासन द्वारा निर्धारित योजना के प्रतिकूल काम करने को कोई-उत्साह ही नहीं होगा और न वे ऐसा

करेंगे हो । इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक संस्थाओं और कारीगरों के परस्पर मिलने से बहुत से पदार्थों और सेवाओं का बटवारा स्वयं ही होजाता है । शासन समिति को उसमें हस्तक्षेप करना ही नहीं पड़ता । यह संस्थाएँ स्वयं भी अपने २ बने पदार्थों का अदल बदल (Exchange) कर लेती हैं जिससे इनके बटवारे की आवश्यकता ही नहीं रहती । परन्तु तो यह सब उपाय इन संस्थाओं को प्रभावित मात्र ही कर सकते हैं । उनका कोई सीधा आधिपत्य नहीं होता वे अधिकतर स्वतंत्र ही रहते हैं ।

दूसरे प्रकार का संगठन

समाजवादी संगठन ऐसा हो सकता है, अथवा विचार किया जा सकता है, जिसमें सब उद्योग धन्धों का आधिपत्य सीधे शासन के ही हाथ में रहे और इन धन्धों में काम करनेवाले सब के सब एक स्वामी (शासन) के सवैतनिक मजदूर हों । ऐसे समाज में, सब बने पदार्थों का स्वामी शासन होगा और वह ही उन्हें वेतन के बदले में सब कार्यकर्ताओं को बाँटेगा । इस संगठन में वेतन के रुपये के स्थान में एक निश्चित संख्या में पदार्थ लेने का परचा शासन द्वारा प्रत्येक काम करने वाले को दिया जावेगा और इस प्रकार अदल बदल (Exchange) का काम ही न रहेगा ।

पूँजीवाद के समर्थक, समाजवादी संगठन का यही एक चित्र खींचा करते हैं । परन्तु ऐसे संगठन में गुण अथवा अवगुण जा कुछ भी हों, वह प्रचलित समाजवादी अथवा सोवियट रूस का संगठन नहीं है ।

रूस में बहुत सी पदार्थ उत्पन्न करने वाली संस्थाएँ शासन के आधीन नहीं वरन् स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने सदस्यों के सहयोग काम करती हैं । उपज का एक बड़ा भाग बैचा तथा मोल लिया जाता है । संस्थाएँ तथा व्यक्तिगत कारीगर अपने काम और बने हुए पदार्थों की परस्पर अदला-बदली भी कर लेते हैं । सरकारी संस्थाएँ भी, परस्पर तथा सहयोगी समितियों से काम और पदार्थों

की अदला बदली करती हैं। इसके अतिरिक्त यह दोनों ही अपने २ पदार्थों को बेचने के लिये दूकानों इत्यादि का प्रबन्ध करती है। जन साधारण से इस प्रकार संपर्क भी रहता है। और लगातार विक्री व मोल चलता है तथा शासन के मध्यस्थ हुए बिना ही, पदार्थ उत्पन्न करने वालों के पास से प्रयोग करने वाली जनता के पास पहुँच जाते हैं।

पूँजीवाद से अन्तर

ऐसे समाजवादी और पूँजीवादी व्यापार में क्या अन्तर है, इस स्थान पर पूर्ण रूप से तो नहीं बताया जा सकता परन्तु इतना तो अवश्य है कि समाजवादी संगठन में कहीं पर भी किसी व्यक्ति अथवा दल को लाभ पहुँचाने के लिये सवैतनिक मजदूर नहीं रक्खे जाते। और न कोई पदार्थ अधिक लाभ के साथ दोबारा बेचने के लिये मोल हो लिया जाता है जैसा पूँजीवाद में विशेषतया होता है।

काम के ऐसे बटवारे से स्पष्टतया लाभ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणामों का वर्णन करते हुए सन् १९३३ ई० में अपने व्याख्यान में स्वयं स्टैलिन (Stalin) ने कहा था। सरकारी तथा ऐसी सहयोगी समितियों में परस्पर व्यापार, पदार्थों व सेवाओं के अदल बदल के बिना, रूस का आर्थिक संगठन चल ही नहीं सकेगा। रूस के व्यापार की उन्नति एक गम्भीर समस्या है जिसे सुलझाए बिना भविष्य में उन्नति ही असम्भव है।

गत वर्षों में इन संस्थाओं, समितियों तथा कारीगरों में परस्पर काफ़ी व्यापार रहा। कभी कभी तो इसके कारण योजना समिति को भी कठिनाई पड़ी है। क्रय तथा विक्रय चलने रहने पर रुपये का काम रहता ही है और वह न केवल वेतन देने के लिये ही वरन्, पदार्थों की अदला बदली भी उसके द्वारा होती है। पदार्थों के मूल्य भी इसीपर निश्चित किये जाते हैं। संक्षेप में पृथक् पृथक् आर्थिक संस्थाओं और उनके कार्यों को वश में रखना, तथा उन सब का आधार लेकर केन्द्रीय योजना बनाना कुछ कम कठिन काम नहीं।

योजना की सफलता

अस्तु, सोवियट रूस में उपज और उसका अनुपात पूर्णतया योजना समिति के आधीन रहता है और वह ही निश्चय करती है कि कौन कौन से पदार्थ बनें और किस किस संख्या में।

अब केवल यह रह जाता है कि यह संगठन सफल हुआ है अथवा हो सकता है या नहीं ? प्रश्न बादग्रस्त है परन्तु तो भी यह तो निश्चय ही है कि ऐसा समाजवादी संगठन लगभग १० वर्षों से चल रहा है और दिन प्रति दिन इतकी उन्नति ही होती जाती है। अनुभव भी ऐसा ही है कि इसमें सफलता मिली है। इन वर्षों में सोवियट रूस के उपज की जितनी वृद्धि हुई है उसके पूरे पूरे आँकड़े तो नहीं परन्तु तो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणामों के सिंहावलोकन से, जो १९३२ ई० में पूर्ण हुई, चेष्टा की सफलता का कुछ अनुमान अवश्य हो जाता है।

उद्योग धन्धों की उपज सन् १९२८ ई० में केवल १५.७ अरब थी सन् १९३२ ई० वह ३४.३ अरब हो गई जिससे २१८.५ प्रतिशत वृद्धि का पता लगता है। सन् १९३२ ई० में उपजकी संख्या युद्ध के पूर्व से तिगुनी और सन् १९२८ ई० से द्विगुनी हो गई थी। पंचवर्षीय योजना का ८३.७ प्रतिशत काम केवल ४ वर्ष और ३ महीने ही में पूरा हो गया था, जब कि पूँजीवादी देशों में दशा इसके विपरीत ही थी। वहाँ उपज लगभग उतनी ही तेजी से घट रही थी जितनी कि रूस में बढ़ती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो तीन वर्षों में इसमें और भी अधिक वृद्धि हुई। परन्तु, इस समय अन्य देशों में भी उपज बढ़ रही थी और इस कारण उसका पूरा पूरा मिलान नहीं हो सकता।

सफलता का प्रमाण

उन्नति का इससे भी स्पष्ट ज्ञान देशवासियों की रहन सहन और उन्हें प्राप्त पदार्थों से लगता है। संगठन से पूर्व और इस समय की दशा की तुलना करने से वास्तविक अन्तर का पता लगता है। परन्तु

इतने पर भी पूँजीवादी नीतिज्ञ इसे स्वप्न ही को तुलना देते हैं। पूँजीवाद को वे एक प्रकार का संगठन न समझकर प्राकृतिक नियम ही समझे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि रूस में अब भी तो पदार्थों की काफ़ी कमी है। और कुछ पदार्थों की संख्या तो विल्कुल ही कम है।

उनका कहना यह ठीक अवश्य है। रूसवासियों को कुछ पदार्थ कम मिल पाते हैं। परन्तु इसका कारण उपज की कमी नहीं वरन् मांगों की अधिकता है। पदार्थों की संख्या तो पहले से कहीं अधिक हो गई है। परन्तु उसके साथ साथ उनकी मांगों में उससे भी अधिक वृद्धि हुई है। समाजवादी संगठन का यह एक अवगुण होने के बजाय गुण ही है कि इस संगठन द्वारा जनता को रहन सहन और आवश्यक पदार्थों की मांग में इतनी बढ़ती हो जावे और वे दिन प्रति दिन बढ़ती ही जावे। पदार्थों की कमी के दो ही कारण हो सकते हैं। उपज में घटो, अथवा मांग में बढ़ती। किसी पदार्थ की कमी उसकी उपज घट जाने अथवा मांग बढ़ जाने से भी होती है। रूस की स्थिति इस समय ऐसी ही है। पदार्थों की मांग बढ़ती जाती है। समाजवादी संगठन से देशवासियों की क्रय शक्ति इतनी बढ़ गई है कि उपज बढ़ने पर भी उन्हें वे कम ही दीखते हैं।

क्रय शक्ति की वृद्धि के साथ, देशवासियों के रहन सहन में काफ़ी अन्तर पड़ा है। पहले रूसवासी यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके लिये भी यह सब पदार्थ रखना सम्भव हो सकता है।

क्रय शक्ति की वृद्धि से उन्हें नवीन नवीन पदार्थों की इच्छा हुई। और वे उनके अभाव को पदार्थों की कमी समझने लगे। जूतों का ही उदाहरण ले लीजिए। सन् १९१३ ई० में रूस में जूने १/२५ या १/२० जोड़े प्रति मनुष्य प्रति वर्ष बन पाते थे। सन् १९३३ ई० में यह अनुपात १।२ जोड़ा प्रति मनुष्य प्रति वर्ष तक पहुँच गया अर्थात् १० गुनी वृद्धि हुई परन्तु तो भी रूसवासियों को जूते की कमी रही। पहले तो वे समझते ही नहीं थे कि जूते पहन भी सकते हैं। परन्तु अब लगभग प्रत्येक देशवासी जूता पहनना चाहता है और इसी कारण १० गुनी वृद्धि होने पर भी उन्हें पदार्थों की कमी है।

परन्तु यह स्व हुआ कैसे । समाजवाद द्वारा ही तो समाजवाद ने इस प्रकार व्यर्थ उपज, और बेकारी दोनों का ही अन्त कर दिया । समाज को क्रय शक्ति बढ़ाने से ही तो यह सम्भव हो सका ।

तभी तो बने हुए सब पदार्थ बिक सकें ।

पूँजीवादियों के तर्क

अब थोड़ा सा उन अर्थ शास्त्रज्ञों के विचारों पर भी ध्यान दें जो सदैव यहो कहा करते हैं कि इस प्रकार का संगठन हो ही नहीं सकता । मिस्टर वेब के शब्दों में वे लोग तो नियमित उपज से प्राप्त सफलता का खण्डन करने की भी आवश्यकता नहीं समझते क्योंकि उनके विज्ञान के अनुसार जो इस प्रकार की सफलता होना ही असम्भव है। प्रोफ़ेसर लुडविग (Professor Ludwig Von Mises) ने तो इसी विषय पर ५०० पृष्ठों की एक पुस्तक तक लिख डाली । और उसमें समाजवादी संगठन हो सकने की सम्भावना ही पर आघात किया है । आश्चर्य की बात तो यह है कि उसमें कहीं पर भी रूस में इस प्रकार प्रचलित संगठन का उल्लेख तक नहीं है ।

इन लेखकों की ऐसी पुस्तकों के कारण ही पूँजीवादी तर्कों पर भी विचार करना पड़ा । वे तो पूँजीवाद को एक पूर्ण वस्तु ही मानते हैं और जो कहीं पर कोई त्रुटि अथवा कमी दिखाई जाती है उसका कारण वे पूँजीवाद के रीढ़ान्त से हटना ही बताते हैं । उनका तर्क यह है कि बाजारों में पदार्थों की विक्री व मोल एक प्रकार का स्थाई चुनाव है जिसमें जनता स्वयं चुन लेती है कि कौन २ से पदार्थ बनाए जावें । यह तर्क ठीक भी हो सकता था यदि सब मनुष्यों को भाव ताव करने की समान शक्ति होती । परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं और इस कथित चुनाव में कुछ मत दाताओं के अन्य मनुष्यों से ४०,००० तक अधिक मत रहते हैं ।

(अमेरिका और ब्रटेन में सबसे धनी और निर्धन मनुष्य की आय में लगभग इतना ही अन्तर है)

नियमित उपज के सम्बन्ध में तो उनका कहना है कि यह इतना भद्दा है कि इस पर काम हो ही नहीं सकता। ऐसी योजना देश को उपजाऊ शक्तियों का पूरा २ प्रयोग कर सकेगी, इसे भी वे स्वीकार नहीं करते। लण्डन विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर राबिन्स (Professor Robbins) ने लिखा है कि उपयुक्त संगठन के लिये आवश्यक है कि उपज के साधन प्राकृतिक पैदावार मजदूर और पूँजी (Land, labour and capital) का इस प्रकार बटवारा हो कि बने हुए किसी भी पदार्थ का मूल्य (utility) किसी अन्य पदार्थ से कम न हो। मूल्य से उनका तात्पर्य, मनुष्यों की माँगों को पूरा करने की योग्यता से है। अन्य शब्दों में कोई भी पदार्थ ऐसे न बने जो जनता के लिये उतने उपयोगी न हो जितने कि उनके स्थान पर बनने वाले अन्य पदार्थ। संक्षेप में, योजना सर्माति से कोई त्रुटि ही न हो। नियमित उपज के संगठन को पूँजीवाद के समान भी न समझकर वे उसे नीचे श्रेणी का संगठन कहते हैं। शास्त्र के हस्तक्षेप के कारण ही त्रुटि होती है ऐसा उनका विचार है।

प्रोफ़ेसर महोदय का तो तर्क ही निराला है। उनका ऐसा विचार क्यों है, और किन आधारों पर वे ऐसे परिणामों पर पहुँचे हैं, इसका वे उल्लेख ही नहीं करते।

समाजवाद से तुलना

वास्तव में नियमित उपज और पूँजीवादी त्रुटियों में विशेष भिन्नता है। योजना की त्रुटियाँ तो उपज के ढंग को नियमानुसार कराने में अकस्मात् ही रह जाती हैं। परन्तु पूँजीवाद में उपज की दुर्दशा तो सम्भवतः कही त्रुटि कही नहीं जा सकती। उस में उपज को नियमित करने वालों का तो कोई दोष है नहीं। वे तो प्राकृतिक संकटों के समान हैं। जिसमें मनुष्य का कोई बस नहीं चलता। उपज लाभ के आधार पर होती है तथा उपज और माँग का सम्बन्ध, अकस्मात् स्वयं ही हो जाता है। वह किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में तो रहता नहीं। इसी प्रकार उपज की रोक थाम भी आप ही

आप होती है। प्राकृतिक शक्ति के अन्ध विश्वास से ही इसमें भी काम होता है और उसके फल स्वरूप दुर्दशा तथा क्लेश सहना पड़ते हैं। पूँजीवाद में उपज की बागडोर, मनुष्यों के हाथ में न रहकर, पदार्थों में रहती है और वे ही उसकी रोक थाम करते हैं।

इसके विपरीत, समाजवादी संगठन में काम करने वालों के सहयोग से जान बूझकर उपज की रोक थाम, की जाती है ताकि जन साधारण की माँगों और उनकी आवश्यकताओं का परस्पर उपयुक्त सम्बन्ध बना रहे।

यह भी कहा जाता है कि लाभ के आधार पर उपज को यों ही छोड़ देने से जान बूझकर उपजकी रोक थाम करना कहीं कठिन है। और यह ठीक भी है। किसी वस्तु की रोक थाम करनेसे उसे अपनी धारा में बहने देना सर्वदा सरल रहता है। उदाहरण के लिये गाड़ी को ठीक मार्ग पर चलाना कठिन है। उसे जहाँ कहीं भी जाने देना सरल है, भले ही वह गड्ढे ही में क्यों न गिर जावे। इसी भाँति उपज के साधनों को वश में रखना, उन्हें अपने पर आधिपत्य न देना, कहीं कठिन है। परन्तु उनका अधिपत्य हानिकारक, तथा घातक हाने के कारण इन कठिनाइयों का सामना ही करना पड़ता है।

समाजवादी संगठन में, अधूरा होते हुए भी इतनी बुराईयाँ नहय़ रहतीं जितनी की पूँजीवाद में, ब्रिटैन और अमेरिका ऐसे उच्च उद्योग-शाली देशों में तो ऐसे संगठन का परिणाम प्रारम्भ से ही उपज की वृद्धि और रहन सहन में निश्चिन्ता होगी। उपज की बागडोर समाज के हाथ में रहने से जन समाज की दुर्दशा, अनिश्चिन्ता तथा अशान्ति से छुटकारा मिल सकेगा। और व्यापारिक तथा राजनैतिक अन्तराष्ट्रीय युद्ध से मुक्ति मिलेगी जिससे सम्पूर्ण संसार ही भयभीत है।



समाजवाद और पूँजीवाद

—:०:—

परस्पर विरोध

उपज के दोनो संगठन पूँजीवाद और समाजवाद का एक साथ मिल कर चलना असम्भव है। पदार्थों के उत्पन्न करने में लाभ तथा नियमित उपज दोनों आधारों पर निर्णय नहीं हो सकता। ऐसा निर्णय तो एक ही आधार पर हो सकता है चाहे वह लाभ के आधार पर हो अथवा उसका अन्त करके उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग एक निश्चित योजना के अनुसार किया जावे। यह दोनों एक साथ तो चल ही नहीं सकेंगे। ऐसा करने से तो आर्थिक जीवन में ही गड़बड़ी पड़ जावेगी। पूँजीवादी देशों में यदि शासन द्वारा योजना समिति का आयोजन हो और वह नियुक्त भी की जावे। परन्तु आर्थिक संगठन पूँजीवादी ढंग पर ही रहे तब देखना है कि परिणाम क्या रहता है और जन साधारण को मागे कितनी पूरी होती है। कितनी उपजाऊ शक्तियों बिना प्रयोग के व्यर्थ पड़ी हैं यह जानने में तो विशेष कठिनाई न होगी क्योंकि देशमें सहस्रों स्त्रीपुरुष नगे और भूखे होंगे। और उसके साथ ही साथ सहस्रों बेकार मजदूर, वन्द कल कारखानों और आवश्यक सामग्री भी व्यर्थ ही होगी।

वसभाविक ही है। कि योजना समिति इनका प्रयोग कराना चाहती। मान लो समिति इन वन्द पड़ी मशीनों के स्वामियों को आदेश देती है

कि ऐसी मशीनें चलाई जावें और उनसे कुरने कमोजं इत्यादि बनाई जावें ताकि नंगोंको कपड़ा मिल सके। कपड़ा बाजार की स्थिति किसी समय में एक ही हो सकती है या तो अधिक कपड़ा बनाना लाभप्रद है। तब तो इन बन्द मिलों के स्वामी तुरन्त ही योजना समिति के आदेशों को स्वीकार करके उन्हें चालू कर देंगे। ऐसी स्थिति में यदि समिति उन्हें तुरन्त आदेश न भी दें, तो भी आदेशों की प्रतीक्षा न करके वे स्वयं बन्द मिलों को चालू करके कपड़ा बनाना आरम्भ कर देंगे। क्योंकि यह तो उन के लाभ की ही बात होगी। और इस स्थिति में किसी आदेश की आवश्यकता भी न होगी।

इसके विपरीत यदि अधिक उपज लाभदायक नहीं, तो सर्व प्रथम तो मिल मालिक उनके आदेशों को स्वीकार करने में आना कानी करेंगे। तथा उससे बचने का प्रबन्ध सोचेंगे। यदि शासन ने उन्हें योजना समिति के आदेशानुसार कार्य करने को विवश किया। और उन्होंने ऐसे कारखाने खोले भी, तो उनके चलने में दिन प्रति दिन घाटा होगा। बाजारों में इन पदार्थों की संख्या बढ़ने से इनके मूल्य में और भी कमो होगा और इस प्रकार घाटा बढ़ता ही जावेगा। यदि और सब बातें वैसी ही रहें तो मशीनें अधिक समय तक चल ही न सकेंगी और अन्त में मिल मालिकों को समिति के आदेशों को अस्वीकार ही करना पड़ेगा। अन्यथा वे मिल मालिक ही न रह सकेंगे। अधिक घाटे से उनको पूँजो घटैगा और सम्भवतः मशीनें ही उनके हाथ से निकल जावें। फिर तो आदेश माने ही न जा सकेंगे।

अस्तु, पहली स्थिति में समिति के आदेश व्यर्थ होंगे और दूसरी में वे माने ही न जा सकेंगे। इसी कारण पूँजीवाद के रहते हुए नियमित तथा निश्चित आधार पर उपज का संगठन करना असम्भव ही है।

शक्तियों का प्रयोग

पूँजीवादी देशों में सब से बड़ा प्रश्न देश की उपजाऊ शक्तियों के प्रयोग का है। इन देशों में बहुत सी शक्तियाँ व्यर्थ पड़ी रहती हैं।

उनका प्रयोग विक्री के ध्यान से लाभप्रद नहीं होता परन्तु तो भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग मनुष्यता के ध्यान से भी होना ही चाहिये भले ही उनसे अधिक लाभ न हो। बेकार मनुष्यों को कुछ काम तो मिलना ही चाहिये ताकि उनकी जीविका निर्वाह हो सके।

बेकारों की समस्या

वर्तमान समय में बेकारों की समस्या बड़ी जटिल है। उनकी संख्या भी अधिक है। शासन को उसे किसी न किसी प्रकार सुलभाना भी अवश्य है। बेकारी के कारण देश की मांगें भी अधूरी रह जाती है। फिर पूँजीवादी देश इन बेकार मनुष्यों को जन साधारण के लिये आवश्यक पदार्थ बनाने को ही क्यों नहीं कह देते। भलेही उनके उत्पन्न करने में लाभ न हो, परन्तु उनसे देशवासियों को भोजन, वस्त्र निवास स्थान इत्यादिक आवश्यक पदार्थ तो प्राप्त हो ही जावेंगे। परन्तु ऐसा होता न ही। पूँजीवादी देश इन्हे इस प्रकार काम करने नहीं देते वरन् इसके स्थान पर वे भाँति भाँति के अन्य कामों की योजना (works scheme) सोचा करते हैं। और ऐसे समय में भी जब कि सहस्रों देशवासी आवश्यक पदार्थों के अभाव से कष्ट पाते हैं, देश के बेकार मनुष्य ऐसे ऐसे कार्यों में लगाए जाते हैं जैसे अनावश्यक सड़कें बनवाना, गड्ढे भराना, जंगल लगाना, पुष्प वाटिकायें लगाना इत्यादि इत्यादि। जन समाज की प्रारम्भिक माँगों को पूरा करने के आवश्यक कार्यों पर तो रोक ही लगा दी जाती है। वास्तविक उपयोगी पदार्थ बनाने की मानौ मनादी होती है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त बेकारों को काम देने के लिये भाँति भाँति की अन्य योजनायें ढूँढ़ने में मानसिक शक्ति का व्यर्थ अपव्यय भी होता है। पूँजीवादी देशों का तो सिद्धान्त ही दूसरा है। उनके सामने तो केवल लाभ का ही आधार रहता है। जब तक किसी पदार्थ का बनना लाभप्रद होगा तभी तक वे बनाए अथवा बनवाए जावेंगे अन्यथा नहीं, चाहे उनकी मांग कितनी ही क्यों न हो और कितने भी देशवासी उनके बिना कष्ट क्यों न भेलें। उन्हे तो अधिक मूल्य और लाभ चाहिये। पदार्थों

की अधिकता से तो लाभ में कमी ही होगी। उनका मूल्य भी अवश्य घटेगा। अस्तु, यही कारण है कि ऐसे संगठन में आवश्यक प्रारम्भिक माँगों को पूरा करने की अधिक चेष्टा नहीं होती।

यदि इस प्रकार का संगठन रहना है तो सदैव ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसी लिये ऐसे देशों में बेकारी को दूर करने के लिये ऐसे कामों की खोज करना पड़ती है जो किसी स्थिति में भी लाभप्रद न हो, अथवा कम से कम इतने समय तक लाभदायक न हो सकें कि केवल लाभ की आकांक्षा से प्रेरित व्यक्ति उस ओर आकर्षित हों। अथवा ऐसे भी काम जिनमें पुराने रिवाज के कारण लाभ उठाया ही न जा सकता हो जैसे डाक, तार इत्यादिक।

शासन का हस्तक्षेप

लाभप्रद कामों में शासन के हस्तक्षेप से पूँजीवादी संगठन चले ही न सकेगा। क्योंकि जैसा ऊपर लिखा जा चुका है यदि शासन मिल मालिकों से जन समाज की आवश्यक माँगों को पूरा करने के पदार्थ बनवाने में इन बेकारों को काम देने को कहे तो मिल मालिक ही निर्धन हो जावेंगे। एक तो पदार्थ बनवाने में घाटा और उस पर इन बेकारों को वेतन देना—इससे तो उन्हें दोहरी हानि ही उठानी पड़ेगी।

उपज के नए साधन बनवाने में भी इन बेकारों का प्रयोग पूँजीवादी व्यवस्था न हो सकेगा। क्योंकि इन नई मशीनों से उत्पन्न पदार्थों के बाजारों में आने से पुराने मिलमालिकों से इनकी गहरी प्रति द्वन्द्वता होगी जो इस समय तक लाभके आधार पर मशीनों को चलाते हैं। पदार्थों की संख्या इसप्रकार भी बढ़ेगी हो और उसके फल स्वरूप मूल्य में कमी होना स्वाभाविक ही है। मूल्य की कमी से उन मिलों को भी हानि पहुँचेगी जो इस समय तक लाभ के साथ चल रही थी और उनके मिल मालिक भी हानि उठावेंगे। अधिक हानि होने पर, मिलों को ही बन्द कर देंगे। उन मिलों में काम करने वाले मजदूर बेकार होंगे और इस प्रकार जितने बेकार मजदूरों को खपत इन नई मिलों में होगी,

उतने ही पुरानो मिलों से मजदूर नए बेकार हो जावेंगे। शासन के हस्तक्षेप से अन्त में लाभ के स्थान में हानि ही होगी।

अस्तु दोनों प्रकार के संगठन (पूँजीवाद व समाजवाद) एक साथ चल ही नहीं सकते। एक साथ चलाने से किसी से भी लाभ न हो सकेगा। पूँजीवाद में नियमित उपज का सिद्धान्त ही ठीक नहीं। वास्तव में पूँजीवाद का एक ही तो गुण कहा जाता है कि इस संगठन में उपज अनियमित रहती है और क्रय विक्रय के आधार पर घट बढ़ कर स्वयं ठीक हो जाती है। यदि यह गुण भी हटा दिया गया, तब तो फिर पूँजीवादी संगठन कुछ रह ही न जावेगा।

पूँजीवाद में शासन द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप न हो, ऐसी भी बात नहीं है। हस्तक्षेप होता है और वह नियमित उपज के ही नाम पर होता है प्रायः दिन प्रति दिन ऐसे नियम बनते हैं कि अमुक पदार्थ की उपज में अन्य वस्तुओं की संख्या निश्चित हो। उदाहरणार्थ किसी पदार्थ की उपज में कोयले की संख्या निश्चित रहे। और देश की सब कोयले की खाने, निश्चित संख्या से अधिक कोयले की उपज न करे। आयात निर्यात कर की नई २ योजनाएँ बनती हैं। मूद्रा मूल्य में कमी की जाती है। सेवाओं के लिये दिये जाने वाले बेतनो में कटौती लगती है। तथा शासन के आधिपत्य अथवा प्रभावित धन्धों में बेतनों में सीधे कमी की जाती है। निरुद्ध ऐसे काम देश के आर्थिक संगठन में हस्तक्षेप के हैं। और यदि इसी को योजना का स्वरूप दिया जावे तो प्रत्येक पूँजीवादी देश में कुछ न कुछ इस प्रकार की योजना अवश्य मिलेगी।

परन्तु ऐसी योजना और पूर्वोक्त नियमित उपजकी योजना में भारी अन्तर है। पूर्वोक्त योजना में जानबूझ कर प्रत्येक उपज के साधन का विशेष २ पदार्थों में बँटवारा करना होता है। अमुक साधन से अमुक पदार्थ, अमुक संख्या में बनेंगे। और इस प्रकार देश की लगभग सभी उपजाऊ शक्तियों का बँटवारा करना पड़ता है।

ऐसा तो सम्भव नहीं कि कुछ साधन अथवा शक्तियों का बटवारा योजना के अनुसार हो और कुछ का लाभ के आधार पर हो। क्योंकि ऐसा होने से तो संगठन में ही गड़बड़ी पड़ जावेगी। नियमित उपज के संगठन में देश की सब उपजाऊ शक्तियों का बँटवारा एक नियमित आधार पर निश्चित होता है। इसके विपरीत शासन द्वारा उपरोक्त हस्तक्षेप में कुछ पदार्थों अथवा साधनों में केवल थोड़ी बहुत रुकावट अवश्य होती है। परन्तु देश की सब उपज का एक नियमित रूप नहीं होता। और फिर उसका मुख्य आधार तो लाभ ही रहता है। इन हस्तक्षेप द्वारा लाभ के आधार की ही पुष्टि होती है। कहीं पर इसका लोप अथवा इसमें कमी नहीं होती जिसके दिना पूँजीवादी संगठन चलने में ही कठिनाई पड़े। उनका उद्देश्य या तो पदार्थों के मूल्य को बढ़ाना या बेतनो में कटौती करके उपज के मूल्य को घटाना होता है।

किसी पदार्थ की उपज को रोकने के सब उपायों का उद्देश्य, उस पदार्थ अथवा उद्योग के मूल्य को बढ़ाना होता है। क्योंकि ऐसी रोक थाम से उन पदार्थों की संख्या में कमी हो जाती है और फिर उनका क्रय मूल्य बढ़कर वे लाभप्रद हो जाते हैं। ऐसा उपाय तो उपज के लिये एक प्रकार का रोक थाम (Contra Ception) ही है। उदाहरणार्थ कृषि व्यवसाय में कुछ खेतों को ऊसर ही रखना अथवा उनपर उपज न कराना ताकि शेष उपजाऊ खेतों की उपज का मूल्य बढ़ सके। इसी प्रकार अन्य धन्धों में भी ऐसी ही युक्ति चलाई जाती है। कुछ मशीनें बेकार ही रखी जाती हैं ताकि अन्य मशीनों द्वारा उत्पन्न पदार्थों का मूल्य बढ़ सके।

मुद्रा के वास्तविक मूल्य को कम करने और उसके परिणाम स्वरूप साख को बढ़ाने की नीति भी ऐसी ही है। उनका उद्देश्य भी पदार्थों के मूल्य को बढ़ाना है। आयातकर, अथवा आयात की संख्या निश्चित करना इत्यादि भी ऐसे ही साधन हैं। परन्तु नियमित उपज की योजना के यह अङ्ग नहीं हो सकते।

पूँजीवादी देशों में अन्य प्रकार के हस्तक्षेप इनसे अधिक सीधे और स्पष्ट होते हैं। उनका उद्देश्य मजदूरों के वेतनों इत्यादि में कमी करके उपज के मूल्य को घटाना होता है। परन्तु इन दोनों प्रकार के उपायों का उद्देश्य उपज में लाभ के आधार की पुष्टि करना होता है। तार्किक इस आधार पर स्वयं चलने वाली कल चालू रहे। विक्री और उपज के मूल्य का अन्तर ही लाभ है, उपज के मूल्य में कमी अथवा विक्री के मूल्य को बढ़ाकर वह पूरा किया जा सकता है। अस्तु यह उपाय लाभ को बढ़ाने अथवा लाभ के आधार पर संगठन को चलाने के साधन हैं। नियमित उपज का संगठन तो इस सिद्धान्त ही का विरोधी है। उसका उद्देश्य लाभ नहीं वरन् जन साधारण की माँगों को पूरा करना है जो लाभ के आधार पर सम्भव नहीं होता। इसी कारण, देश की उपजाऊ शक्तियों का पूरा प्रयोग, जनता को अधिक से अधिक पदार्थ और सेवाएँ प्राप्त कराने वाले समाजवादी संगठन का प्रारम्भ पूँजीवाद के रहते नहीं हो सकता।

व्यक्तिगत स्वामित्व

इन दोनों संगठनों के एक साथ न चल सकने का विशेष महत्व पूर्ण कारण एक और भी है। पूँजीवाद संगठन में उपज के साधन का आधिपत्य तथा स्वामित्व पृथक् पृथक् व्यक्तियों के हाथ में रहता है। नियमित उपज अथवा समाजवादी संगठन के लिये यह आवश्यक है कि उपज के साधनों का आधिपत्य अथवा स्वामित्व व्यक्तियों के हाथ में न रहकर शासन अथवा समाज के हाथ में ही रहे। ऐसे स्वामित्व का दोनों संगठनों से गहरा सम्बन्ध है। और उसके बिना संगठन भली भाँति चल नहीं सकेगा।

समाजवादी संगठन में किसी प्रकार की योजना चलाना असम्भव है, जब तक उपज के लगभग सम्पूर्ण साधनों पर उनका प्रभावशाली तथा स्थाई आधिपत्य न हो, अथवा जब तक वे उपज के साधन मशीन,

मजदूर, आवश्यक सामग्री, तथा अन्य उपजाऊ शक्तियों का बटवारा इस प्रकार न कर सकें कि उनसे निश्चित संख्या में ही जन साधारण के पदार्थ बनें। इनके बिना वे शक्ति हीन तथा निस्सहाय रहेंगे। व्यक्ति विशेष के हाथ में इनका आधिपत्य रहने पर, उनके स्वामी, इन साधनों का प्रयोग शासन के कहे पर भी एक बाहरी समिति के आदेशानुसार चलने नहीं देंगे। न ऐसा कर ही सकते हैं। क्योंकि व्यक्तियों के हाथ में साधनों के रहने से, उनका प्रयोग लाभ के आधार पर होगा—किसी केन्द्रीय योजना के आधार पर कदापि नहीं।

अस्तु, यही कहना पड़ता है कि नियमित उपज अथवा समाजवादी संगठन का प्रारम्भ तब हो सकता है जब कि उपज के लगभग सब साधना का स्वामित्व अथवा पूरा पूरा आधिपत्य शासन के अथवा सहयोगी समितियों के रूप में जनता के हाथ में रहे जो पूँजीवादी संगठन में सम्भव नहीं।



उपज का बटवारा

—:०:—

पूँजीवादी ढंग

उपज का उद्देश्य, उसका प्रयोग है। जो पदार्थ बने, उनका प्रयोग हो। वे जनता के काम आवें। गेहूँ तथा दूसरे अनाज उपजाने का उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य समाज उससे भोजन पा सके। अन्य वस्तुओं अथवा पदार्थों के लिये भी ऐसा ही है। समाज का आर्थिक जीवन केवल उपज ही नहीं हो सकता है। उसके लिये केवल उपज ही प्रयाप्त नहीं है। पदार्थों के प्रयोग के लिये उनका बटवारा भी उतना ही आवश्यक है। बटवारे शब्द का प्रयोग मुख्यतया दो अर्थों में होता है। प्रथम तो पदार्थों अथवा सेवाओं का उपज के स्थान से उनके प्रयोग के स्थान तक पहुँचाना। उदाहरणतः बने हुए पदार्थ, गेहूँ, अनाज इत्यादि का बाजारों में पहुँचाना। दूसरे, उपज के पदार्थों को जन समाज के भिन्न भिन्न वर्गों तथा व्यक्तियों में बाँटना होता है। अर्थात् बने हुए पदार्थों का उपयोग पदार्थ उत्पन्न करने वाले प्रत्येक वर्ग तथा व्यक्ति को किस प्रकार और कितनी संख्या में मिले।

पहिले प्रयोग से तो अधिक प्रयोजन नहीं, विशेष महत्व की बात तो इस दूसरे प्रयोगमें ही है। पदार्थ कैसे अथवा किन के द्वारा बाजारों और घरों में पहुँचने हैं। इसका अधिक महत्व नहीं। देखना तो यह है कि किन किन के पास कितनी संख्या में ये पहुँचते हैं। अर्थात् समाज

में उपज किस प्रकार बटती है। उपज को संख्या निश्चित हो जाने पर, यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि उसका उपयोग मिलेगा किसे ? कौन कौन से पदार्थ बने और कितनी कितनी संख्या में यह निश्चय हो जाने पर यह भी निश्चय आवश्यक होता है कि इन बने हुए पदार्थों का कितना कितना भाग किन किन वर्गों अथवा व्यक्तियों को मिले।

पदार्थों और सेवाओं के बटवारे का ढंग प्रत्येक व्यक्ति को पदार्थ अथवा सेवा की एक निश्चय संख्या देना ही हो सकता है। यह संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिये चाहे समान हो, अथवा भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिये कम अथवा अधिक हो। परन्तु व्योहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। मनुष्यों को पदार्थ न दैकर उसके स्थान में रुपया दिया जाता है जिससे वे अपनी इच्छानुसार पदार्थों अथवा सेवाओं को मोल ले सकें और उनका प्रयोग कर सकें। मोल लेने अथवा प्रयोग कर सकने की उनकी शक्ति प्राप्त रुपये तक ही सीमित रहेगी। इस प्रकार बटवारे का प्रश्न समाज में आय का बांटना ही रह जाता है। क्योंकि आयके बटवारे से ही, मनुष्यों को पदार्थ अथवा सेवाओं को मोल लेने की शक्ति मिलती है। इसी कारण बटवारे के प्रश्न पर विचार करने समय केवल यही विचार करना रहता है कि देश का सम्पूर्ण आय किस प्रकार किन २ वर्गों अथवा व्यक्तियों में, किस २ संख्या में, और कैसे बांटी जावे स्पष्ट रूप में किन २ कामों के लिये आय दी जावे और प्रत्येक के लिये कितनी ?

मजदूरों का वेतन

पूँजीवादी संगठन में मनुष्यों को धन उनके किये हुए कामों के लिये दिया जाता है। इसका बटवारा दो विशेष भागों में रहता है। एक तो काम करने वाले मजदूरों को वेतन के रूप में और दूसरा पूँजी-पतियों को अपनी पूँजी के प्रयोग के लिये। मजदूरों को दिया जानेवाला धन 'वेतन' अथवा मजदूरी कहलाता है। प्रत्येक मजदूर के काम की संख्या और गुणके आधार पर उसका वेतन निश्चित होता है।

जो प्रायः प्रति सप्ताह अथवा निश्चित घंटों पर निर्भर होता है। किसी मजदूर को मजदूरी निश्चित करने में उसके काम के गुण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साधारण मजदूर व शिक्षित कला कुशल कारीगर व इंजीनियर इत्यादि के काम में भिन्नता रहती है और उसी के अनुसार उनको दिये जानेवाले वेतन में भी अन्तर होता है। काम सरल है अथवा कठिन, उसे करने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता है अथवा नहीं, मजदूरी निश्चित करने में इन बातों का प्रभाव पड़ता है।

पूँजीपतियों का भाग

दैश की आय का बटवारा एक तो उपर्युक्त ढंग से मजदूरों को वेतन देने में होता है। पदार्थ उत्पन्न करने तथा उससे सम्बन्धित काम करने वाले, अपने काम के लिये वेतन अथवा मजदूरी पाते हैं। उपज से प्राप्त धन का एक भाग इस प्रकार बँट जाता है। परन्तु इसके अतिरिक्त पूँजीवादी देशों में एक दूसरे प्रकार के मनुष्यों को भी धन दिया जाता है जो स्वयं काम नहीं करते। वे किन्हीं पदार्थों के स्वामी होते हैं। उन्हें उनके काम के लिये नहीं वरन् उनके स्वामित्व के लिए धन दिया जाता है। प्रत्येक पदार्थ के स्वामी को यह धन नहीं दिया जाता वरन् केवल उपज के साधनों के स्वामियों को ही यह मिलता है। उदाहरणतः एक मोटर के स्वामी को केवल उस के इस स्वामित्व के कारण उपज का कोई भाग अथवा धन नहीं दिया जावेगा। क्योंकि वह तो उपज के साधन का स्वामी नहीं वरन् एक साधारण पदार्थ का ही स्वामी है। इसके विपरीत एक मोटर बनाने वाली मशीन के स्वामी अथवा ऐसे किसी कार्यालय के हिस्सेदार को उपज का यह भाग मिलेगा क्योंकि ऐसी मशीन अथवा उसके धन से मोटरें तथा अन्य पदार्थ बनाए जावेंगे। अस्तु उपज के साधनों के स्वामियों अथवा उनके हिस्सेदारों को ही इस प्रकार आय का एक भाग दिया जाता है। इस प्रकार अनाज उपजाने वाले खेतों के

स्वामी, जमींदार, ताल्लुकेदार, कोयले इत्यादि कानों के स्वामी, तथा अन्य पूँजीपति जो अपना धन उपजाऊ पदार्थों को उत्पन्न कराने में लगाते हैं, यह धन पाते हैं।

इन स्वामियों को इस प्रकार धन देने का कारण कहा जाता है कि अपनी पूँजी को उपज के कामों में प्रयोग करने देने की उनकी स्वीकृति है। यदि उन्हें उपज का यह भाग न मिले तो वे अपनी पूँजी, मशीन इत्यादि का प्रयोग ही न होने दें। इसी कारण उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिये उन्हें उपज का एक भाग देना ही पड़ता है। कानून के द्वारा उन्हें ऐसा करने को साधारणतया कोई बाध्य तो कर नहीं सकता वरन् यदि वे चाहें तो इस प्रयोग को अस्वीकार भी कर सकते हैं। क्योंकि यह साधन भी उनकी वैयक्तिक सम्पत्ति ही तो है। और अन्य सम्पत्ति की भाँति उन्हें अधिकार है कि वे उसका भी जैसा चाहे प्रयोग करें। उदाहरणार्थ किसी खेत का स्वामी अपने खेत को जोते जाने से रुकवा भी सकता है। अपने आनन्द के लिये उस पर पुष्प वाटिका लगवाने का भी उसे अधिकार है। इसी प्रकार किसी खदान के स्वामी को पूरा अधिकार है कि वह अपनी खदानों में काम न होने दें। जिससे कोयला, सोना, अथवा कोई अन्य खनिज पदार्थ निकाला ही न जा सके। पूँजीवादी संगठन में इसी तर्क से, ऐसे स्वामियों को उनकी सम्पत्ति का उपजाऊ कामों में प्रयोग करवाने के लिये सूत, लगान अथवा भाड़ा देना पड़ता है। अधिक सूत, अथवा भाड़ा देने वाले को हो ये अपनी सम्पत्ति का प्रयोग देते, यह भी स्पष्ट ही है। लाभ के कारण ही नो वे ऐसा प्रयोग देने को प्रेरित होते हैं। लाभ की अधिकता पर ही यह इसका निर्णय भी करेंगे।

वास्तविक प्रश्न

परन्तु वास्तविक प्रश्न तो यह है कि वे किराये पर लेने वाले

यह सूत अथवा किराया कहाँ से देगे । पदार्थ से प्राप्त लाभ ही मे से तो दिया जावेगा ।

भाड़े पर मशीन अथवा खेत लेने वाला खेत की उपज से प्राप्त मूल्य मे ही से सूत अथवा लगान दैगा । और कोई अन्य पूँजी तो है नही और न हो ही सकती है । अपने पास से अथवा अन्य कहीं से देने मे पदार्थ बनाने से उसे लाभ ही क्या होगा । उपज के लाभ से ही यह भाग दिया जाता है ।

साधनो के स्वामियो और उन्हे प्रयोग करने वालो मे यह तो सीधा सम्बन्ध हुआ । परन्तु वास्तव मे ऐसा भी नही होता । सब प्रयोग करने वाले, इन साधनों को सीधै उनके स्वामियों से नही लेते वरन एक या दो मनुष्य इन्हे भाड़े इत्यादि पर लेकर उन्हे दूसरों को दे दैते हैं अथवा दूसरों द्वारा उनका प्रयोग करवाते हैं । ऐसे बीच के लोगों को भी कुछ न कुछ लाभ चाहिये नही तो वे भी काम न करेंगे । भाड़े अथवा लगान के रुपये मे इन का भाग भी जुड़ जाता है । किसी एक किसान अथवा मजदूर के पास इतना धन ही नही होता कि यह सीधै इन साधनों को मोल अथवा भाड़े पर भी ले सके । उनके लिये कठिनाइयाँ भी अधिक रहती हैं । और इस प्रकार बीच के लोगों के कारण भाड़े का धन द्विगुना नही तो डेवड़ा होही जाता है ।

अब सहज ही यह प्रश्न उठता है कि साधनो के यह स्वामी भाड़े पर देने के वजाय स्वयं इनका प्रयोग उपजाऊ कामो मे क्यों नही करते ? कुछ स्वामी ऐसा करते भी है । और दशा सूत अथवा भाड़ा न मिलकर उन्हे उपज का सम्पूर्ण लाभ ही मिल जाता है । भाड़े पर प्रयोग करने वालो से उन्ह अधिक ही मिलता है क्योंकि उन्हे तो सूत अथवा भाड़ा भी देना पड़ता है जो इन्हे नही देना पड़ता । अथवा यों कहे कि वे सूत अथवा

भाड़ा भी अपने ही को देते हैं। और इस प्रकार सूत, भाड़ा और लाभ तीनों ही उनको मिल जाते हैं।

स्वामित्व का धन

उपज के साधनों के प्रयोग से प्राप्त लाभ ही वह भाग है जो इन स्वामियों को उनके स्वामित्व के लिये मिलता है। सूत अथवा भाड़े तो उसका एक भाग है। साधन के भाड़े पर न उठाए जाने पर भी, ये भाग रहते हैं भले ही उनका प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति हो। अस्तु उपज के स्वामियों को प्राप्त लाभ में से एक भाग देना पड़ता है क्योंकि उसके बिना, समाज को इन आवश्यक साधनों का प्रयोग ही न मिले। उपज हा ही न सके और समाज जीवित ही न रह सके।

चूँकि उपज के साधनों, खेत, खदान तथा पदार्थ उत्पन्न करने के लिये आवश्यक मशीनों के अधिकतर स्वामी वे ही होते हैं, समाज का विवश होकर, उन्हें लाभ का एक भाग देना होता है। और वह भी अधिक भाग। यह जानकर कि समाज इनके बिना जीवित ही नहीं रह सकता, उनकी भाव ताव की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और इस कारण यह लोग उपज का एक बहुत बड़ा भाग ले लेते हैं। प्रायः यह भाग इतना बढ़ जाता है कि प्रयोग करने वालों के पास जीवित रहने भर का भी नहीं बच पाता।

दुर्दशा के लक्षण

पदार्थों के रूप में रखने पर इसके अर्थ यह होते हैं कि बनने वाले लगभग सब पदार्थ यह स्वामी ही ले लेते हैं और इनके अतिरिक्त अन्य मनुष्यों के लिये कुछ बचता ही नहीं। स्थिति तो यहाँ तक भी पहुँच जाती है कि जन साधारण को भूखे और नंगे तक रहना पड़ता है। जब कभी भी समाज अथवा साधनों का प्रयोग करने वाले, इस भाग में कमी करना चाहते हैं ताकि उसे

दूसरों में वाँट सकें, ये पूँजीपति अपने साधनों का प्रयोग ही रोक देते हैं। उनका प्रयोग चाहने वालों को निकाल देते हैं। कारखानों को बन्द कर देते हैं। कार्य स्थगित कर देते हैं जो प्रचलित भाषा में, लाक आउट (Lock out) कहलाता है। जीविका संकट से विवश होकर बेचारे काम करने वालों को इन स्वामियों से फिर समझौता करना पड़ता है। क्योंकि उनके बिना वे जीवित ही नहीं रह पाते। इस प्रकार इन स्वामियों अथवा पूँजीपतियों की देश की उपज में से काम करने वालों को जीविका के लिये आवश्यक पदार्थों को छोड़कर, शेष सब वचत मिल जाती है। अथवा यों कहे कि काम करने वाले जीविका के आवश्यक पदार्थ और सेवाओं को रोककर देश की सब शेष उपज इन पूँजीपतियों को ही दे देते हैं। और यदि वे, अपने जीवन के लिये आवश्यक से अधिक पदार्थ बनावे ही नहीं तो इन पूँजीपतियों को कुछ मिले ही नहीं। परन्तु वास्तव में मजदूर जीविका की सीमा से कहीं अधिक संख्या में पदार्थ बना सकते हैं और यह पूरी वचत पूँजीपतियों को मिल जाती है।

अस्तु, इस प्रकार लाभ होता तथा बँटता है। साधनों के स्वामित्व के कारण ही पूँजीपतियों को लाभ का भाग देना पड़ता है। ऐसा स्वामित्व कानूनों द्वारा सुरक्षित है। वह अधिक प्रभावशाली भी है। और इसी कारण उनका भाग अधिक होता है।

उपज की रोक थाम

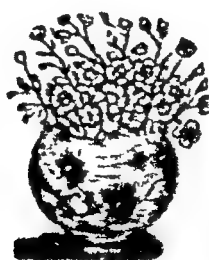
वैसे तो पूँजीपतियों को अपनी सम्पत्ति अथवा उपज के इन साधनों का प्रयोग करवाने का प्रोत्साहन देने के लिये ही यह लाभ का भाग दिया जाता है। परन्तु इसके अतिरिक्त इस लाभ द्वारा सगठन तथा नीति की रोक थाम का काम भी होता है और वे ही पदार्थ बनाने दिये जाते हैं जिनकी, बिक्री से लाभ हो। पदार्थों

के बटवारे का उपरोक्त ढंग पूँजीवादी संगठन का एक आवश्यक अङ्ग ही है। पूँजीवादी व्यवस्था में यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्त्री पुरुषों को न केवल उनके काम के लिये उपज का कोई भाग दिया जावे, वरन् साधनों के स्वामित्व अथवा पूँजी के लिये भी—क्योंकि पूँजीपतियों को लाभ, सूत अथवा भाड़ा न देने से ऐसे संगठन में काम करने की इच्छा अथवा उपज की रोक-थाम का ही अन्त हो जावेगा।

परिणाम

उपज का यह बड़ा भाग इन मुठ्ठी भर पूँजीपतियों के हाथ में देने के कारण ही पूँजीवाद में बड़े अवगुण तथा हानि होती हैं। क्योंकि इस के कारण, संगठन में जनता की आवश्यक माँगों का विचार किये बिना दैश की आय का बटवारा करना पड़ता है। मनुष्यों की माँगों और पदार्थों के मूल्य में इसी लिए इतनी भिन्नता जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसमें धनी मनुष्यों की सजाबट इत्यादि के व्यर्थ पदार्थ बनाना लाभप्रद तथा असंख्य जनता को जीवन के आवश्यक पदार्थ बनाना लाभप्रद न होना सम्भव होता है। स्पष्टमें ऐसा भलेही न हो, परन्तु वास्तव में, दैश की उपज अथवा आय के इस प्रकार बुरे बटवारों के कारण ही पूँजीवाद में सहस्रों दैशवासियों को बेकार रहना पड़ता है। काम मिलने ही नहीं पाता।

यही कारण है कि पूँजीवादी संगठन को दिन प्रति दिन अवनति होती जाती है और यहाँ तक कि अब उसके अनुसार काम हो ही नहीं सकता है।



पूँजीवाद का परिवर्तित रूप

स्वामित्व भाग

उपज के साधनों के स्वामित्व के लिये पूँजीवाद में उपज का एक बड़ा भाग पूँजीपतियों को दिया जाता है। भाग की अधिकता के कारण ही पूँजीवाद में इतनी खींच तान बढ़ गई है जिससे कार्य होना हो कठिन है। पूँजीपतियों का भाग इतना अधिक है कि अन्य काम करनेवालों के लिये कुछ बचता ही नहीं। इसका पूरा पूरा ज्ञान तभी होता है जब पूँजीपतियों के भाग को रुपये के रूप में न देखकर पदार्थों में उसका हिसाब लगाया जावे। संगठन की निस्सारता तथा असंगतता भी तभी स्पष्टतया सिद्ध होगी। रुपये के हिसाब में एक मनुष्य का दूसरे से सहस्रों गुना अधिक व्यय करना अव्योहारिक प्रतीत नहीं होता। ऐसा होता ही रहता है, उचित अथवा न्याय पूर्ण भले हो न हो। उपज की रीति की गड़बड़ी का उससे पूरा पूरा अभास नहीं हो पाता। जन साधारण की क्रय शक्ति के बदवारे में तो इससे कमी नहीं होती है, उसको कुल संख्या तो वही रहती है चाहे सहस्र मनुष्यों को एक एक रुपया मिले अथवा एक मनुष्य को एक सहस्र मिल जावें। परन्तु इसी कारण पदार्थों की माँग में भी कोई कमी न होना चाहिये, व्योहार में ऐसा नहीं होता।

एक मनुष्य को बहुत अधिक धन मिल जाने और दूसरों के

कम मिलने से पदार्थों की माँग में कमी हो जाती है। और इसे ही दूर करने का उपाय ढूँढ़ना है।

असमान आय

असमान आय के वटवारे का परिणाम पदार्थों के रूप में देखने से स्थिति बिल्कुल दूसरी हो जाती है। किसी मनुष्य को सहस्र गुना धन मिलना भले ही अव्योहारिक न प्रतीत हो परन्तु उसे दूसरों से सहस्र गुने अधिक पदार्थ मिलना असंगत तथा व्यर्थ ही होता है। क्योंकि सम्भवतः वह उन सब का प्रयोग नहीं कर पावेगा। उदाहरण के लिये भोज्य किसी पदार्थ को ही ले लीजिए, एक मनुष्य अधिक से अधिक दूसरे मनुष्य से द्विगुना भोजन कर सकेगा परन्तु सहस्र गुना नहीं। इसकी तो बात ही क्या, दस गुना भी भोजन कभी नहीं कर सकता। इसी प्रकार वस्तु तथा निवास-स्थान के सम्बन्ध में भी है। कोई मनुष्य एक समय में सहस्रों पल्लंगों पर सो नहीं सकता और न इतने पलंगों की उसे आवश्यकता ही हो सकती है। सहस्रों वस्त्र, घर इत्यादि की आवश्यकता भी उसे नहीं हो सकती। यह ठीक है कि धनी लोग बहुत कुछ व्यर्थ तथा अनुपयोगी व्यय करते हैं परन्तु वे तो भी किसी प्रकार तो भी उस अनुपात में पदार्थों का प्रयोग नहीं कर सकते जो उनकी तथा अन्य मनुष्यों की आय में रहता है। और यदि इस प्रकार व्यय करें भी, तो उसे अपव्यय तथा दुर्न्यय के अतिरिक्त अन्य कुछ कहा नहीं जा सकता।

व्यर्थ पदार्थ

ऐसी स्थिति के आर्थिक परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। लाभ, लगान, सूत, वेतन अथवा मजदूरी इत्यादि द्वारा प्रयुक्त क्रय शक्ति का वटवारा पूँजीवाद में भी होता है। इसी लिये कि सब बने पदार्थ मोल लिये जा सकें। परन्तु वटवारा के इस ढंग के कारण सब पदार्थों की खपत नहीं हो पाती।

यह स्थिति तो तब है जब देश की उपजाऊ शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग भी नहीं हुआ है। पूरे प्रयोग द्वारा बनने वाले पदार्थों का तो कहना ही क्या है।

इसका मुख्य कारण बटवारे के आय को इतनी असमानता हो है। कुछ मुट्ठी भर धनी लोगों को इतना अधिक धन मिल जाता है कि मोल लेने की शक्ति होने पर भी वे उतने पदार्थ मोल नहीं लेते। उन्हें उतनी आवश्यकता ही नहीं होती। इसके विपरीत असंख्य मनुष्यों को उपज का भाग इतना कम मिलता है कि आवश्यकता होते हुए भी वे पदार्थ मोल ले नहीं पाते। उनमें पदार्थ मोल लेने की सामर्थ्य नहीं होती। धनी पदार्थों को लेते नहीं, क्योंकि उनके लिये वे पदार्थ व्यर्थ तथा अनुपयोगी होते हैं, और निर्धन उन्हें ले नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना धन ही नहीं होता। और इस प्रकार पदार्थ बिक ही नहीं पाते। वे व्यर्थ ही पड़े रहते हैं और इसी कारण उनके बनाने में लाभ नहीं होता। अस्तु यह तो नहीं कह सकते कि पूँजीवाद में क्रय शक्ति का पूरा २ बटवारा हो जाने से उसमें कोई बुराई रहती ही नहीं। उदाहरण से यह और भी स्पष्ट हो जाता है।

मान लो कि ५) ५) रुपये वाले १०० पलंग बनाए गए और उनसे ५००) की क्रय शक्ति का बटवारा हुआ। अब यदि इसमें से ४००) एक मनुष्य को दिया गया। और शेष १००) को ५० मनुष्यों में २) रुपये के हिसाब से बाँटा गया। तो यह नहीं कहा जा सकता कि सब पलंग बिक ही जाएँगे। पचासों मनुष्य १।५ पलंग नहीं मोल लेंगे और न एक मनुष्य ८० पलंग ही। इन पचास में से कोई २ एक पलंग भी नहीं ले सकेंगे और एक मनुष्य को ८० की आवश्यकता तो हो ही नहीं सकती। इस प्रकार बहुत से पलंग बिकने से निस्तदैह बच जाएँगे। क्रय शक्ति के असमान और बुरे बटवारे का भी वही परिणाम होगा जो कम शक्ति बटने से होता है। यही कारण है कि

पूँजीवाद में उपज के साधन रहते हुए भी बहुत से आवश्यक पदार्थों की माँग पूरी नहीं हो पाती। और कुछ पदार्थ आवश्यकता से कहीं अधिक बन जाते हैं। निर्धनता तथा पदार्थों की अधिकता एक साथ हो रहती है। मशीनों से पूरा २ काम नहीं लिया जाता और बहुत से काम करनेवालों को काम भी नहीं मिलता।

परन्तु यदि व्योहार में पूर्ण रूप से ऐसा ही होता तो पूँजीवाद का कभी का अन्त हो गया था और चूँकि पूँजीवाद इतने दिनों से लगातार चल रहा है, इन कठिनाइयों को दूर करने का कोई न कोई उपाय अवश्य ही ढूँढ़ लिया गया होगा। इस बात में थोड़ी सत्यता भी है। धनी व्यक्ति अपनी पूँजी लगाते हैं और प्राप्त धन से पदार्थ मोल लेते हैं। उन्हें सब धन संचय हो करना नहीं रहता। परन्तु प्रयोग के पदार्थों के मोल लेने में भी वे अपना अधिक धन व्यय नहीं करते। वे उससे उपज के नए २ साधन मोल लेते हैं। अर्थात् उपज के साधनों के स्वामित्व से प्राप्त धन से वे उपज के और नए नए साधन मोल लेते हैं और इस प्रकार इन साधनों पर उनका स्वामित्व दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है। पूर्वोक्त उदाहरण में ४००) रुपए पानेवाला व्यक्ति ८० पलंग तो मोल नहीं लगा। परन्तु नए ढंग के पलंग बनाने की मशीन अथवा कारखाना खोलने में उस धन का लगावेगा और इस प्रकार उपज का प्रयोग पदार्थों से हटकर उपज के साधनों की ओर झुकता है। साधारण शब्दों में लगान, सूत अथवा लाभ के धन का व्यय न तो प्रयोग के पदार्थों के मोल लेने में होता है और न संचय ही किया जाता है। वह फिर से धन्या में लगाया जाता है। इससे यह अभिप्राय नहीं कि पूँजीपान धन संचय करते ही नहीं और सब का रुद्धा व्यय हो कर डालत है अथवा धन्यों में लगा देते हैं। वे संचय भी करते हैं और इस प्रकार भी समाज की उन्नति में बाधक होते हैं।

उपज का भुकाव साधनों के मोल लेने अथवा बनाने में होना प्रत्यक्षतया वर्तमान कठिनाई को दूर करने का उपाय प्रतीत होता है। क्योंकि इससे समाज की क्रय शक्ति में कोई कमी नहीं होती और उपजाऊ शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग भी होता है। केवल प्रयोग के पदार्थों के स्थान में उपज के साधन अधिक से अधिक संख्या में बनते अथवा मोल लिये जाते हैं। उनका अनुपात समाज के व्यय और संचय के अनुपात पर ही आश्रित रहता है। पूँजीवाद में यह अनुपात भी बटवारे की असमानता के अनुपात से ही निश्चित होता है। क्योंकि स्वभावतः धनी लोग धन संचय ही करेंगे और निर्धनों को सब रुपया व्यय ही करना पड़े। एक बात और भी है साम्प्रति पूँजीपतियों का भाग उन्हें पृथक् पृथक् न देकर, पूँजीपति वर्ग अथवा उसकी भिन्न भिन्न संस्थाओं, स्टॉक कम्पनी, ट्रस्ट, बैंक इत्यादि का दिया जाता है ताकि वह फिर उन्हीं धन्धों में लग सके। और यह संस्थायें प्राप्त धन को पूँजीपतियों को न देकर, उसे उसी धन्धे में लगा भी देते हैं इस प्रकार प्रथम बाँट और फिर उन्हीं पूँजीपतियों से लेने की आवश्यकता भी दूर हो जाती है। परन्तु चाहे वे पूँजीपति उस धन को स्वयं धन्धों में लगावें अथवा इन संस्थाओं द्वारा वह धन्धों में लगे, इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। सिद्धान्त तो वही रहता है।

वास्तविक कठिनाई तो यह है कि इस प्रकार धन्धों में धन का लगना भले ही एक निश्चित काल के लिये पूँजीवाद को चलने दे, परन्तु परिस्थित दिन प्रति दिन विकट ही होती जाती है। उपज का अन्तिम ध्येय तो प्रयोग है और जब यह प्रयोग ही नहीं हो पाता, वरन ज्यों ज्यों उपज के साधन अधिक होते हैं, उनमें अधिकतर धन लगता जाता है, प्रयोग के पदार्थों के बनने और उनके प्रयोग में उतनी ही कमी हो जाती है। और उससे होने वाले सब परिणाम बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि पूँजीवाद में इन नए उपज के साधनों का स्वामित्व भी व्यक्तियों के हाथ में ही रहता है और उससे प्राप्त लाभ फिर प्रयोग के पदार्थों को मोल लेने अथवा उनके प्रयोग में न लग

कर उपज के साधनों में ही लगता है। यह तीसरे ढंग के उपज के साधन भी व्यक्ति विशेष के हाथ में ही रहेंगे और उससे प्राप्त लाभ का प्रयोग भी वैसाही होगा। इसी प्रकार यह गाड़ी चलेगी और पूँजी संचय बढ़ता जावेगा। उपजाऊ शक्तियों के एक विशेष ढङ्ग के प्रयोग से ही तो पूँजी बनती है। और वह ढङ्ग यही है कि उससे नए उपज के साधन जमा हों और फिर बने, इत्यादि इत्यादि ऐसे ही क्रम चलता रहे। पूँजीवाद का उद्देश्य तो लाभ कमाना था। और लाभ उठाने में पूँजी संग्रह होने लगा जिसके अर्थ लाभ उठाने वालों के हाथ में रुपए के स्थान में एक प्रकार के पदार्थों देना होता है। यह पदार्थ उपज के साधन ही हैं।

पूँजीवाद के समर्थकों का कहना है कि पूँजीवादी सङ्गठन का उद्देश्य लाभ कमाना है। पदार्थ उत्पन्ना करना नहीं। यह तो उसका साधन मात्र है। पदार्थ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उनकी बिक्री द्वारा लाभ उठाया जा सके। इसके अर्थ तो यह होते हैं कि पूँजीवाद का उद्देश्य पूँजी संग्रह के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और पूँजी संग्रह तो उपज के साधनों को उन्नति बतलाने का एक ढङ्ग है। क्योंकि पूँजीवाद में लाभ, उपज के साधनों के रूप में ही रहता है। और उसी में उसका अनुमान लगता है। इस प्रकार पूँजीपतियों के कुल लाभ का अनुमान नए बने हुए उपज के साधनों से होता है। इसीलिये पूँजीवाद का उद्देश्य नए उपज के साधन बनाना है ऐसा भी कहा जा सकता है।

पूँजी संग्रह

ऐसे पूँजी संग्रह से भी एक बड़ी हानि होती है। प्रचलित साधनों के स्थान में आनेवाले नए साधन इनसे कहीं भिन्न होते हैं। उनके द्वारा काम भी अधिक होता है। मजदूरों का काम भी अधिकतर, अन्य मशीनों से ही लिया जाता है। और इसी कारण उनसे बने पदार्थों की आय का बटवारा भी मशीन और उनके

स्वामियों में ही अधिक होता है। पदार्थ बनाने में जिससे काम अधिक लिया जावेगा उपज का भाग भी उसे ही अधिक मिलेगा। और चूँकि इन नई मशीनों में द्वारा पदार्थ बनाने में मशीनों तथा पूँजी की ही अधिक सहायता रहती है, उपज का अधिक भाग भी उन्हें ही मिलता है। वेतन और मजदूरी के रूप में मजदूरों को कम दिया जाता है क्योंकि उनका काम कम रहता है। इसके अतिरिक्त, मजदूर प्राप्त धन का व्यय पदार्थों में कर डालते हैं। परन्तु पूँजीपति उससे अन्य उपज के साधन लेंगे जो इनसे भी अधिक मशीन द्वारा काम कराने वाले होंगे।

इसके परिणाम स्वरूप उपज का और अधिक भाग इन पूँजीपतियों को मिलेगा और उतनाही मजदूरों का कम होता जावेगा। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। वरन् दिन प्रति दिन इसका वेग बढ़ता ही जावेगा। जिससे बटवारे की असमानता और उसके दुष्परिणाम और भी बढ़ेंगे।

संगठित पूँजी

उपज के साधनों के बढ़ने से एक परिणाम और भी होता है। सीधे, सरल तथा छोटे २ साधनों के स्थान में बड़े और पैचीदा होते जाते हैं। क्योंकि बटवारे के इस ढंग के कारण उनका स्वामित्व, बिखरा हुआ तथा पृथक् पृथक् व्यक्तियों के हाथ में न रहकर संगठित, संयुक्त तथा सर्वाधिकार सुरक्षित हो जाता है। पूँजीपति ही नए साधन मोल ले सकते हैं। और इन पूँजीपतियों में भी अधिक धनी व्यक्तियों का पूँजी की अधिकता के कारण अधिक ही अधिक भाग रहता है। पूँजीवादी देशों में जहाँ पहले छोटे छोटे साम्ने के कारखाने थे। उनके स्थान में आज बड़ी २ कम्पनियाँ, कारपोरेशन, और सेन्डीकेट बन गए हैं। बड़ी शीघ्रता से यह काम हुआ है और प्रति दिन होता जाता है।

ऐसे संगठन का परिणाम और भी बुरा हुआ। बहुत से पूँजीपतियों की संख्या घटकर थोड़े से बहुत धनी ही पूँजीपति रह गये

जिससे पूँजीपतियों का भाग इन मुट्ठी पर धनी व्यक्तियों में ही बटा । और इस प्रकार सैकड़ों छोटै २ पूँजीपति भी उपज से पृथक हुए और उन्हे भी आय काम मिलने लगी । जिसके फल स्वरूप उनकी आवश्यक पदार्थ मोल ले सकने की शक्ति कमी हुई ।

पहिले मजदूर फिर छोटै छोटै पूँजीपति, और फिर उनसे बड़े पूँजीपति, इसी प्रकार धीरे धीरे असंख्य देशवासी अपनी साधारण आवश्यकताओं की माँगों को पूरा करने की शक्ति से बंचित होते जाते हैं ।

सर्वाधिकार पूँजीपति

उपज के साधनों का कुछ थोड़े मनुष्यों के हाथ में जमा हो जाने का इससे भी अधिक हानिकारक परिणाम यह होता है कि इस प्रकार भिन्न भिन्न उपज करने वालों में परस्पर स्वतन्त्र प्रतिद्वन्दता नहीं रह पाती । जो पूँजीवाद का एक मुख्य गुण है । परस्पर प्रतिद्वन्दता के कारण ही तो लाभ की खींच तान से पूँजीवादी संगठन चलता रहता था । उपज पर सर्वाधिकार (Monopoly) अथवा अर्ध अधिकार (Semi Monopoly) होने पर, ऐसी प्रतिद्वन्दता का अन्त ही हो जाता है । और उसके कारण संगठन के अन्य प्राकृतिक नियमों में भी परिवर्तन होता है ।

पूँजीवादी संगठन में ऐसी स्थिति का होना स्वाभाविक तथा अवश्यम्भावो ही है । ऐसी स्थिति में बने हुए पदार्थों की विक्री और भी कठिन हो जाती है । जब देश के उपजाऊ साधनों की उन्नति इस स्थिति पर पहुँच जाती है कि वे कुछ धनी व्यक्तियों के हाथ में ही जमा हो जावे पूँजीपतियों को परस्पर प्रतिद्वन्दता का अन्त हो जाता है ।

जनता अधिकतर निर्धन और बेकार होती है । देश के बने हुए पदार्थों की विक्री को खोज अन्य देशों में की जाती है । देश

के बाजारों को तो अपने कार्यों से वे पहिले ही नष्ट कर चुके होते हैं। और इसी कारण अन्य देशों में अपने पदार्थों की खपत करना और उसके लिये राजनैतिक आधिपत्य प्राप्त करने की आवश्यकता, देश की उद्योगिक उन्नति के पश्चात् प्रायः प्रत्येक पूँजीवादी देश को होती है। जिसके कारण अन्त राष्ट्रीययुद्ध तथा महायुद्ध होते हैं। उनका होना अनिवार्य ही हो जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति में पूँजीवाद ही तो साम्राज्यवाद का रूप धारण करता है। साम्राज्यवाद के अवगुण तथा उससे होनेवाली हानि कितनी भयंकर होती है यहाँ पर बतलाना सम्भव है और न आवश्यक ही। पूँजीवादी उन्नति नही अन्तिम निश्चित परिणाम बतलाना साम्राज्यवाद है। देशों की पारस्परिक वैमनस्यता, आर्थिक द्वन्द्व, राजनैतिक कलह, सांसारिक महायुद्ध, जिसके आवश्यक भावी तथा अनिवार्य फल है। पूँजीवाद का अन्तिम परिवर्तित रूप भी यही है।

अन्तिम परिणाम

पूँजीवाद के प्रारम्भ मे उपज के साधनों की उन्नति की प्रेरणा लाभप्रद वस्तु थी। यह एक ढंग था जिसके द्वारा देश की उद्योगिक उन्नति के लिए सरलता से धन प्राप्त हो जाता था तथा लाभ के लोभ के कारण दिन प्रति दिन उसकी उन्नति होती जाती थी।

परन्तु देश की उपजाऊ शक्तियों की पूर्णतया उन्नति हो जाने पर पूँजीवाद का यह गुण अथवा अवगुण ही कहिए, समाज के लिए श्राप सा हो जाता है। देश मे उपज के साधनों के प्रयाप्त संख्या में होने पर अधिक संख्या मे उन्हें और बढ़ाना व्यर्थ होता है। जब उनसे पदार्थों की अधिकता व निश्चितता प्राप्त हो जाती है और जनता निर्धन तथा बेकार रहती है।

इस स्थिति में उपज के साधनों से प्राप्त धन (लाभ) फिर उपज के साधनों के बनाने मे ही लगता चला जाता है। जो फिर उसी काम में आता है और इसी प्रकार ऐसा तो तभी होगा जब कि इस प्रकार

साधनों की लगातार उन्नति करना सम्भव भी हों। और उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग आवश्यक पदार्थों में न होकर बराबर अधिक से अधिक अनुपात में साधनों की उन्नति में ही लगे।—परन्तु वास्तव में एक निश्चित मात्रा के उपरान्त यह सम्भव नहीं रहता और उसके पश्चात् उपजाऊ शक्तियों की ऐसी उन्नति ही असम्भव हो जाती है। क्योंकि उससे लाभ नहीं होता। वर्तमान पूँजीवादी देश में इस समय स्थिति कुछ ऐसी ही सी है। उपज के साधनों को बढ़ाना लाभप्रद नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पूँजीवाद का अन्तिम ध्येय। केवल उपज के साधनों की उन्नति ही नहीं वरन आवश्यकता और प्रयोग के पदार्थों को अधिक संख्या में बनाना और उसे जन साधारण में बाँटना भी है। वास्तव में किसी भी आर्थिक संगठन का यही ध्येय हो सकता है।

साम्यवादी तथा समाजवादियों का भी यही कहना है। पूँजीवादी देश की उपजाऊ शक्तियों की बढ़ती अथवा प्रारम्भिक उद्योगिक उन्नति करने का अच्छा ढंग हो सकता है। परन्तु इससे अधिक उसका काम नहीं। प्रारम्भिक उद्योगिक उन्नति हो जाने पर संगठनके अवगुण दिखाई देने लगते हैं और पहिले के दिखावटी गुण प्रत्यक्षतया अवगुण हो जाते हैं।

लाभ की इच्छा द्वारा ही प्रारम्भ में जनता उद्योगिक उन्नति के लिये प्रेरित होती हैं। परन्तु देश की उन्नति के माने तो यह है कि जनता के आवश्यक पदार्थ, प्रयोग के लिये अधिक संख्या में मिलें। वास्तव में होता क्या है ?

देश की उद्योगिक उन्नति हो जाने पर पूँजीवाद में जनसंख्या के ६० प्रति शत मनुष्यों को उसकी उन्नति के कुछ लाभ नहीं होता। वरन परिस्थिति उलट ही जाती है। वे जो अनेक दिनों समय में उन्नति के लिये आवश्यक थीं, वे ही अब अत्यन्त आवश्यक हो जाती हैं।

किसी भी आर्थिक परख के लिये यह स्पष्ट है कि उसका

परिणाम व स्वरूप केवल उसी समय ही न परखा जावे वरन यह भी, देखा जावे कि भविष्य में इसका रूप और परिणाम क्या रहता है, तभी उसकी पूरी परख हो सकती है, अन्यथा नहीं। पूँजीवाद का प्रारम्भिक रूप भले ही सुन्दर, आकर्षक तथा लाभप्रद हो, परन्तु उसका बाद का स्वरूप और विशेषकर अन्तिम रूप तो निश्चित हानिकारक वरन घातक ही होता है। साम्राज्यवाद तथा उसके परिणामों पर द्रष्टि डालने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है।



वर्ग

अथवा

श्रेणी संघर्ष

पूँजीवादी संगठन में, उपज के साधनों पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व रहता है। वे लाभ के लिये उनका प्रयोग करते हैं। उपज में पूँजीवादी संगठन रहने के कारण बँटवारे का भी पूँजीवादी ढङ्ग ही रखना पड़ता है। और इसी कारण पूँजीपतियों का उपज में एक बड़ा भाग रहता है।

ऐसे बँटवारे के कारण समाज दो वर्गों में विभाजित सा हो जाता है। एक तो वे जो अपने काम के पुरस्कार स्वरूप निश्चित वेतन पाते हैं। और दूसरे वे जिन्हें केवल साधनों के स्वामित्व के कारण भाग मिलता है। प्रथम मजदूर और द्वितीय पूँजीपति कहलाते हैं। पूँजीवादी बँटवारे का ही यह परिणाम है। ऐसे संगठन में इनका होना प्रायः अनिवार्य ही है। यही नहीं, वरन् इनमें परस्पर काफ़ी संघर्ष भी रहता है।

इन वर्गों और उनके संघर्ष को अस्वीकार करना अथवा उसे भुला देना, जानबूझ कर भूल करना ही होगा। पूँजीवादी उपज ही से इनका जन्म होता है। बँटवारे का उपज से अटूट

सम्बन्ध है और इसी कारण कहना पड़ता है कि वर्गों का होना पूँजीवादी संगठन का एक निश्चित परिणाम ही है ।

स्थगित फल

प्रायः कहा जाता है कि साधनों के स्वामित्व के लिये प्राप्त धन और मजदूरों के वेतन में विशेष भिन्नता नहीं । क्योंकि दोनों ही काम के पुरस्कार स्वरूप दिये जाते हैं । आज के साधनों के स्वामी कभी मजदूर ही थे और मजदूरों से प्राप्त धन को दचाकर ही वे आज ऐसे स्वामी बन गये हैं । पिछले वर्षों में अपनी मजदूरों के धन को पूरा पूरा व्यय न करके, वे उसमें से थोड़ा थोड़ा संचय करते रहे । और इस संचित धन से ही वे ऐसे साधनों को मोल ले सके हैं । इसी कारण वे भी मजदूरों को भाँति ही लाभ का भाग पाने के अधिकारी हैं । मजदूरों को वर्तमान कामों के लिये धन मिलता है और पूँजीपतियों को उनके पिछले वर्षों के काम के लिये स्वामित्व के रूप में लाभ का भाग मिलता है ।

गत वर्षों को मजदूरों से प्राप्त धन संचय करने का यह पुरस्कार है । या दूसरे शब्दों में पिछले कामों का यह स्थगित फल है ।

पूँजीपति कैसे बने

देखें यह तर्क कहाँ तक सच और वास्तविक है ? बहुत पहिले ऐसा कहा जा सकता था कि अच्छे वेतन पाने वाले मजदूरों और स्वतन्त्र कारीगरों को मजदूरों की बचत से कुछ उपज के साधनों की थोड़ी उन्नति हुई । परन्तु अब यह तर्क उठाना भूल ही है ।

ब्रिटेन तथा अमेरिका ऐसे देशों में जहाँ उपज के साधन विशेष उन्नति पर हैं, इस तर्क का कोई महत्व नहीं । रैकड़ों वर्ष पूर्व भी वहाँ के साधनों की उन्नति जमींदारों व ताल्लुकेदारों की आय की बचत

से हो हुई थी। यह आय कुछ तो उनके स्वामित्व से मिली और कुछ व्यापारियों द्वारा नई बस्तियों के लूटमार से प्राप्त हुई थी।

अमेरिका के सम्बन्ध में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट ही है। वहाँ उद्योगिक उन्नति मजदूरों अथवा किसानों के धन की बचत से हुई हो, ऐसी बात नहीं। वहाँ कुछ पूँजी ब्रिटैन से गई और वहाँ के उद्योग धन्धों में लगी और कुछ दाक्षिणी देशवासियों (Negro) के काम से प्राप्त लाभ की बचत से हुई।

गत वर्षों के काम की बचत से यह पूँजीपति हुए हों अथवा इसीसे देश की उद्योगिक उन्नति हुई हो, यह बात कदापि नहीं।

अमेरिका और ब्रिटैन दोनों ही में अधिकतर पूँजीपति वर्ग मौरूसी ही रहा है। उसके सदस्यों ने आय, अपने पूर्वजों से पाई है। अथवा उपज के साधनों को बढ़ाकर, उसके स्वामित्व से स्वयं प्राप्त की है। गत वर्षों में मजदूरी करके और उससे प्राप्त धन की बचत से कल कारखाने इत्यादि चलाये नहीं गये हैं।

कुछ उदाहरण ऐसे भी अवश्य मिलते हैं जिनमें कुछ व्यक्ति स्वयं अपने परिश्रम से पूँजीपति बने हो परन्तु उनमें भी ऐसा कोई नहीं जो मजदूरी का एक एक पेसा बचा कर पूँजीपति हुए हों। उनकी वर्तमान बड़ी पूँजी, या तो उनके भाग्य के कारण है जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिला है अथवा प्रारम्भ में ही उन्हें कोई ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, जब उन्होंने उपज के किसी साधन का लाभ के साथ प्रयोग कर के उससे विशेष धन प्राप्त कर लिया है। और उसे साधनों के मोल लेने में लगाकर वे पूँजीपति बन गये हैं मजदूरी के पैसे की बचत से अथवा गत वर्षों के कामों के स्थगित फल स्वरूप, पूँजीपति कोई विरले ही बना हो।

वर्ग विभाजन

कौन व्यक्ति किस वर्ग का है इसका निर्णय आय की अधिकता

अथवा न्यूनता पर नहीं रहता । इसका निश्चय तो इस बात पर होता है कि आय उसे किस प्रकार मिलती है । उदाहरणार्थ कुछ मजदूर किन्हीं पूजीपतियों से अधिक वेतन पाते हैं । निपुण तथा विशेषज्ञ मजदूरों को ५००) अथवा इससे भी अधिक वेतन मिलता है । बुद्धि से कार्य करने वाले इससे भी अधिक वेतन, पाते अथवा पास करते हैं । परन्तु ये पूजीपति नहीं कहे जा सकते । इसके विपरीत कुछ पूजीपतियों के पास साधन इतने कम हैं कि उनको भाड़े, लगान अथवा सूत के रूप में बहुत कम धन मिलता है । परन्तु मजदूरों से धन कम मिलने पर भी यह पूजीपति ही रहेंगे और वे मजदूर ही कम धन मिलने से ये पूजीपति मजदूर नहीं कहे जा सकते और इसी प्रकार अधिक वेतन मिलने पर भी वे मजदूर पूजीपति नहीं हो सकते । चाहे उनकी आय पूजीपतियों से कितनी ही अधिक क्यों न हो । अथवा उनके स्वभाव में ही अन्तर क्यों न हो जावे क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है, कि अधिक धन मिल जाने से मनुष्य स्वभाव का मुकाव पूजीपतियों का सा होने लगता है । साधारणतया मजदूरों की आय कम और अधिक रहती है, ऐसे उदाहरण सम्भवता कम मिलेंगे जिन में, मजदूरों की आय पूजीपतियों से अधिक हो । परन्तु तो भी वर्गों के विभाजन में आय की अधिकता अथवा न्यूनता का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । वर्ग शब्द धनी अथवा निर्धनता का प्रयायवाची नहीं । इसका सम्बन्ध आय के आधार से हो रहता है । और उसी के अनुसार कोई व्यक्ति एक अथवा दूसरे वर्ग में कहा जाता है । ऐसा सम्भव है कि समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो जिन्हें दोनों प्रकार से थोड़े बहुत आय मिलती हों । और उन्हें पूजीपति अथवा मजदूर दोनों ही कह सकते हैं ।

ऐसे व्यक्ति अधिकतर बुद्धि से कार्य करनेवालों में ही मिलेंगे । परन्तु इनकी संख्या अधिक नहीं रहती और इसी कारण उनका विशेष उल्लेख भी नहीं किया गया और न उन्हें कोई पृथक् वर्ग ही दिया गया ।

कोई विशेष वर्ग न रहने पर भी ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन करने से इस बात का ज्ञान होता है कि आय के आधार का मनुष्य के स्वभाव तथा उनकी विचार धारा पर क्या और किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। साधारणतया मनुष्यों को विचार धारा आय के आधार पर ही निर्भर रहती हैं। यह देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के विचार कुछ मजदूरों और कुछ पूँजीपतियों के से होते हैं अथवा दोनों का मिश्रण रहता है। ऐसे व्यक्ति मध्यम श्रेणी के कहलाते हैं। संख्या में कमी के कारण, वगैरे विचार से इनका अधिक महत्व नहीं होता और इसी कारण तीसरा वर्ग ऐसा नाम न देकर प्रायः दो ही वर्ग विशेष कहे जाते हैं। एक मजदूर दूसरा पूँजीपति।

वर्गविभाग का परिणाम

समाज का इस प्रकार दो बड़े २ वर्गों में विभाजित होना, राजनैतिक व आर्थिक क्षेत्र में बड़े महत्व का है। और उसका परिणाम भी महत्व पूर्ण ही होता है। यह तो स्पष्ट ही है कि वर्गों के स्वार्थ समान नहीं होते। वरन् एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। जितना अधिक भाग मजदूरों को वेतन अथवा मजदूरी के रूप में दिया जावेगा, पूँजीपतियों के लिये भाड़ा, लगान व सूत के रूप में उतना ही कम बचेगा। और इसी प्रकार जितना अधिक भाग पूँजीपतियों का होगा, मजदूरों के हिस्से में उतनी ही कमी करनी पड़ेगी। यह भी देखा गया है कि पूँजीपतियों का भाग बहुत अधिक और मजदूरों का इतना कम होता है कि उससे वे अपना जीवन निर्वाह तक नहीं कर पाते। केवल किसी प्रकार अपने को काम कर सकने के योग्य रख पाते हैं क्योंकि उसके बिना तो उनकी जीविका ही चली जावे। इसके विपरीत पूँजीपतियों का भाग इतना अधिक होता है कि वे जीवन का पूरा आनन्द ही नहीं उठाते, वरन् अधिक विलासता में पड़कर प्रायः उसका दुरुपयोग भी करते हैं। इस भाँति एक वर्ग केवल अपने स्वामित्व के कारण प्राप्त धन से असंख्य भोगों का भोग करते हुए, विलासता का जीवन

व्यतीत करता है; जब कि दूसरा वर्ग (मजदूर) बड़े परिश्रम और अधिक समय तक काम करके भी केवल इतनी ही आय प्राप्त कर पाता है कि वह किसी प्रकार रूखी सूखी रोटी खाकर अपना पेट भर सके और बहुतों को तो वह भी प्राप्त नहीं होता। तिस पर भी उसकी जीविका सुरक्षित नहीं रहती। काम से पृथक कर दिये जाने पर उसे यह रूखा सूखा भोजन मिलना भी दुर्लभ हो जाता है।

निश्चित अन्याय

समाज के बहुत व्यक्ति और विशेषकर मजदूर वर्ग ऐसी व्यवस्था को अन्याय पूर्ण समझता है। गत ३०० वर्षों की ऐतिहासिक तथा उद्योगिक उन्नति के अनुभव से प्रायः अधिकतर व्यक्तियों के ऐसे विचार होते जाते हैं कि मनुष्य मनुष्य में ऐसी असमानता का रहना अवश्य हानिकारक है और इसे दूर होना चाहिये भले ही वे उसके उपाय अथवा अन्य व्यवस्था, पूर्ण रूप से निश्चित न कर सके हों।

पूँजीवाद के समर्थक पूँजीवादी व्यवस्था के इस अंग पर अब अधिक वाद विवाद नहीं करने। उनका प्रयत्न अब इसे भुलाने का हो रहता है। स्थिति का उल्लेख होने पर उसे आवश्यक बुराई ऐसा कह देते हैं। और ऐसा ही उसे समझने भी है। स्वीकार भी कर लेते हैं कि ऐसी असमानता अनुचित है परन्तु फिर भी व्यवस्था के अन्य गुणों का विचार करते हुए उसे छोड़ना नहीं चाहते। वरन इसे प्रचलित रखने का यह मूल्य बतलाते हैं। पूँजीवाद में कौन से ऐसे गुण हैं जिनके कारण इतना असह्य क्लेश सहने और समाज को इत प्रकार नष्ट होते देखकर भी उनके विचार परिवर्तित नहीं होते, यह तो वे ही जान सकते हैं। अधिक विचार विनिमय के उपरान्त भी हमारी तो यही धारणा है कि ऐसी व्यवस्था का शीघ्रातिशीघ्र अन्त होना चाहिये।

कार्य की इच्छा

यह भी कहा जाता है कि आय में असमानता को दूर कर देने से मनुष्यों में काम करने की इच्छा न रहेगी अथवा उसमें बहुत कमी हो जावेगी। जिससे उपज घटैगी और पदार्थों के अभाव से जनता को कष्ट उठाना पड़ेगा तथा उपज का कोई नियंत्रण ही न चल सकेगा।

आश्चर्य की बात है कि बार बार वही बात दुहराई जाती है मानों पूँजीवाद के अतिरिक्त दूसरा कोई उपज का नियंत्रण हो ही नहीं सकता अथवा पूँजीवाद आवश्यक भी है। फिर यह भी कहाँ का न्याय है कि किसी एक वर्ग को काम करने को प्रोत्साहित करने के लिये, उसे दूसरों का उचित भाग दे दिया जावे। इस सिद्धान्त पर यदि प्रत्येक काम करनेवाला ऐसे ही अधिक भाग माँगे और उसके बिना काम ही न करें तो प्रत्येक भाग में अधिकता हो भी कैसे पावेगी। फिर यदि यही तर्क दूसरा वर्ग, पूँजीपतियों के सामने रखे, और उपज का अधिक भाग लिये बिना मजदूर काम ही न करें तो क्या पूँजीपति इसे स्वीकार करेंगे ?

यही नहीं, अपना न्यायोचित भाग माँगने पर तो वे काम से पृथक् कर दिये जाते हैं। अधिक भाग को तो बात ही क्या। उस समय इस वर्ग को काम के लिये प्रोत्साहन देने का सिद्धान्त नहीं रक्खा जाता वरन् उनके निर्धन अशिक्षित तथा असंगठित होने से लाभ उठाकर उन्हें जीवन निर्वाह के वेतन पर काम करने को विवश किया जाता है अन्यथा जीविका हरण, बैकारी तथा उससे होनेवाले असह्य कष्ट सहने की विवशता।

आवश्यक परिणाम

फिर यदि दूसरा वर्ग भी संगठित हो जावे, और इन सब बातों को सहकर भी अपनी उचित माँगों को प्राप्त किये बिना काम न करे, तब तो उपज ही रुक जावेगी। क्योंकि उपज के लिये साधनों का प्रयोग

और उसका प्रयोग करनेवाले मजदूर, दोनों ही आवश्यक हैं। केवल एक से तो काम चल ही नहीं सकता। अस्तु

इसके तो यही अर्थ होते हैं कि दूसरे वर्ग को भी संगठित होना ही पड़ेगा। अधिक भाग लेने के लिये न सही, तो स्वरक्षा के विचार से ही उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। उनके संगठित हो जाने पर लगातार इन दोनों वर्गों में संघर्ष रहेगा। क्योंकि दोनों की चेष्टा यही होगी कि उपज का भाग उसे ही अधिक मिले और दूसरे को कम। और फिर एक दूसरे को पराचित करने में दोनों का समय तथा शक्ति का दुर्व्यय होगा। उपज की उन्नति के स्थानमें उल्टे अवनति हो होगी। विशेष उद्योग धन्यों को परस्पर कलह और इस खींच तान में नष्ट हो जावेंगे क्योंकि उपज के दोनों आवश्यक वर्गों की शक्ति क्षीण से उपज में धक्का लगाना स्वाभाविक ही है।

अस्तु, पूँजीवाद का निश्चित परिणाम समाज को दो बड़े बड़े तथा परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित करना होता है जिन्हे विपरीत आधारों से आय मिलती हैं। उनके जीवन में अधिक असमानता और परस्पर विरोध रहता है। संगठन की कथित उन्नति के साथ साथ यह विरोध भी बढ़ता जाता है। और सीधे संघर्ष का रूप धारण करता है। शक्ति के हास के साथ २ उपज शक्ति भी क्षीण होती है। उद्योग धन्यै नष्ट हो जाते हैं। बेकारी बढ़ती है। आवश्यक पदार्थों के अभाव से जनता को कष्ट सहना पड़ता है। दैश में स्थान २ पर चोरी, डाका तथा मार पीट होने लगती है।

अन्याय और अत्याचार से मुक्ति पाने के लिये संगठन आवश्यक ही होता है जो क्रान्ति करके समाज को इन क्लेशों से छुटकारा दे।

इसी से तो समाजवादी कहते हैं कि ऐसे पूँजीवाद का प्रारम्भ मे ही अन्त क्यों न कर दिया जावे ताकि भविष्य में यह सब क्लेश होने ही न पावे। वर्ग विभाग ही न हो और न उससे होनेवाले उपरोक्त यह दुष्परिणाम ही।

बटवारे का समाजवादी ढंग

—:o:—

आवश्यकता का आधार

—

पूँजीवादो उपज में गड़बड़ी का मुख्यकारण उसके बटवारे का ढंग है। इसी के द्वारा, समाज में सबसे अधिक अन्याय होता है। वर्गों के संघर्ष का भी यही कारण है। देखना यह है कि इसके स्थान पर समाजवादो ढंग क्या हो सकता है। समाजवादो ढंग में सूद, लगान अथवा लाभ तो देना ही नहीं होगा क्योंकि यह भाग तो उपज के साधनों के स्वामित्व के कारण दिये जाते हैं और समाजवाद में ऐसा वैयक्तिक स्वामित्व ही नहीं होता। समाजवादो ढंग पर की गई उपज का बटवारा पूँजीवादी ढंग पर नहीं हो सकता और इसी प्रकार पूँजीवादो उपज और समाजवादी बटवारा नहीं हो सकता। यह दोनों ढंग भिन्न २ हैं और इसी कारण किसी एक प्रकार की उपज के लिये उसी प्रकार का बटवारा भी आवश्यक होता है। और समाजवादी ढंग से प्राप्त उपज को समाज के पृथक पृथक व्यक्तियों में बाँटने के लिये कोई समाजवादी ढंग ही निकालना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को क्या और कितना २ भाग मिले, यही प्रश्न इस सम्बन्ध में उठते हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है।

समान आय

निश्चित योजना के अनुसार प्राप्त उपज के लब्ध पदार्थों का

प्रत्येक व्यक्ति को सामान दे देना ही बटवारे का सबसे सरल ढंग हो सकता है। इस सिद्धान्त पर बटवारा करने में विशेष सुविधा भी रहेगी। किसी देश की सम्पूर्ण उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग होने पर, देश के प्रत्येक कुटुम्ब अथवा उसके सदस्य को समानता के आधार पर उपज का कितना भाग मिले, यह अनुमान लगाया जा सकता है। और उसी के अनुसार लब्ध पदार्थ बाँटे जा सकते हैं।

बहुतों का ऐसा विचार होगा कि समाजवादी अथवा साम्यवादियों का प्रस्तावित ढंग यही है। वे उपज का बटवारा इसी सिद्धान्त पर करना चाहेंगे। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समान आय पहुँचाना उनका अन्तिम अथवा तत्कालिक कोई भी ध्येय नहीं। इसके विपरीत साम्यवादी विचारधारा के जन्मदाता मार्क्स और एन्जेल ने बटवारे का दूसरा ही ढङ्ग बताया था। और लेनिन तथा स्टालिन ने सोवियट रूस में इसी ढङ्ग का प्रयोग भी किया है।

लेखकों का मत

मार्क्स के सिद्धान्तों पर न चलने वाले और फिर भी अपने को समाजवादी कहने वालों में जॉर्ज बर्नार्ड शा (George Bernard Shaw) प्रमुख हैं, निश्चित योजना के आधार पर प्राप्त उपज के समान आय के सिद्धान्तों पर बाँटने का प्रस्ताव किया है। श्रीमान् शा ने तो समान आय के सिद्धान्त को अगले कार्यक्रम का केन्द्र ही बनाया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आय की समानता ही समाजवाद है और वे लोग जो इस प्रकार आय की समानता नहीं चाहते, समाजवादी ही नहीं।

समाजवाद और साम्यवाद पथ प्रदर्शक नामक अपनी पुस्तक में अत्यन्त सारगर्भित शब्दों में वे इस सिद्धान्त को दुहाई देते हैं। इनके कथनानुसार तो मार्क्स, एन्जेल तथा लेनिन ही समाजवादी नहीं। यदि उनका यह कथन सत्य मान लिया जावे तो, श्रीमान् शा

को यह सिद्ध करना चाहिये कि एन्जिल का यह कथन कि श्रेणी तथा वर्गों के अन्त के अतिरिक्त आय में समानता की माँग सर्वथा असंगत तथा व्यर्थ है समाजवादी संगठन के लिये अनुपयुक्त है। उन्हें यह भी बतलाना चाहिये कि आय की समानता के सिद्धान्त का प्रयोग न करके लेनिन और स्टालिन ने कैसे भूल की है ?

शा महोदय ने अपनी पुस्तक में कहीं इसकी चर्चा भी नहीं की कि आर्थिक समानता के विषय पर इससे पूर्व कभी विचार भी हुआ है। और प्राचीन विज्ञान नीतिज्ञों के सब विचारों और रुढ़भावों को भुलाकर जिनका इन समस्याओं से विशेष सम्बन्ध है, यों ही एकायक कह डाला है कि समाजवाद के अर्थ आय की समानता ही है समाजवादी नेताओं ने इस पर विशेष मगन किया है और इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट विस्तार पूर्वक वक्तव्य भी दिये हैं। उदाहरणार्थ सोवियट यूनियन के साम्यवादी दल की १७ वीं कांग्रेस में स्टालिन ने कहा है कि “मार्क्सवाद का प्रारम्भ ही यह मान कर होता है कि मनुष्य की योग्यता तथा आवश्यकताएँ न समान हैं और न हो सकती हैं।” इसके अतिरिक्त अंग्रेजी समाजवादी विचारकों श्री मतो तथा श्रीमान वेव ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके लिए तो यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वे मार्क्स के सिद्धान्तों को रूस में प्रस्तुत वातावरण के अनुसार करने के लिए उन्हें ताड़ मरोड़ अथवा घुमा फिरा कर करेंगे, वे तो मार्क्स के अनुयायी भी नहीं हैं। और न रूस से उनका कोई विशेष सम्बन्ध ही है। वरन् गत वर्षों में वे मार्क्सवाद के एक बड़े विरोधी लेखक भी रहे हैं।

इस सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा है कि यह समझना एक बड़ी भूल है कि सोवियट रूस में साम्यवादी दल ने समाजवादी शासन की स्थापना इस आधार पर की कि सब मानसिक और शारीरिक काम करने वालों के समान आय हो मिले क्योंकि सब मनुष्य समान ही जन्म लेते हैं अतः ऐसे समाज में जिसमें इनका जन्म हुआ और जिसमें वे रहते हैं उन्हें पूरा अधिकार

है कि उत्पन्न हुए सब पदार्थों में समान ही भाग ले सकें ।

समाजवादियों की कभी भी ऐसी विचार धारा नहीं रही । समानता के सिद्धान्त को वे सदैव तीव्र आलोचना हो करते रहे हैं ।

बटवारे का ढंग

समाजवाद में प्राप्त पदार्थ फिर किस सिद्धान्त पर बाँटे जावें । बटवारे के दो ढंग बतलाये गये हैं । (१) उपज काम करने वालों को उनके काम की संख्या व गुण के आधार पर बाँटे । जिसका अर्थ यह है कि प्रचलित ढंग का एक भाग ऐता हो रक्खा जावे । यानी मजदूरों को तो वर्तमान ढंग पर ही वेतन मिले । वेतन के द्रव्य में वृद्धि अवश्य हो जावे परन्तु दूसरे भाग का अन्त हो कर दिया जावे । स्वामित्व के लिये लगान, सूद अथवा लाभ का भाग दिया जाता है । समाजवाद में ऐसा स्वामित्व जिसके द्वारा उपज के साधनों के स्वामियों को उनके हो नहीं रहेगा । बिना काम किये किसी को आय दी ही न जावे । संक्षेप में, जीवन निर्वाह का केवल एक ही ढंग रक्खा जावे और वह काम करके ही हो । बिना काम के मिलने वाली आय का अन्त हो कर दिया जावे । ऐसी रीति में मनुष्यों को केवल अपने काम के लिये ही पुरस्कार मिल सकेगा । परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि काम के लिये अयोग्य, बूढ़े, रोगी, तथा शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों को भोजन ही न दिया जावेगा । इनके लिये आज का ही सा प्रबन्ध रहेगा । वे किसी काम करने वाले पर ही आश्रित रहेंगे । समाज में ऐसे मनुष्यों की भी एक काफ़ी संख्या रहती है जो उपज का कोई काम कर ही नहीं सकते । समाजवाद में उनके लिये दूसरा ही प्रबन्ध होता है । बुढ़ापे को पेंशन, अयोग्यता अथवा दुर्घटनाओं के लिये बीमा, उच्चश्रेणी की शिक्षा के लिए वजीफ़े इत्यादि इसके कुछ उदाहरणमात्र हैं । समाजवाद में इनका विशेष प्रबन्ध रहता है बरन् पूँजीवाद से कहीं अधिक ही होता है । परन्तु इस प्रकार धन देने से भी समाजवाद के मूल सिद्धान्त में

कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उसमें केवल काम के लिए ही आय दी जाती है। बुढ़ापे को पेंशन, दुर्घटनाओं का बीमा अथवा दुर्घटनाओं के कारण हानि की क्षति पूति इत्यादि का तो कार्य से सम्बन्ध है ही। विद्यार्थियों को वजीफे के रूप में दिया जानेवाला धन भी उन्हें भविष्य में अधिक काम करने योग्य बनाने के सिद्धान्त पर रहता है। कुछ न कुछ ऐसे संरक्षण तो रहना ही चाहिए।

अस्तु, यह दैन लेन भी उसी ही सिद्धान्त पर है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने काम के लिए ही पुरस्कार मिले तथा किसी का भी जीवन निर्वाह दूसरों के परिश्रम पर न रहे। इसी सिद्धान्त पर समाजवादी संगठन में शासन के उद्योगों में वैतनिक मजदूरों, तथा सहयोगी समितियों में सदस्यों को उनके काम के लिये क्रय शक्ति अथवा पदार्थों और सेवाओं का बटवारा होता है। दोनों के लिये एक ही सिद्धान्त रहता है। सहयोगी समितियों में उपज के साधन उन्हीं के होते हुए भी, उनके स्वामित्व के लिये कोई धन नहीं दिया जाता है। सदस्य स्वयं उन साधनों पर काम करते हैं और उनके काम के लिये उन्हें भी धन देने की व्यवस्था है।

परिवर्तन का परिणाम

उपज के ढंग में परिवर्तन होने से ही उसके बंटवारे में भी परिवर्तन करना पड़ा है परन्तु इस परिवर्तन के सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। आर्थिक परिणामों में सबसे प्रथम ध्यान में रखने वाली बात तो यह है कि इस ढंग से समाज की उपजाऊ शक्तियों का प्रयोग आवश्यक पदार्थ अथवा सेवाओं के उत्पन्न करने में ही होगा। अथवा एक निश्चित अनुपात में उपज के साधनों के बनाने में, यह अनुपात निस्संदेह समाज के आदेशों पर योजना बनाने वालों के निश्चयानुसार ही होगा। आवश्यक पदार्थों की पूरी र माँग न हो सके, इसकी तो कोई भय है नहीं। क्योंकि आय की अधिक असमानता का तो प्रश्न ही नहीं

रहता। आप की असमानता तथा काम के बिना धन मिल जाने के कारण हो तो पूँजीवाद में देश को उपजाऊ शक्तियों का पूरा प्रयोग जन साधारण के लिये आवश्यक पदार्थों के बनाने में नहीं लग पाता है वरन् बहुत सा धन मुट्ठी भर धनी आदमियों के पास संचित हो जाता है जिसका व्यय हो नहीं हो पाता है। समाजवादो संगठन में भले ही मनुष्यों की आय में अपने २ काम के अनुसार थोड़ी बहुत असमानता रहे और कुछ मनुष्य दूसरों से अधिक पदार्थों से सेवाये ले सकें। परन्तु इतनी असमानता नहीं रह सकती कि उससे कोई कायकर्ता अपनी आय का व्यय न कर सके। और पदार्थ व्यर्थ हो पड़े रहें।

वटवारे के इस ढङ्ग से समाज को इस बात से तो छुटकारा मिल ही जाता है कि एक ओर वहुतरै पदार्थों की अधिकता हो और वे व्यर्थ पड़े रहे तथा दूसरी ओर सहस्रों मनुष्य बेकार रहे और उन्हें काम करने की को कुछ न हो। काम के आधार पर मनुष्यों के आय के वट जाने पर ऐसे काम द्वारा उत्पन्न पदार्थों की पूरी पूरी विक्री हो जाना कभी भी असम्भव नहीं हो सकती वरन् यह तो स्वाभाविक ही है। और साधारणतया सब आय इस प्रकार वट भी जाती है। केवल उस भाग के जो जान वृद्धकर भविष्य में उपज के साधनों की उन्नति के लिए सुरक्षित रक्खा जाता है। ऐसे ही मनुष्य अथवा मशीने भी बेकार नहीं पड़ी रह सकती हैं। इस ढङ्ग में चाहे अन्य कितनी ही वुराइयाँ अथवा कटिनाइयाँ क्यों न हो, एक सब से बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा जनता को माँग और बैकारों दूर हो जाते हैं और उसके स्थान पर उपज में अधिकता तथा निश्चित हो जाते हैं ढङ्ग के अन्य लाभ इस एक बड़े लाभ के सामने से पीछे पड़ जाते हैं।

प्रत्येक मनुष्य अथवा कुटुम्ब की आय अथवा रहन सहन विलकुल समान रहे यह तो सम्भव नहीं और न संगठन से ऐसा कोई अभिप्राय हा है। कुटुम्बों की आय में असमानता तो रहेगी ही।

क्योंकि एक तो भाँति २ के कामों के लिए भिन्न २ वेतन होंगे दूसरे कुटुम्बों में काम करनेवालों को संख्या से भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। जितने यह नहीं कहा जा सकता कि सब को रहने सहने एक ही सी होगी। दो या तीन कार्य कर्ताओं वाले कुटुम्ब को आय अवश्य ही उस कुटुम्ब से कहीं अधिक होगी जिसमें केवल एक ही काम करनेवाला है और अन्य सब उसके आश्रित। परन्तु इस असमानता को सीमा पर ध्यान करना और उसकी तुलना पूँजीवादी देशों में प्रचलित असमानता से करने में दोनों के अन्तर का पूरा पूरा ज्ञान होता है। ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे उन्नतिशाली देशों में जहाँ इस समय भी नीच से नीच श्रेणी के कुटुम्ब को भी, अच्छा स्वास्थ्य तथा निश्चित जीवन व्यतीत करने भर के पदार्थ मिल जाते हैं। उन्हें समाजवादी ढंग में भी इन प्रकार की सुविधा तो रहेगी ही। इसमें वृद्धि ही हो सकती है असमानता सम्भवतः उसके ऊपर ही रहेगी। परन्तु ऐसी असमानता जिसमें सब के लिए एक कम से कम आधार (Standard minimum Standard) सुरक्षित रहता है, उस पूँजीवादी असमानता से कहीं भिन्न होगी जिसमें बहुत से अनाथ और भोख माँगने वाले हो जाते हैं और कुछ ही विशेष धनी और आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले, रहते हैं।

इसके अतिरिक्त काम करने वालों में परस्पर असमानता तथा बिना काम करने वाले और काम करने वालों की असमानता में भी बड़ा अन्तर है। दूसरे काम करने वालों में असमानता कहीं कम रहती है। रूस के अनुभव से कहा जा सकता है कि रूस में ऐसी असमानता १ और १५ के अनुपात से है परन्तु अनुमान लगाया गया है कि पूँजीवादी देश अमेरिका और ब्रिटेन में अशिक्षित मजदूर तथा अति धनी पूँजीपति में १ और ४०,००० का अनुपात बैठता है।

धन-संचय

असमानता की कमी का सामाजिक तथा आर्थिक महत्व भी है

क्योंकि कम से कम आय से १५ गुनी अधिक आय भी सरलता से आवश्यक पदार्थों और सेवाओं में व्यय की जा सकती है। परन्तु ४०,००० गुनी आय इस प्रकार व्यय नहीं की जा सकती और स्वभावतः संचित भी न रहेगी। स्वाभाविक ही जिसके अर्थ यह होते हैं कि उसके द्वारा अन्य उपज के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त किया जावेगा। और उससे लाभ की व्यवस्था होगी जो असमानता को और अधिक बढ़वेगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यक्तिगत धन संचय समाजवाद में हो सकता है, निस्संदेह यह सम्भव नहीं। वैयक्तिक धन संचय के अर्थ उपज के साधनों का व्यक्ति विशेष द्वारा लगातार मोल लेना ही है फिर धन संचय राका कैसे जाता है? आय को असमानता में कमी होने और उपज के साधनों के स्वामित्व से लाभ न मिलने से व्यक्तिगत धन संचय अनावश्यक ही हो जाता है। व्यक्ति विशेष के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह अपनी आय को आवश्यक पदार्थों और सेवाओं में व्यय कर दे। परन्तु यह कहा जा सकता है कि अधिक शिक्षित और उसी के अनुसार अधिक वैतनिक अपनी आय का कुछ भाग बचा सकते हैं। और उससे उपज के साधन मोल ले सकते हैं। परन्तु वास्तव में यह भी सम्भव नहीं। समाजवादी संगठन में उपज के साधन बँचे ही नहीं जाते। किसी कारखाने के शेयर अथवा स्टॉक जिससे उस पर स्वामित्व मिल सके, विकते ही नहीं।

सोवियट रूस में किसी व्यक्ति के लिए भी यह सम्भव नहीं कि वह किसी कारखाने अथवा रेल का कोई शेयर अथवा स्टॉक मोल ले सके। चाहे जितना भी धन उसके पास संचित हो। स्पष्ट शब्दों में, निश्चित योजना के आधार पर होने वाली उपज अथवा समाजवादी शासन में उपज के साधनों के किसी भाग का भी व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में जाने की प्रायः कानूनन मनादी रहती है।

कुछ-थोड़े से औजारों को छोड़ कर जिनसे किसान व स्वतन्त्र

कारोगर काम करते हैं। सहयोगी समितियों के अधिकार में रहने वाले साधन भी व्यक्तियों के हाथ में नहीं कहे जा सकते। वे किसी की निजी सम्पत्ति ही नहीं लेते। उन पर भी समाज को ही अधिकार रहता है। परन्तु ऐसे उन साधनों तक संगठन के कारण पहुँच नहीं हो पाती।

वैयक्तिक पूँजी

अस्तु, इस प्रकार समाजवाद में वैयक्तिक पूँजी की सम्भावना ही नहीं रहती। मनुष्य अधिक आय निस्संदेह संचय कर सकते हैं। परन्तु ऐसा करने पर वे उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकते। केवल उसे संचित ही रख सकते हैं। और वह भी सम्भवतः सिक्के के रूप में ही आज कल सोवियट प्रजा तन्त्र रूस में इस प्रश्न के धन से शासन पत्र मोल (Government Bonds) लिये जाते हैं, जिन पर थोड़ा ही सूद मिलता है। और वह थोड़े ही समय के लिये रहता है। यह भी प्रायः प्रारम्भिक समय के आर्थिक संकट से ही चला है और सम्भवतः शीघ्र बन्द भी हो जावेगा। देश के उद्योगों के लिये प्रयाप्त धन मिल सकने और मनुष्यों को भविष्य के लिये प्रबन्ध की चिन्ता न रहने पर यह सूद की पृथा का ही अन्त हो जावेगा। समाज सेवा की भावना बढ़ने और समाज में पदार्थों की अधिकता हो जाने से, ऐसी चिन्ता रहेगी ही नहीं। और न फिर धन से संचय ही होगा। इसमें थोड़ा समय अवश्य लग जावेगा और उस समय तक निरर्देह इस प्रकार शासन को (Governments Bonds) में रुपया लगाया जायगा। परन्तु यह सदा रहने वाली बात नहीं है। और न किसी समाजवादी शासन में बहुत समय तक रह ही सकती है। जब समाज में मनुष्यों को बुढ़ापे, दुर्घटनाओं इत्यादिक के लिए संरक्षणों की आवश्यकता ही न रहेगी, वे स्वयं ही ऐसे व्यर्थ धन संचय से उकता जावेंगे।

अन्य परिभाषा

इस आधार पर समाजवाद को एक दूसरी परिभाषा भी की

जा सकते हैं। कि समाजवाद वह संगठन है जिसमें केवल प्रयोग के पदार्थ ही व्यक्तियों के हाथ में रहने हैं, उपज के साधन नहीं। इस परिभाषा से समाजवाद में वैयक्तिक सम्पत्ति के सम्बन्ध का भ्रम दूर हो जाता है।

समाजवादी संगठन की अत्यावश्यक तथा प्रारम्भिक शर्त यह है कि उपज के साधनों में वैयक्तिक सम्पत्ति का अन्त हो। परन्तु इससे यह अभिप्राय नहीं कि प्रयोग के पदार्थों में भी वैयक्तिक सम्पत्ति का रहना अनावश्यक तथा अवान्छनीय है। इसके विपरीत समाजवाद ऐसी निजी सम्पत्ति तो बढ़ाना ही चाहती है। ताकि जनसाधारण के पास प्रयोग के पदार्थ अधिक से अधिक संख्या में रहे। यह तो पूँजीवाद का ही कलंक है कि उसमें ७० प्रति शत मनुष्य, इस निजी सम्पत्ति से भी रहित रहते हैं और उनके पास (आवश्यक पदार्थ), प्रयोग करने भर को भी नहीं रहते।

यह भी कह सकते हैं कि समाजवादी संगठन का उद्देश्य समाज में प्रयोग के पदार्थों की अधिकता करना है ताकि वे इन पदार्थों का पूरा पूरा भोग कर सकें। उनके पास भोजन वस्त्र, निवास स्थान वागा, बगीचे, मोटर तथा भाँति भाँति के अन्य प्रयोग के पदार्थ अधिक से अधिक संख्या में रहे। उन्हें कभी भी इन पदार्थों की कमी न होने पावे।

पूँजीवादियों के कार्य

पूँजीवादी समर्थकों के द्वारा समाजवाद के विषय में इतना भ्रम फैला दिया गया है कि लोग पदार्थों की इस प्रकार अधिकता को समाजवाद के सिद्धान्त से हटाना तक कहने लगे हैं।

सोवियट रूस में दैशवासियों के पास इन प्रयोग के पदार्थों की अधिकता देखकर वे उसे समाजवाद के सिद्धान्त से हटा हुआ कहते हैं। पर वास्तव में सिद्धान्त से हटाना तो तभी

होगा जब इन पदार्थों के स्थान में ऐसे पदार्थों के बनाने के साधन व्यक्ति विशेष के हाथ में आ जावें। और इन पर व्यक्तियों का आधिपत्य अथवा स्वामित्व हो जावे। परन्तु ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। केवल दैशवासियों के पास अधिक संख्या में ऐसे पदार्थों का होना समाजवाद से हट जाना नहीं कहा जा सकता। समाजवादी आर्थिक संगठन का तो यह पहला काम है कि आवश्यक तथा प्रयोग के पदार्थों की अधिकता हो। संगठन पूर्ण हो ही नहीं सकता जब तक कि दैशवासियों के पास उनकी आवश्यकता के पदार्थ प्रयाप्त संख्या में न हो जावें।

अस्तु, समाजवाद में, आय का बटवारा समानता के आधार पर न होकर प्रत्येक मनुष्य के काम की संख्या और गुण के आधार पर होता है। मनुष्यों की आय में असमानता रहती है परन्तु बहुत अधिक असमानता नहीं रहने पाती। काम के बिना केवल साधनों के स्वामित्व के कारण आय मिलना समाप्त हो जाता है। वैयक्तिक धन संचय का अधिकार तो रहता है परन्तु इस धन से वे प्रयोग के पदार्थ ही ले सकते हैं, उपज के साधन नहीं। वे तो बेचे ही नहीं जाते। बेकारी दूर हो जाती है। और पदार्थ अधिक संख्या में निश्चित रूप से रहते हैं। मनुष्यों के पास आवश्यक पदार्थों की कमी नहीं रहती वरन् उनकी अधिकता होती है। समाज के रहन सहन में वृद्धि होती है। दैश की उपजाऊ शक्तियों का पूरा प्रयोग होता है और उनसे उत्पन्न पदार्थों का पूरा भाग किया जाता है। वे व्यर्थ नहीं पड़े रहते। और न कल कारखाने की मशीनें ही बेकार रहती हैं। सब के काम करने का अवसर मिलता है। और सब अपनी शक्ति भर काम करके अपनी योग्यतानुसार वेतन पाते हैं। और उस से सुखी जीवन बिताते हैं इससे अधिक और चाहिये भी क्या—



वर्गों का अंत

समान अवसर

पिछले परिच्छेद में बतलाया जा चुका है कि पूँजीवादी व्यवस्था में समाज दो भिन्न २ वर्गों में विभाजित हो जाता है। यह भिन्नता उनकी आय के परस्पर विरोधी आधारों पर ही आश्रित रहती है। उपज का जितना अधिक भाग पूँजीपतियों को मिलेगा, उतना ही कम मजदूरों के लिये बचेगा। और इसी प्रकार इसके विपरीत मजदूरों को अधिक भाग मिलने पर पूँजीपतियों के लिये उतना ही कम रहेगा। इन परस्पर विरोधी हितों के आधार पर ही वर्तमान पूँजीवादी समाज को घातक नींव पड़ी है। और इसी पर संगठन का ढाँचा बना है।

वर्गों का अन्त हो जाने से समाज को एक बड़े संकट से छुटकारा मिल जावेगा। इससे लाभ तो स्पष्ट ही है। और इसी कारण इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं।

ऐसे समाज में सब मनुष्यों को एक ही आधार पर जीवन निर्वाह के लिये आय मिलेगी। और इस प्रकार सबके हित स्वाभावतः एक से ही होंगे। ऐसे वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा पूँजीवादी व्यवस्था में

जहाँ थोड़े से मनुष्य उपज के साधनों के स्वामित्व से धन प्राप्त करते हैं, ऐसे वर्ग के रहने हुए समान अवसरों का मिलना, कई कारणों से प्रायः असम्भव सा हो है। परन्तु वर्गों का अन्त हो जाने पर सम्मिलित समाज में ऐसे अवसर सभी को मिलते हैं।

यह वर्गों का अन्त समाजवादी संगठन में हो हो सकता है। जहाँ केवल काम के लिए ही आय मिलती है। स्वामित्व अथवा अन्य किसी कारण वश किसी को भी आय नहीं दी जाती। और तभी इन वर्गों का अन्त हो पाता है।

समाजवादी संगठन के विरोधियों का ऐसा कहना है कि काम ही के लिये आय मिलने पर भी, 'अच्छे वेतन वाले मजदूरों को अथवा उनके पुत्रों को, अधिक सुविधा मिलेगी, परन्तु संगठन में ऐसी सुविधाओं का प्रभाव जन सेवा, सरकारी शिक्षा, निर्वाह भत्ता इत्यादि के प्रबन्ध से कम कर दिया जाता है। सामाजिक असमानता रहने पर भी, अन्य प्रकार की विशेष सुविधाएँ जो पूँजीवाद में प्रायः छिपी रहती हैं, इस संगठन में रहने नहीं पाती। अथवा अन्य किन्हीं उपायों से उनका प्रभाव कम किया जाता है।

मानसिक शक्ति का विकास

वर्गों के अन्त से एक लाभ यह ही होता है कि ऐसे वर्ग रहित सम्मिलित समाज में मानसिक शक्ति का विकास विशेष कर होता है। संगठन के कार्य में अनुभवी व्यक्तियों और शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता तो रहती ही है। वरन् उनकी माँग बढ़ ही जाती है। समाज के नेता प्रायः मौखिकी पूँजीपति वर्ग ही से होते ही हैं। और वास्तव में उन्हीं में से ही भी सकने हैं क्योंकि इन्हीं ही ऐसे काम के अवसर मिलते हैं। मजदूर अथवा अन्य कार्य करने वाले तो अपने जीवन निर्वाह के चक्कर में ही दिन रात चिन्तित रहते हैं। सूक्ष्म वृक्ष की वात निकाल सकने का तो उन्हें अवसर ही नहीं मिल

पाता। मध्यम श्रेणी से अवश्य कुछ जन सेवक तथा परोपकारी व्यक्ति निकलते हैं। जो न्याय, धर्म, अथवा साधारण हित के विचार से मजदूरों का पक्ष लेते हैं और उन्हें पूँजोपतियों की धन लोलुपता से बचने में सहायता देने हैं।

इसके विपरीत वर्ग रहित समाज में, हितों के परस्पर मेल से ऐसे जन सेवक केवल एक वर्ग, ही सीमित न रहकर सम्पूर्ण समाज से ही निकलते हैं। दासता और निस्सहायता का वातावरण दूर हो जाने पर, वैसे ही मनुष्यों की विचार-शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रकृतियों के मनुष्य अपने अपने विषयों, विज्ञान, कला, शिक्षा, शासन इत्यादि में, अग्रसर होने का पूरा अवसर मिलता है। पेट की चिन्ता और जीविका की अनिश्चिता के कारण पूँजोवाद में वे इस ओर ध्यान देना तो दूर की बात है विचार तक भी नहीं कर पाते हैं। विचारशील मनुष्य अवसर न मिल सकने के कारण छिपे ही पड़े रहते हैं और उनको मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का लाभ भी नहीं मिल पाता। इस प्रकार देश को यह शक्तियाँ व्यर्थ हो पड़ी रहती हैं। समान अवसर की व्यवस्था तथा स्वतन्त्र वातावरण के कारण ऐसी शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग भी देश को मिल सकेगा।

सामाजिक शान्ति

इसके अतिरिक्त सामाजिक शान्ति के लिये भी ऐसी श्रेणी संघर्ष का अन्त परमावश्यक हो है। क्योंकि जब तक समाज में ऐसी असमानता रहेगी कि कुछ व्यक्ति तो अपने स्वामित्व के कारण अधिक लाभ उठावे और दूसरे, कल कारखानों में काम करके अधिक परिश्रम के उपरान्त भी जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक धन न प्राप्त कर सकें, सामाजिक शान्ति होना असम्भव ही है। मनुष्य समाज का इतिहास इसका पूर्णतया साक्ष्य है। समान अधिकार न रहने से शासक और शासितों में सदैव ही कुछ न कुछ झगड़ा चलता

रहता है। स्वेच्छा से कभी भी इस प्रकार परस्पर मेल नहीं रक्खा जा सका है। धन अथवा बल से व्यक्ति दबाए अवश्य जा सकते हैं परन्तु उनमें स्वाभाविक मैत्री के भाव उत्पन्न नहीं किये जा सकते हैं। अवसर मिलने पर स्वाभाविक ही उनकी इच्छा प्रतिकार की होगी। वास्तविक शान्ति तो समान अवसर अथवा समाजवादी संगठन तथा वातावरण में हो रह सकेगी।

अयोग्यता का ढोंग

यही नहीं आश्चर्य तो यह है कि मजदूरों की कमजोरी और निर्धनता का बुरा लाभ उठाया जाता है। निर्धनता के कारण वे अच्छा भोजन नहीं कर सकते। बड़े तथा स्वच्छ घरों में रह नहीं सकते। स्वच्छ वस्त्र नहीं पहन सकते और न रुगिनावस्था में उनकी औषधि इत्यादि का हो सुचित प्रबन्ध रहता है। प्रायः इसी कारण वे अस्वस्थ भी रहते हैं। परन्तु इस निर्धनता और अस्वस्थता को दूर करने, अथवा उनकी स्थिति सुधारने के स्थान पर कहा जाता है कि मजदूर तो पूँजीपतियों से कम बुद्धि और योग्यता वाले होते हैं। उन्हें नीच श्रेणी का वतलाये जाता है। इससे बड़ा अंधेर और हो ही क्या सकता है।

एक ओर तो मजदूरों को विकास का अवसर न मिले। उन्हें आवश्यक सामग्रियाँ तक प्राप्त न हो सकें। और वे वैचारे इस परिस्थिति में किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करें। इसके विपरीत यह कहा जावे कि उनमें योग्यता कम होती है, आज, वे पूँजीपतियों की भाँति स्वतन्त्र रह ही नहीं सकते हैं। मजदूरों को भी पूँजीपतियों की ही भाँति अधिक वेतन और लाभ मिले। उन्हें भी, अधिक नहीं, तो समान अवसर प्राप्त हो, तब इस बात की तुलना हो सकती है कि इनमें कौन नीच अथवा उच्च श्रेणी का है। वर्तमान तुलना के आधार पर इस प्रकार का तर्क किसी प्रकार भी न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता।

मनुष्य समाज की उन्नति, उसके विकास अथवा पतन में समाज-वादी अथवा साम्यवादी नीति का बड़ा महत्व रहा है। इस प्रकार समाज के श्रेणियों में विभाजित रहने से ही इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक सभ्यता की उन्नति समाज में विभाजन से ही हुई है और अन्त में उसका रूप शासक व शासित का ही रह गया है। सभ्यता के विकास के इतिहास से यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि समाज में कोई विशेष विभाग नहीं है। फिर ज्यों ज्यों उनमें से श्रेणी विभाग होने गये, नई नई सभ्यताएँ उतनी ही बढ़ती गईं। इनका विकास भांति भांति से भिन्न भिन्न धाराओं में हुआ। परन्तु अन्त में सदैव ही दो श्रेणी रह गई हैं। एक शासक द्वितीय शासित। शासक द्वारा शासित पर अपने विचार सदैव ही लादे जाते हैं कभी भी अपनी स्वेच्छा से उन्होंने ने सम्भवतः उन्हें स्वीकार नहीं किया है क्योंकि अधिकतर सभ्यताओं में शासकों ने विशेष अधिकार अपने लिये ही सुरक्षित रखे हैं। और शासन का बोझ शासित पर बांटने की को चेष्टा की है। और ऐसी सभ्यता को मनुष्य समाज की उन्नति में एक पग आगे कहा जाता है। यदि ऐसा हो भी तो भी इस कथित अप्रता का बड़ा मूल्य है, क्योंकि ऐसी सभ्यता में शासक ही शासित पर दबाव डालने हैं और उत्तर में शासितों की ओर से उनका लगातार विरोध रहता है। शासित उनके आदेशों को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेने हों अथवा सुख से इतनी कठिनाइयों को झेलते हों, ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसमें इन्हें लाभ तो कम ही होता है। इस प्रकार इस समय तक सभ्यता अल्प संख्यक शासकों द्वारा ही जन साधारण पर लादी गई है और वह ही उसके लाभ का अधिकतर भोग करते हैं। आज से पूर्व कभी श्रेणी रहित समाज स्थापित हुआ हो नहीं। वास्तव में जब तक समाज में ऐसी श्रेणियों का अन्त नहीं होता, स्वेच्छा की सभ्यता स्थापित हो नहीं हो सकती क्योंकि श्रेणी रहित समाज में ही प्रत्येक को समान अवसर मिलते हैं और उसे ही सब अपनी इच्छासे स्वीकार भी करेंगे।

पूँजीवादी सभ्यता के अवगुण और उसकी कमी के प्राप्त अनुभवों से अधिकतर लोगों को इस प्रकार श्रेणी रहित समाज की

आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। बहुतां का तो यहाँ तक कहना है कि पूँजीवादो सभ्यता प्राचीन असमानता से भी अधिक अच्छी नहीं ।

श्रेणी रहित समाज की इस समय केवल आवश्यकता ही नहीं वरन् सम्भावना भी है। उपज इतनी है कि शासक के दिन प्रति दिन बढ़ते हुए कर्मचारियों, विज्ञाताओं, कलाकारों तथा प्रणाली के अन्य आवश्यक व्ययों को उठाने के उपरान्त भी, जनता को स्वतंत्र और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिये काफ़ी धन बच सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसे समाज की स्थापना हो सकती है जिससे सम्पूर्ण जनता को हो लाभ पहुँचा सके। वर्तमान श्रेणी समाज सबसे अधिक अस्थिर और अनिश्चित रहा है। इस संगठन के अन्तिम स्वरूप में शासकों को प्रायः सभी कार्यों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष यह कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य रहती है कि कहीं पर भी उनके शासक रहने में कोई कमी न होने पावे। वास्तव में उनका प्रत्येक कार्य इसी भावना को बढ़ानेवाला हो होता है। और यदि कहीं उनके कार्यों से उनके (शासकों) अधिकारों अथवा सुविधाओं में कोई कमी होती प्रतीत होती है। तो तुरन्त उनमें परिवर्तन हो जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब कि ऐसे समाज में कोई कार्य ही नहीं किया जा सकता है, ऐसी चेष्टा भी नहीं हो सकती जिससे संगठन की स्थिरता को धक्का लगे। संगठन की नींव को हानि पहुँचाने वाले विचार ही असम्भव कर दिये जाते हैं। उनके अनुसार कार्य होना तो दूर की बात है। शासक वर्ग सर्वव्यापी उपायों से जिन्हे वे स्वयं ही समझ सकते हैं, केवल शासितों को ही नहीं दबाते, वरन् किसी स्वतंत्र विचार तथा कार्य शील मनुष्य को चाहे वह अपने ही दिल का क्यों न हो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में बाधक होते हैं। उनको भय रहता है कि कहीं यह कार्य शीलता, उनकी सुस्त तथा अकर्मण्य स्थिति को संकट में न डाल दें क्योंकि वे स्वयं तो कुछ काम करते ही नहीं। और न करना ही चाहते हैं। इसी लिये उनकी यह चेष्टा रहती है कि

दूसरे भी कुछ काम न कर सकें। और न उन्नति की ओर विचार हो करें। उन्नति शाली और कार्य शील होने पर वे कही उनका ही स्थान न ले लें, किसी समाज के लिये यह नाश के लक्षण हैं। ऐसे समय में कलाकारों को देखने, कवियों को सुनने तथा विज्ञान-दाताओं की जाँच करने इत्यादि की हो मनादी हो जाती है। कही उनके आविष्कारों से समाज को वर्तमान स्थिति में गड़बड़ी न आ जावे। अतः इस प्रकार के सब कार्य ही वे बन्द करा देते हैं। जिससे समाज की उन्नति ही नहीं हो पाती। यही नहीं, इसका परिणाम यह भी होता है कि धीरे धीरे यह कलाकर, विज्ञता इत्यादि भी वातावरण वास्तविकता तथा स्थिति का पूरा-र ज्ञान ही नहीं कर पाते।

श्रेणी वर्ग का प्रभाव उन पर इतना पड़ता है कि वे उसी धारा में विचार करने के अतिरिक्त स्वतंत्र विचार ही नहीं कर सकते अतिरिक्त और न कोई ऐसा कार्य ही हो पाता है। यह भी नहीं कि शासकों द्वारा सदा हो उन्हें ऐसा करने की मनादी होती है परन्तु धीरे धीरे वे स्वयं भी उसी वर्ग के होते जाते हैं, और ऐसे ही कार्य करते हैं, जिससे उनका वर्ग ही आधिपत्य में रहे। परन्तु ऐसी स्थिति वर्ग के अन्तिम समय में ही होती है, जब कि उनका कार्य समाप्त पर होता है अथवा उनका अन्त निकट आ जाता है। प्रारम्भ में जब देश के उद्योग धन्धों की उन्नति के लिये पूँजीवादी व्यवस्था प्रायः अधिकतर अनिवार्य सी होती है, ऐसी विचार धारा उन में नहीं रहती। उस समय तो वे सब बातों का स्वयं भी विचार कर रहे हैं और ऐसे विचारों की स्वतंत्रता दूसरों को भी देते हैं। शासित को दबाने की तब आवश्यकता नहीं होती और न ऐसे उपायों का ही प्रयोग होता है जिनके कारण पूँजीवादी समाज आज प्रायः एक बड़े कारागार की ही भाँति हो गया है। मजदूरों का भी उस समय तक यही विचार रहता है। कि पूँजीपति संसार के उद्योग धन्धों की उन्नति में इतना कार्य कर रहे हैं और यही समाज के वास्तविक तथा सच्चे नेता हैं

परन्तु उन्नति कर लें पर उस उन्नति शील स्थिति को स्थिर रखने तथा अन्य क्रियाशील और अपने से उत्साही मनुष्यों से अपनी रक्षा के लिये वे ऐसे कार्य कराने लगते हैं। जिसका परिणाम अन्त में उनका विनाश ही होता है। क्योंकि वे न तो स्वयं उन्नति का मार्ग सोचते अथवा ढोंग निकालते हैं, और न दूसरों को ही ऐसा करने देते हैं। धन विलासिता, भोग ऐसी ही अन्य बातों में पड़ जाते हैं जिस के फल स्वरूप उन्नति बन्द हो जाती है। अवनति होना प्रारम्भ होता है और धीरे-२ ऐसे लोग बिल्कुल ही मिट जाते हैं। कितने ही शासकों की यही गति हुई है। मान तथा अधिक धन मिल जाने पर उनमें अवगुण आ जाते हैं जिनका आवश्यक परिणाम विनाश ही होता है। सदियों से ऐसा ही चला आता है।

इस समय स्थिति ऐसी ही है। ऐसे शासक वर्ग की आवश्यकता ही नहीं रही है। आज का शासक वर्ग समाज की उन्नति का कोई कार्य नहीं करता वरन् उनसे उन्नति के मार्ग में बाधाएं अथवा रोड़ पड़ते हैं। चाहे वह आर्थिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र में क्यों न हों। धनी अधिकतर सुस्त और काहिल हो गये हैं। वे विलासी, भोगी और झुकमी हैं तथा समाज पर एक बोझ की भाँति हो रहना चाहते हैं। उन का स्पर्श मात्र ही पदार्थ को बुरा और दुर्गन्धो बना देता है। उनका मूल्य घट जाता है। उनके कार्य व्यर्थ उन का जीवन निस्तार, तथा नाशप्राय होता है। यह दशा तो ऐसे धनाढ्यों की है जो काम नहीं करते परन्तु इन के अतिरिक्त ऐसे भी धनी हैं जो कुछ न कुछ कार्य करते हैं। वह तो समाज के लिये विशेष हानि कारक हैं क्योंकि अपने आर्थिक संगठन से वे ऐसा गुह बनाते हैं तथा जीवन के लिये आवश्यक पदार्थों में उन की ऐसा नीति रहती है जिस से संसार का आर्थिक जीवन ही बिगड़ जाता है। इन बातों में पास खेल्ने की भाँति ही उनके कार्य रहते हैं। समाज इनके लिये पासे की गुट्टी ही होती है जिसे वे जिस प्रकार चाहे अपने दांव पर लगा दे और जहां चाहे फेक दे। जीवन का मूल्य ही उनके सम्मुख कुछ नहीं। उन्हें केवल लाभ होना चाहिये। पूँजी अपने

देश के धन्यै से हटाकर अन्य देशों को भेज दी जाती है। अथवा फिर उसका प्रयोग अपने देश में किया जाता है। जिससे भी उन्हें अधिक लाभ हो। कितनी आवश्यक पदार्थ की संख्या में कम करके अधिक लाभ उठाने की नियत से वे पूँजी का प्रयोग अन्य पदार्थों में भी लगा देते हैं। राजनैतिक संकटों से बचाने के लिये अपनी पूँजी अन्य देशों में भेजने की नीति निर्धारित करते हैं। देश की भलाई हो अथवा बुराई इससे उन्हें क्या प्रयोजन। उनका स्वार्थ पूरा होना चाहिये। अन्य देशवासी जिसमें अधिकतर वे होते हैं जिनकी सहायता और परिश्रम से ही यह पूँजी बनती है, चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट भेलें और मर ही क्यों न जायें, उन पर इसका प्रभाव ही नहीं होता। धन लोलुपता से वे प्रायः अन्धे ही हो जाते हैं। देश विदेश से उचित अनुचित सम्भौता करते हैं। व्यापारियों में हार जीत होती है। पदार्थ अन्य देशों में भेज दिये जाते हैं और असंख्य स्त्री, पुरुष तथा बच्चे जिनके कठिन और सर्वतर परिश्रम से यह पदार्थ बनाते हैं भोजन तक नहीं पाते। संसार का नाचघर हो जाता है जिसमें नाम के आधार पर पूँजीपति नाचा करते हैं। उनमें हार जीत रहती है और उसके परिणाम में अलंख्य अशिक्षित निर्धन मनुष्य बँगे तथा भूखे रहते हैं। तथा भाँति भाँति के कष्ट उठाते हैं। वे बैचारे कुछ कह भी नहीं पाते। क्योंकि उन में इतनी शक्ति नहीं होती। परस्पर दांव पैच में कुछ लोग इतने शक्ति शाली भी हो जाते हैं कि उन्हें पराजित करना भी प्रायः असम्भव हो जाता है। इस के विपरीत दूसरे लोग ऐसी स्थित में होते हैं कि स्थान बदले बिना विजयी हो ही नहीं सकते। यह लोग फिर मजदूरों और किसानों का संगठन करते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर प्रचलित शासन को परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। एक बार मार काट होती है और जन साधारण को उस में प्राणों की आहुति देना पड़ती है ताकि एक प्रकार के जुआरियों के स्थान में उसी ढंग के दूसरे जुआरी आसनारुढ़ हो जावे। अथवा एक पूँजीपति या शारूक के स्थान में उसी नीति को चलाने वाला दूसरा पूँजीपति अथवा शारूक आजावेगा। समाजका अन्तिम रूप यही होता है

बड़े बड़े देशों को सर्व व्यापी महा युद्ध में सम्मिलित होना पड़ता है। और उस के घातक परिणाम संसार को ही प्रभावित करते हैं।

इन अवगुणों से बचाने के लिये ही श्रेणी रहित समाज की आवश्यकता है। और समाजवादी संगठन में ही यह दूर हो सकते हैं। वर्गों का अन्त समाजवादी संगठन का आवश्यम्भावी परिणाम है जिसमें उपज एक निश्चित योजना के आधार पर होती है और उस का फल उपज करने वालों में कार्य की संख्या तथा गुण के अनुसार बाँटा जाता है।



काम करने की प्रेरणा

—:o:—

पूँजीवाद

—

समाजवाद और साम्यवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि इसमें मनुष्यों को काम करने की इच्छा ही न रहेगी। और बिना इस प्रकार की इच्छा के किसी आर्थिक संगठन से तनिक भी लाभ नहीं हो सकता। वास्तव में किसी आर्थिक संगठन के लिये आवश्यक है कि उसके प्रत्येक काम करने वाले में स्वेच्छा पूर्ण, संलग्नता तथा लगातार काम करने की इच्छा हो। तभी संगठन सफल हो सकता है।

देखना यह है कि पूँजीवाद, समाजवाद अथवा साम्यवाद किसमें कितना २ प्रोत्साहन इस इच्छा की ओर है और क्या २ ?

पूँजीवाद में कुछ काम करने वाले निस्संदेह अधिक परिश्रम करते हैं उनसे ऐसा कराने के लिये इस संगठन में पुरस्कार और दण्ड दोनों ही का प्रयोग होता है। पुरस्कार भी दो प्रकार के होते हैं प्रथम तो वह जो पूँजीपतियों को दिया जाता है। वे तो अपनी पूँजी कल कारखानों में लगाते हैं और स्वयं उन्हें चलाते हैं और उनके द्वारा लाभ उठाते हैं अथवा उसे हिस्सों के मोल लेने और बेचने में लगाते हैं। प्रायः इन कामों का पुरस्कार भी बहुत

बहुत होता है इसके अतिरिक्त दूसरा पुरस्कार, वकीलों, डाक्टरों, नाट्यकारों, लेखकों, इन्जिनियरों इत्यादि को दिया जाता है। इनका भी पुरस्कार बहुत अधिक होता है कि वे स्वयं ही, किसी न किसी उपाय से कोई न कोई उपज का साधन स्वयं ही, माल ले लेते हैं। और पूँजीपति वर्ग में ही सम्मिलित हो जाते हैं।

पुरस्कार द्वारा काम करने की इच्छा तो इन्हीं वर्गों में पैदा की जाती है अधिकतर मजदूर तो और ही कारणों से काम करते हैं। हाँ साधारणतया लोगों का ऐसा विचार अवश्य है कि अधिकतर शारीरिक व मानसिक काम करने वाले, पुरस्कार द्वारा ही काम करने को प्रोत्साहित किए जाते हैं और उसी कारण वे बिना किसी दबाव के सुबह से शाम तक अपने पुरस्कार के लालच में काम करते हैं। कहा भी यही जाता है। मजदूरों को बतलाया जाता है कि प्रारम्भ में सबही बराबर होते हैं और बाद में लोग अपने काम, चातुर्य, कौशल से धनी हो जाते हैं और दूसरे अपनी अकर्मण्यता, तथा मूर्खता से निधन हो रह जाते हैं परन्तु वास्तव में स्थिति ऐसी है नहीं। अमेरिका तथा ब्रिटैन पूँजीपति देशों में प्रारम्भ में भले ही इस प्रकार धनी हो जाने का लालच मजदूरों को काम करने के लिये प्रोत्साहित करता हो परन्तु अब तो, यह लालच मजदूरों को काम करने के लिये प्रोत्साहित करने में अधिक महत्व का नहीं।

पूँजीवाद में, मजदूरों को काम के लिये प्रोत्साहित कराने को एक दूसरे प्रकार के पुरस्कार से भी प्रयोग होता है और पहिले का यह अधिक वास्तविक भी है। उपज के साधनों को माल ले सकने का अवसर पूँजीवाद में, मजदूरों को कदाचित ही कभी मिलता हो, परन्तु अच्छे और परिश्रमी मजदूरों को उनके वेतनों में वृद्धि अवश्य दी जाती है ताकि वे अपने रहन सहन को अच्छा कर सकें। अच्छे काम के लिये अधिक वेतन देकर मजदूरों को अपने काम में शिजा प्रदान करने और कुशल होने की भावना

उत्पन्न को जाता है ।- प्रायः काम के अनुसार वेतन देकर उन्हें शीघ्र और अधिक काम करने को प्रोत्साहित किया जाता है ।

बेकारी का भय

इस प्रकार के पुरस्कार अधिक वास्तविक है । और उनसे काम में प्रोत्साहन अवश्य मिलता है । पूँजीपति बनने का अवसर प्रदान करने वाले पुरस्कार तो वास्तव में व्यर्थ हो हैं क्योंकि अधिकतर मजदूरों को कभी ऐसे अवसर मिलते ही नहीं । दूसरे प्रकार के पुरस्कारों का प्रयोग भी पूँजीवाद में अब बहुत कम हो गया है, शिक्षित तथा अशिक्षित मजदूरों के वेतनों में अन्तर भी अब अधिक नहीं । इस प्रकार मजदूरों को काम के लिये प्रोत्साहित करने वाले ये पुरस्कार पूँजीवाद में अधिक प्रयोग में नहीं आते । वास्तव में पूँजीवाद में मजदूर दण्ड के भय से ही काम करते हैं । उन्हें पूँजीपति बनने का अवसर मिलने का लोभ और न अधिक वेतन को आकांक्षा अपने काम पर रहने के उत्साहित करती है । वरन् इस भय से कहीं काम से निकाल न दिए जावे और अपने अन्य साथियों की भाँति उन्हें भी बेकार रहकर भूखे मरना पड़े, वे अपने काम पर जमे रहते हैं । और बड़े परिश्रम से काम भी करते हैं, चाहे उन्हें कितनी कम वेतन ही क्यों न मिलें, कभी कभी तो कम वेतन मिलने पर भी वे इतने अधिक परिश्रम से काम करते हैं कि प्रायः वे रोग ग्रसित होकर अकाल मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं । इतना काम और परिश्रम वे क्यों करते हैं । कौन बात उन्हें ऐसा करने को प्रोत्साहित करती है ? उत्तर बड़ा सरल है । और वह है बेकारी का भय । जिसके भयंकर परिणामों को सोचकर वे सतत भयभीत रहते हैं । यह दण्ड मजदूरों को उपज के साधनों के पास पहुँचने तक नहीं देता उनके लिए कारखानों के दरवाजे बन्द कर दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी जीविका निर्वाह ही न कर सकें । सब

मजदूरों को न काम मिल सकने के कारण, काम करने वाले मजदूरों पर पूँजीपतियों का प्रभुत्व और भी अधिक रहता है। क्योंकि निकाले गए मजदूरों के स्थान पर काम करने को सदैव ही सहस्रों बेकार मजदूर प्रस्तुत रहते हैं। और इसी कारण पूँजीपति को कम वेतन देने और अधिक परिश्रम लेने पर भी इस बात का पूरा भरोसा रहता है कि उन्हें काम कराने के लिये मजदूरों को ढूँढ़ने की आवश्यकता न होगी और प्रयाप्त संख्या में मजदूर स्वयं ही उनके पास आ जावेंगे।

पूँजीवाद में, काम का प्रोत्साहन यही बेकारी का भय ही है, जिससे मजदूर केवल काम ही नहीं करते वरन् बड़े परिश्रम से पूरी शक्ति भर काम करते हैं। यह प्रोत्साहन अवश्य है परन्तु इसका आधार पुरस्कार न रहकर दण्ड और दवाव है। सत्य तो यह है कि पूँजीवाद में मजदूरों से बेगार ली जाती है और इन दवावों के रहने से यह बेगार अधिक कष्टकर भी होती है। प्राचीन सेवक वृत्ति में, मालिकों को यह भय रहता था कि यदि उन्होंने अपने सेवकों से अधिक परिश्रम से काम लिया और वे रोग ग्रसित हुए अथवा उससे उनकी मृत्यु ही हो गई, मृत्यु का उत्तरदायित्व उन पर होगा। और सम्भवतः उन्हें आर्थिक हानि भी हो परन्तु वर्तमान पूँजीवाद में तो यह भी नहीं है। कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर वैसे तो स्वतन्त्र रहते हैं। अधिक परिश्रम का काम अस्वीकार करने में उन्हें कोई कानूनी बाधा भी नहीं होती है। जिन शर्तों पर मिल मालिक उन्हें काम पर रखना चाहते हैं, उसे वे अस्वीकार भी कर सकते हैं परन्तु वे ऐसा कर नहीं पाते। क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें अपने जीवननिर्वाह से ही हाथ धोना पड़ता है। तथा उनके बाल बच्चे भूखे मरते हैं। परन्तु उनके इन कष्टों का उत्तरदायित्व किसी दूसरे पर डाला भी नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष में उनका उत्तर दायित्व उन्हीं पर रहता है और वे ही मरते भी हैं।

इस प्रकार पूँजीवाद में मजदूर से वास्तविक अथवा अवास्तविक पुरस्कारों द्वारा काम नहीं करते । वरन् वे काम करने का विवश किये जाते हैं और पूँजीपति उन पर मनमानी शर्तें लगाते हैं जो उन्हें भूख और बेकारी के कारण स्वीकार करनी पड़ती हैं । और उसी से भयभीत होकर वे इच्छा न होते हुए तथा कम वेतन लेकर भी लगातार काम करते रहते हैं । इन परिस्थितियों से निकलने का वे प्रयत्न तक नहीं करते । यहाँ पर भी वही भय उन्हें अपने कर्तव्य से पीछा हटाये रहता है ।

यह प्रोत्साहन तो उन लोगों के लिये हो सकते हैं जो पूँजीवाद में अब भी काम पर हैं । इसके अतिरिक्त १५ प्रतिशत से ३० प्रतिशत मजदूर तो सदैव बेकार हो रहते हैं, और उनके लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन पूँजीवाद में है ही नहीं । इतने नवयुवक स्त्री पुरुषों को काम न मिलना कितने अनर्थ की बात है और विशेषकर ऐसे समय में जबकि वे अपनी शिक्षा समाप्त करके नवीन जीवन में पदार्पण करते हैं । आज पूँजीवाद द्वारा सहस्रों नवयुवकों को बेकार रह कर निराशा और भूख के कष्टों को सहन करना पड़ता है । परन्तु फिर भी यही कहा जाता है कि पूँजीवाद में मनुष्यों को काम के लिये प्रोत्साहित करने वाले प्रलोभन अधिक हैं । आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे बेकार भी इस बात पर विश्वास रखते तथा उसका समर्थन करते हैं । और व्यापार तथा उद्योग धन्धों के व्यक्तिगत अवसरों की स्वतन्त्रता को ही न्यायमत्त मानते हैं । पूँजीवाद के कारण बेकारी और उससे होने वाले क्लेशों को भोगते हुए भी वे सदैव यही कहते हैं कि उद्योगों की उन्नति के लिये वैयक्तिक उद्योग और प्रलोभनों का रहना ही आवश्यक है । और उन्हें रखना ही चाहिये । अन्यथा लोग काम ही न करेंगे । परन्तु इस प्रकार का विचार सदैव नहीं रह सकता । जीवन के अनुभवों का प्रभाव दैर सबेर अवश्य होगा । और इसे समझने में जितना ही विलम्ब होगा । उसका प्रभाव भी उतना ही दीर्घकालीन रहेगा ।

अस्तु, पूँजीवाद के प्रलोभन संक्षेप में इस प्रकार कहे जा सकते हैं:—

(१) अधिक लाभ के प्रलोभन से पूँजीवाद पूँजीपति वर्ग को विशेषकर काम के लिये प्रोत्साहित करता है जिसका फल अन्त में घातक ही सिद्ध होता है ।

(२) अधिक वेतन दैकर पूँजीवाद मजदूरों से एक सीमा तक अधिक परिश्रमी काम ले लेता है वेतन अथवा लाभ की वृद्धि ही इसका प्रलोभन रहता है ।

(३) परन्तु मजदूर वर्ग काम के लिये प्रोत्साहित होने के बजाय अधिकतर काम करने को विवश ही होता है ।

(४) पूँजीवाद का प्रलोभन, प्रलोभन न रहकर भय का ही काम करता है और उसका आधार भी पुरस्कार की आशा के स्थान में भय की आशंका हो जाती है ।

(५) इसमें दबाव से काम होता है । मजदूर भयभीत रहकर काम करते रहते हैं । भले ही इस दबाव और भय में प्राचीन समय के मालिकों के कोड़ों से थोड़ी भिन्नता हो ।

(६) मजदूर वर्ग में जो बेकार हैं उनके लिये इस पूँजीवादी व्यवस्था में कोई प्रलोभन ही नहीं है । उन्हें तो काम करने का अवसर ही नहीं मिलता ।

पूँजीवाद में इसी ढंग पर काम होता है प्रलोभनों द्वारा काम होना, ऐसा कहना तो भूल ही है । वास्तव में काम तो बेकारों भूख और उससे होनेवाले कष्टों की आशंका से ही किया जाता है । प्रलोभन तो केवल कहने मात्र को ही रहते हैं । और न उनका कोई व्योहारिक महत्व ही है । फिर भी, यदि स्वीकार भी कर लिया जावे कि

पूँजीवाद में काम कराने को प्रयाप्त प्रलोभन हैं और इन्हीं के कारण उपज भली भाँति हो जाती है, तो भी केवल इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि इसके स्थान में समाजवादी व्यवस्था हो ही नहीं सकती जब तक कि उसके प्रलोभनों पर भी विचार न हो जावे। देखे समाज-वाद के क्या प्रलोभन हैं ?



काम करने की प्रेरणा

—:०:—

समाजवाद

— — —

पूँजीवादी व्यवस्था में मजदूरों को काम के लिये प्रोत्साहित करने वाले प्रलोभनों पर विचार किया जा चुका है। अब समाजवाद के आधीन इनकी तुलना करना है। तुलना के पश्चात् ही यह कहा जा सकता है कि कौन सी व्यवस्था में काम की इच्छा अधिक है। और उसी के अनुसार व्यवस्था की अच्छाई बुराई का निर्णय हो सकता है।

पूँजीवाद की तरह समाजवादी संगठन में भी यह तो प्रतिबन्ध रहता ही है कि स्वस्थ स्त्री व पुरुष काम न करने से अपना जीवन निर्वाह प्राप्त न कर सकेंगे। उनसे काम कराने के लिए यह एक दबाव रहता है। और निस्संदेह पूँजीवाद से कहीं अधिक सस्ती के साथ इसका प्रयोग समाजवाद में होता है। पूँजीवाद में इसका प्रयोग केवल मजदूर वर्ग के लिये ही होता है पूँजीपति वर्ग के तो बिना काम के ही जीवन की आवश्यक सामग्री प्राप्त हो जाती है केवल यही नहीं, बरन् आवश्यकता से कहीं अधिक संख्या में प्राप्त होता है। उपज के लाभ का एक बड़ा लाभ उन लोगों को मिलता है जो भाग्य अथवा अभाग्यवश पूँजीपतियों के वंश में जन्म लेते हैं। उनसे काम की कभी आशा भी नहीं की जाती।

परन्तु समाजवाद में वे इस प्रकार भाग्य शाली नहीं रह सकने। वास्तव में तो ऐसे लोग अभागे ही हैं क्योंकि बिना काम किए इस प्रकार अधिक धन मिल जाना, उनके तथा उनके बाल बच्चों के लिये भी हानिकर ही सिद्ध होता है। समाज के लिये तो वह ऐसा है ही। सुस्ती, आलस्य, अकर्मण्यता इत्यादिक रोग उनमें सहज ही आ जाते हैं। और उनसे होने वाले दुःखद परिणाम उन्हें भेलना पड़ते हैं।

समाजवाद उन्हें भी अपने जीवन निर्वाह के लिये काम करने को विवश करता है और इस प्रकार उन लोगों का भी जो पूँजीवाद में काम करने से बच रहते हैं काम पर लगा देता है। परन्तु यही नहीं कि काम न करने पर उनके जीवन निर्वाह का ही अन्त कर दे और फिर उन्हें काम न दैकर दूसरे शब्दों में बैकार रख कर, उनका काम करना ही असम्भव कर दे, जैसा की पूँजीवाद में होता है। वरन् मोटे शब्दों में, समाजवाद में प्रत्येक योग्य मनुष्य के लिये काम करना आवश्यक होता है। और साथ ही साथ बेकारी दूर करके उन लोगों के लिये काम करना सम्भव भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त समाजवाद में यह सिद्धान्त पूरे जन समाज पर एक ही ढंग से लागू किया जाता है। पूँजीवाद की तरह केवल पूँजी रहित वर्ग पर ही सीमित नहीं रहता। दूसरे जिस प्रकार पूँजीवाद में पूँजी से लाभ न प्राप्त कर सकने वाला मजदूर वर्ग आर्थिक संकटों के कारण, काम करने को विवश होता है, ठीक उसी प्रकार समाजवाद में मनुष्य काम करना अस्वीकार भी कर सकता है। यदि वह अन्य उचित उपायों से अपने जीवन निर्वाह का प्रबन्ध कर सके। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होती है। और इसी कारण पूँजीपति अथवा उसी प्रकार के अन्य वर्ग समाजवाद के इस ढंग को दासता इत्यादिक नामों से पुकारते हैं। काम का सिद्धान्त सब पर समान लागू होना उन्हें विशेष अखरता है। जो लोग इस समय तक काम करने से बचे रहते हैं, उन पर भी भोजन के लिए ऐसे प्रतिबन्ध लगाना जो अन्य लोगों पर प्रारम्भ से ही रहते हैं,

कुछ धनी लोगों को दासता सी हो प्रतीत होती हैं। परन्तु उस सम्पूर्ण जन समाज को जो निरन्तर काम करके ही अपना पैट भरता है यह थोड़ी सी कुछ लोगों की असुविधा से, उससे होने वाले गुण कही अधिक जचते हैं। वास्तव में तो उन्हें यह कोई असुविधा प्रतीत भी नहीं होती कि कुछ धनी लोगों की सुस्त और बेकार रहने की सुविधा दूर हो जावे और उन्हें भी अन्य लोगों की भाँति ही काम करके अपना जीवन निर्वाह करना हो।

काम छांटने का अवसर

समाजवाद के विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि इसमें काम करने वाले को काम छांटने का अवसर नहीं मिलता। क्योंकि ऐसी व्यवस्था में केवल एक ही मालिक (शासन) रहता है और अन्य सब मजदूर उसी के आधीनस्थ काम करते हैं। मजदूरों को ऐसी स्थिति में अपने मालिक छांटने और उनसे अपने काम के लिये सौदा करने का अवसर नहीं मिलता। परन्तु ऐसा कहना भी नासमझी की बात है, समाजवादी व्यवस्था में ऐसा है। नहीं वर्तमान समाजवादी संगठन में मजदूर नौकर रखनेवाली तीन मुख्य संस्थायें तो है ही (१) शासन अथवा म्युनिसिपल बोर्ड के आधीन संस्थाएँ, (२) काम करनेवालों की (Producers) सहयोगी समितियाँ, और (३) ग्राहकों (consumer) की सहयोगी समितियाँ। और इन सब में भिन्न भिन्न प्रकार की अख्य संस्थायें और हैं जो मजदूरों को काम देती हैं। और इस प्रकार काम को छांटने इत्यादि की सुविधा की कोई कमी नहीं। श्रीमान तथा श्रीमती वेव ने इस प्रकार की संस्थाओं का वर्णन करते हुए कहा है:—

सोवियट रूसमें सैकड़ों ट्रस्ट (Trust) और कम्बाईन (Combines) हैं। वे सब एक से भी नहीं हैं और उनसे भी अधिक भिन्नता रखने वाले हजारों पृथक पृथक कारखाने हैं। जो अपने विशेष कार्यों के लिये स्वतन्त्र रूप से चलते हैं। किसी ट्रस्ट इत्यादि से उनका सम्बन्ध नहीं। उनका उत्तरदायित्व सीधे उच्च अधिकारियों से हो रहता है।

छोटे छोटे देहाती कारखाने, प्रान्तीय संस्थायें, स्वायत्त प्रजातान्त्रिक समितियाँ इत्यादि भी हैं। इनका प्रबन्ध और संगठन रूस के प्रचलित संगठन के समान भी नहीं और न सोवियट यूनियन या उनके प्रतिनिधियों के आधीनस्थ हो हैं। सदस्यों को भाग देने के लिये मजदूर संघ, कारखाना कमेटी इत्यादिक हजारों सहायक तथा सहयोगी समितियाँ हैं जो वटवारे के अतिरिक्त उपज का काम भी करती हैं।

इसी प्रकार इन सब कारखानों में मजदूरों को काम छांटने की अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त जो लोग वेतन के लिये काम न करना चाहे वे सामूहिक खेतों में काम ले सकते हैं। रूस में लगभग ढाई लाख ऐसे खेत भी हैं। और भी, यदि मजदूरों में योग्यता हो, तो वह स्वयं अपनी वस्तु बना कर बेच सकते हैं सम्पादक, सम्पादक, अथवा लेखक हो सकते हैं, घरों की मरम्मत अथवा रँगाई कर सकते हैं। संगीतज्ञ होकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं अथवा कारीगर होकर भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं, वे चाहे तो सहयोगी समितियों में सम्मिलित हो जावे अथवा स्वतन्त्र रूप से ही काम करे। 'केवल एक प्रतिबन्ध उन पर अवश्य है और वह यह कि वे दूसरों को नौकर रखकर उनके वेतन पर काम लेकर लाभ नहीं उठा सकते। अन्य सब बातों में वे पूर्णतया स्वतन्त्र हैं।

इस प्रकार समाजवाद में काम लेने के लिये यह सिद्धान्त तो रहता ही है कि काम करनेवालों को ही आय मिलेगी, ताकि समाज में किसी व्यक्ति के लिये यह सम्भव न रहे कि वह लाभ तो उठा ले परन्तु काम कुछ न करे।

पुरस्कार नीति

मजदूरों से काम लेने वरन् अच्छा काम लेने के लिए समाजवाद केवल इसी सिद्धान्त पर आश्रित नहीं रहता। इसमें पुरस्कार की एक निश्चित नीति भी है ताकि समाज के प्रत्येक मनुष्य से अच्छा और अधिक परिश्रमों काम ठीक प्रकार से लिया जा सके। समान

वेतन की नीति पहिले ही अस्वीकार की जा चुकी है अस्तु अच्छे काम के लिये अधिक वेतन तथा पुरस्कार देने की व्यवस्था समाजवाद में होती है और इस प्रकार पूँजीवाद से अधिक प्रलोभन इसमें मनुष्यों को अच्छा और परिश्रमी काम करने के लिये रहता है ।

इससे एक बड़ा भारी भ्रम भी दूर हो जाता है बहुतों का ऐसा विचार था कि अधिक धन के लालच से ही मनुष्य काम करते हैं और यह अधिक धन पूँजी संग्रह में लगाते हैं । जिसके अर्थ उपज के साधनों का वैयक्तिक अधिपत्य होते हैं जो समाजवादी संगठन में असम्भव है । परन्तु इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता है कि समाजवाद में अधिक वेतन का प्रलोभन देकर काम लिया ही नहीं जा सकता । उपज के साधनों पर अधिपत्य पाने का अवसर न देते हुए स्वयं पूँजीवाद में भी अधिक वेतन के प्रलोभन का प्रयोग होता है । एक सैनिक पदाधिकारी, सवैतनिक दफ्तर अथवा बैंक का कर्मचारी, मजदूर इत्यादि को काम की प्रेरणा करनेवाली यही बात रहती है कि यदि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा वेतन मिलेगा । पूँजीपति होने की आशा उन्हें नहीं होती क्योंकि उपज के साधनों को वे पा नहीं सकते । परन्तु अधिक वेतन की तीव्र इच्छा उन्हें निरसित रहती है ताकि इस बढ़ती से वे आवश्यक पदार्थों को अधिक संख्या में ले सकें और अपने रहन सहन को बढ़ा सकें । पूँजीवाद के अनुभव से भी यह सिद्ध होता है कि काम कराने के लिये अधिक वेतन एक बहुत प्रभावशाली प्रलोभन है उपज के साधनों पर आधिपत्य हो अथवा न हो ।

समाजवाद में इस प्रलोभन का अधिक शक्ति के साथ प्रयोग हो सकता है । सब काम करनेवालों को समान अवसर प्रदान करने की नीति से प्रत्येक कार्यकर्त्ता को अच्छे वेतन वाला काम मिल सकता है । वर्तमान समय में, शिक्षा, वर्ग सम्बन्ध, कौटुम्बिक संकीर्णता इत्यादि बन्धन ऐसे हैं जिनके कारण कार्यकर्त्ता उच्च वेतनवाले बहुत से पदों पर पहुँच नहीं स

इसी कारण उनके लिये इनका प्रलोभन व्यर्थ है। क्योंकि वे भली भाँति जानते हैं कि चाहे जो कुछ भी वे करें उन्हें वे पद मिल नहीं सकते समाजवाद ऐसे बन्धनों का अन्त कर देता है और ऐसा करके मजदूरों के अच्छे काम के लिये विशेष प्रोत्साहन देता है।

वेतन योजना

समाजवाद में अच्छे काम के लिये अधिक वैयक्तिक पुरस्कार को नीति विशेष रूप से चलाई जाती है जहाँ जहाँ और जब भी सम्भव हो, काम के अनुसार वेतन देने की व्यवस्था (Piece wage) की गई है। इसके अतिरिक्त काम की माँग के अनुसार सब काम करने वालों के वेतन एक निश्चित वेतन दर पर निर्धारित किये गये हैं। एक प्रकार के कामों के लिये एक नियत वेतन निश्चित है और उससे कम अथवा अधिक, काम की संख्या और गुण को ध्यान में रखकर भिन्न २ काम करनेवालों का वेतन एक निश्चित योजना के आधार पर नियत होता है।

मजदूर संघ, किसी एक व्यापार के मजदूरों को भाँति भाँति के दरजों में बाँट देता है। कम से कम परिश्रम से लेकर अधिक से अधिक शिक्षित काम के दरजे बना दिये जाते हैं। और फिर प्रत्येक दरजे के लिये प्रात घन्टा की एक रकम निश्चित कर दी जाती है। अथवा अधिक कारीगरी के कामों में जितना भी अधिक अन्तर इस घण्टे की दर में सम्भव हो रक्खा जाता है ताकि अधिक से अधिक प्रलोभन रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि काम करने वाले इन भिन्न भिन्न दरजों में किस आधार पर रक्खे जाते हैं। आधार उन काम करने वालों की प्रार्थना होती है। नीचे दरजे में काम करने वाला मजदूर ऊँचे दरजे में रक्खे जाने की माँग कर सकता है। और यदि वह उस दरजे का अधिक कारीगरी का काम कर सकता है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है। दूसरे दरजे में काम करने का अवसर मिलने और

उस स्थान पर भली भाँति काम करने लगने पर उसे उस दरजे का वेतन भी मिलने लगता है।

मानसूचक पदवियाँ

इससे यह स्पष्ट है कि समाजवाद में अच्छे काम के लिए अधिक वेतन का पूँजीवाद से कहीं अधिक, प्रोत्साहन रहता है। श्रीमान् व श्रीमती बेव का तो यहाँ तक कहना है कि सोवियट रूस में अधिक योग्य परिश्रमी तथा उत्साही काम करने वालों का नीचे दरजे से ऊँचे दरजे में पहुँचने के अवसर बहुत अधिक हैं। अन्य किसी देश में साधारणतया वे इतने स्वाभाविक नहीं रहते इस बात में पूँजीवादी मालिक प्रायः रूस के उद्योगिक संचालकों की ओर ईर्ष्या से ताकते हैं। वे लाभ उठाने में अपनी दूरदृष्टिता को सब से अधिक समझते थे। परन्तु इस प्रकार के प्रोत्साहनों द्वारा रूस में मजदूरों से इतना अधिक और अच्छा काम होते देखकर उन्हें भी आश्चर्य होता है। फिर नीचे दरजे से ऊँचे दरजे में जाना तो पहिली ही सीढ़ी है समाजवादी संगठन में प्रत्येक काम करने वाला यही नहीं कि वह कार्यकर्ताओं में सर्वोच्च श्रेणी के काम तक पहुँच सके वरन् उससे भी आगे प्रबन्धको और संचालकों के उच्च उत्तरदायित्व के पदों पर पहुँचने को इच्छा करता है और अपनी ही चेष्टाओं द्वारा पहुँचता भी है। निस्संदेह इन पदों का वेतन उससे भी अधिक होता है। अस्तु

अवसर न मिलने से हानि

काम के लिये प्रोत्साहित करने वाले प्रलोभनों में अधिक वेतन का लालच प्रमुख है जिससे मनुष्य काम करते हैं और उन्नति की आशा बाँधते हैं। बहुत से स्त्री पुरुष इस उन्नति द्वारा प्राप्त शक्ति से काम करने के लिये लालायित रहते हैं। शक्ति से मान का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उच्चकोटि में उन्नति पाने से जन साधारण में वे योग्य माने जाने हैं। इस मान के लिये

वे सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं । कोई कारण नहीं कि समाजवादी संगठन में इस प्रकार के मान, पदक, इत्यादि का प्रयोग क्यों न हो, जिससे मनुष्यों में काम करने की प्रेरणा बढ़े । प्रचलित समाजवादी संगठन में ऐसे पदक तथा मानसूचक पदवियाँ दी भी जाती हैं और उनसे यथार्थ परिणाम भी होता है । भले ही इनके दुरुपयोगों से वर्तमान पूँजीवादी देशों में इस प्रकार के पदक घृणा और स्पृधा को दृष्टि से देखे जाते हों । देश रत्न, देश बन्ध देश प्राण, इत्यादि मान व पदवियाँ वास्तव में प्रोत्साहन का काम करती हैं । इसके अतिरिक्त ऊँचे दरजों में उन्नति से अधिक अच्छा और उपयोगी काम होता है । इसी के द्वारा मनुष्यों को शारीरिक व मानसिक शक्तियों के विकास का अवसर मिलता है । मनुष्य इसके द्वारा अपनी उपयोगिता रिद्ध कर पाता है, जिससे उसे आगे उन्नति का अवसर प्राप्त होता है । उरुकोट में पहुँचना ही एक बड़ा पुरस्कार है । उन्नति न कर सकना किसी मनुष्य के लिये एक बड़ा दुर्भाग्य है । प्रसिद्ध अंगरेज़ लेखक शेक्सपियर ने हेमलेट को उदासी का कारण केवल उसके इन्हीं वाक्यों से जान लिया था कि श्रीमान् मैं उन्नति में पीछे क्यों रह जाती हूँ ।" (why sir? I lack advancement) निराशा जीवन को ही हतोत्साह कर देती है । फिर आज कल पूँजीवादी देशों में लाखों मनुष्य केवल उन्नति में पीछे ही नहीं रह जाते वरन् उन्नति करने को उनकी आशा ही लोप हो जाती है । जनता के एक बड़े भाग से ज्ञान, शिक्षा, तथा बुद्धि के प्रयोग की सम्भावना ही छीन ली गई है । खदानों का पूरा प्रबन्ध कर सकनेवालों को प्रायः कोयला खोदने का ही काम मिलता है । बड़े बड़े कारखानों को सुचारु रूप से चला सकने की योग्यता रखनेवाले विशेषज्ञ, एक साधारण कर्मचारी (clerk) का ही काम करके अपना पैट पालने को विवश होते हैं स्थिति तो इससे भी गिरी हुई है । आर्थिक व्यवस्था की अनुपयोगिता के कारण अधिक योग्य और अनुभवी मनुष्यों को भी प्रायः साधारण कुली का ही काम करना पड़ता है । उन्हें अपनी योग्यता दिखाने तथा उसे बढ़ाने का अवसर ही नहीं मिल पाता । उन्हें तो केवल निराशा ही होती है, परन्तु उनकी योग्यता से

पूरा २ लाभ न मिलने के कारण समाज को कितनी हानि पहुँचती है इस का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे अधिक अंग्रेज और क्या हो सकता है ।

इसके विपरीत समाजवाद का तो यह दावा है कि उसमें प्रत्येक योग्य स्त्री पुरुष को यही नहीं कि अपने ज्ञान, बुद्धि तथा योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर ही मिलता हो, वरन् उन्हें अपनी शक्ति को प्रयोग करने का प्रोत्साहन दिया जाता है। और सत्य तो यह है कि वे एक प्रकार उन्हें बढ़ाने को विवश हो किए जाते हैं।

समाजवादी उद्योगों में ऐसे ही प्रलोभन रहने हैं जो मजदूरों को काम करने के लिये प्रोत्साहित करने हैं। दूसरे प्रकार के प्रोत्साहनों का अधिकतर प्रयोग सहयोग समितियों द्वारा बनने वाले पदार्थों में होता है। ऐसी समितियाँ खेती और तत् सम्बन्धी पदार्थों को उपज में काम करती हैं। गौक उद्योगिक पदार्थ बनाने में भी इनका कुछ भाग रहता है। इन संस्थाओं के उपज के साधन भी अपने ही होते हैं। और बनने पर पदार्थों का स्वामित्व भी इनका ही रहता है। इस प्रकार सामूहिक क्षेत्रों के किसान अपनी फसल के स्वयं मालिक होते हैं। पर अन्य किसानों की भाँति उन्हें भी शासन को कर देना होता है और उनमें उत्पन्न पदार्थ अनाज इत्यादि या तो वे उसी तरह आपस में बाँट लेते हैं अथवा उन्हें बेचकर विक्री से प्राप्त धन का बँटवारा कर लेते हैं। इसी भाँति कारीगरों के पदार्थ बनानेवाली सहयोगी समितियाँ भी, बने पदार्थों को बेचकर अपने सदस्यों को काम का पूरा पूरा भोग देती हैं। बाजारों में अच्छा मूल्य पाने का लालच ही उन्हें अधिक परिश्रम से अच्छा काम करने के लिये प्रोत्साहित करता है। अच्छे पदार्थ बनने पर उन्हें उनका मूल्य अधिक मिलेगा जिससे प्रत्येक की मजदूरी अधिक होगी। ऐसी ही स्थिति उन वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों, कारीगरों, मानसिक कार्यकर्ताओं सम्पादकों, लेखकों इत्यादिक की है जो अपने काम अथवा सेवाओं का स्वयं बाजार में सौदा करते हैं।

इन कार्यकर्ताओं की स्थिति, पूँजीवादी समाज से किनी प्रकार भी समाजवाद में भिन्न नहीं। क्योंकि दोनों में ही उनके काम का बाजार में सौदा होता है। और उनसे उन्हें धन मिलता है। अन्तर केवल इतना है कि समाजवादी संगठन में समितियों के सदस्य अपने काम से प्राप्त पदार्थ स्वयं अथवा समिति द्वारा बेचते हैं और उससे धन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत पूँजीवाद में एक पूँजीपति अपने मजदूरों के काम से प्राप्त सब पदार्थों को बेचता है। और मजदूरों के वेतनों की रकम से अधिक धन विक्री द्वारा प्राप्त करके लाभ उठाता है।

निजी काम की व्यवस्था

सहयोग समितियों के सदस्यों के सम्बन्ध में, जिनके द्वारा अधिकतर पदार्थ बाजारों में बेचे जाते हैं, कई प्रकार के मिश्रित प्रोत्साहन रहते हैं। सर्व प्रथम तो समिति के सब सदस्य यह भली-भाँति जानते हैं कि वटवारे की कुल रकम उनके परिश्रम पर ही निर्भर है। जितना अधिक परिश्रम वे करेंगे, उतना ही द्रव्य बढ़ेगा। और उसी के अनुसार उनके भाग में वृद्धि होगी। परन्तु तो भी एक बड़े समूह के कार्य में यह काफ़ी प्रोत्साहन नहीं होता और इसी कारण इन समितियों के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी अपने काम की संख्या और गुण के अनुसार ही कुल व्यय के वटवारे में पृथक् २ भाग मिलता है अथवा घण्टों के अनुपात से ही वैयक्तिक भाग निश्चित होते हैं। इन दोनों प्रोत्साहनों के साथ साथ एक और प्रलोभन भी रहता है। सामूहिक क्षेत्रों में सदस्य अपने कुटुम्ब की आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा उपज को बेचने के लिए वैयक्तिक कृषि कर सकते हैं और करते भी हैं।

इस प्रकार रूस में सामूहिक क्षेत्रों के किसान भी गाय, सुअर अथवा मुर्गी पालकर, तथा अपने मकान के आस पास तीन एकड़ तक वैयक्तिक कृषि करके, अपनी निजी सम्पत्ति को बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने को वे उत्साहित भी किये जाते हैं। प्रायः जिले की

मुख्य स्थाई उपज भी सहयोग के आधार पर ही की जाती है। परन्तु ऐसी वैयक्तिक उपज में भी कोई मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को वेतन पर रखकर उससे अपना काम नहीं करवा सकता है।

अस्तु, यही सब प्रोत्साहन है जो समाजवादी संगठन में मनुष्यों को काम करने में दिए जाते हैं। यही प्रलोभन हैं जो स्वार्थी मनुष्यों को भी काम करने तथा अच्छा और परिश्रमी काम करने को विवश करते हैं। इन्हीं प्रलोभनों के द्वारा रूस अपनी जनता से अधिक काम ले पाता है।

निस्स्वार्थ सेवाभाव

यह कहना भी उपयुक्त नहीं कि मनुष्य केवल अपने तात्कालिक वैयक्तिक स्वार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी बात की ओर ध्यान ही नहीं देने। वास्तव में वे आदर्शवादो स्वार्थ रहित प्रार्थनाओं पर भी पूरा ध्यान देने हैं। और कभी कभी तो ऐसी प्रार्थनाओं पर शीघ्रता से बिना विचार किए कार्य करने से अनर्थ तक हो गए हैं। अथवा ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे बुरे अथवा साधारण किन्हीं आदर्शों के लिए केवल कान कराना ही नहीं बल्कि मनुष्यों से जीवनोत्सर्ग तक करा देना सम्भव हो गया है। जन साधारण की भलाई की लड़ाइयों में मनुष्य प्रायः स्वभावतः कूदने पर तत्पर रहते हैं। और ऐसा करके बहुत सभ्यताओं तथा संगठनों का अन्त करने में वे सहायक भी हुए हैं। प्राचीन काल में वंश के वंश एक अथवा दूसरे धर्म के नाम पर प्राण दे चुके हैं। मान, प्रतिष्ठा इत्यादिक विचारों पर अंगणित आहुतियाँ दी गई हैं। मनुष्यों ने अनेक बार स्वार्थ तथा सम्बन्धियों को त्याग करके, अपना सम्पूर्ण जीवन किसी भी एक आदर्श के लिये लगा दिया है जिसे उन्होंने पवित्र समझा। इतिहास में ऐसे उदाहरण अनेको हैं जिनसे मनुष्यों की आदर्शवादिता तथा दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। जब इस प्रकार सब शासनों में किसी भी आदर्श के लिये लड़ने और सर्व त्याग करने के लिये मनुष्य उद्यत हो जाते

हैं जिनसे उनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं होता है तब फिर अपने आदर्शों की पूर्ति के लिये समाजवाद को ही क्यों ऐसे मनुष्यों की कमी रह सकेगी प्रचलित समाजवादी संगठन में शासन को इस प्रकार की सुविधायें पूर्ण रूप से प्राप्त भी हैं। ऐसी सुविधायें कुछ तो पुरस्कार अथवा दण्ड नीति से मिलती हैं। जो व्यक्तियों को प्रभावित तो करती हैं परन्तु उनसे उनके वैयक्तिक स्वार्थों को ठेस नहीं लगती। जैसे अच्छे काम के लिये सार्वजनिक प्रशंसा और बुरे के लिये बदनामी इस युक्ति का प्रयोग रूस में इस प्रकार होता है कि अच्छे काम करने वाले और उनके काम, एक प्रशंसा की सूची में लिखकर सार्वजनिक स्थानों पर टाँग दिये जाते हैं और बुरे कामों की सूची अलग बना दी जाती है और उसे भी किसी अन्य स्थान पर टाँग दिया जाता है। इसी तरह के उपाय हो सकते हैं। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि जनता की उपज की उन्नति में वास्तविक इच्छा हो। क्योंकि ऐसी इच्छा के बिना किसी प्रकार का भी सार्वजनिक दबाव उन्हें अच्छे काम करने को विवश न कर सकेगा।

पूँजीवाद में ऐसा सार्वजनिक दबाव हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उसमें अच्छे काम अथवा उन्नति के अर्थ पूँजीपति को लाभ पहुँचाना ही होगा। मजदूर को तो उससे कोई लाभ होगा ही नहीं और न समाज को ही उपज के साधनों पर पूरा आधिपत्य होने के कारण, पूँजीपति उपज की बचत का प्रायः सब भाग अपने ही लिये सुरक्षित रखेंगे। जनता को उपज की वृद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। परन्तु समाजवाद में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसमें तो कोई ऐसा अधिकारी वर्ग ही नहीं होता। उपज की वृद्धि से सम्पूर्ण समाज को लाभ मिलता है और इसी कारण उपज की उन्नति तथा अच्छे कामों के लिये सार्वजनिक दबाव डाला जा भी सकता है।

बांझित प्रतिद्वन्दता

प्रथम समाजवादी शासन रूस में ऐसी तद्दीर्घों का भी प्रयोग

किया जाता है ताकि मनुष्यों के भावों और प्रेरणाओं का पूरा २ लाभ उठाया जा सके। उदाहरण के लिये कामों में परस्पर प्रतिद्वन्दता करा देना, कोई व्यक्ति अथवा दल विशेष, अन्य व्यक्ति अथवा दल को, किसी विशेष काम के लिये ललकार दे कि अमुख कार्य को अधिक शीघ्रता से कौन कर पाता है परन्तु शीघ्रता में काम के गुण में कोई अन्तर न पड़ने पावे इत्यादि। ऐसे ही किसी गाँव अथवा कसबे की सम्पूर्ण जनता को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि अमुख विशेष आवश्यक कार्य सब को भलाई का है और उसे सबको मिलकर पूरा करना चाहिये। और वे सब किसी छुट्टी के दिन जुट कर उसे पूरा करा देते हैं। मास्को (Moscow) के तैखाने बनाने में मिट्टी को सफाई का काम इसी प्रकार लिया गया था। इसके अतिरिक्त उन्नतिशील संस्थाओं पर अशिक्षित अथवा कम उन्नति वाली संस्थाओं अथवा दल को शिक्षित करने तथा अपनी ही भाँति उन्नति शाली बनाने का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। किसी प्रारम्भिक पाठशाला के संगठन और उसके सुचारु रूप से चलाने का भार किसी एक कारखाने अथवा वैज्ञानिक क्लब को सौंपा जा सकता है। इत्यादि इत्यादि, ऐसी ही तद्वीरें समाजवाद में मनुष्यों से और अधिक अच्छा काम लेने के लिये की जाती है।

यह सत्य है कि पूँजीवादी देशों में भी मनुष्यों में समाज सेवा की इच्छा रहती है। और बहुत सा काम वेतन के बिना भी मजदूरों तथा पूँजीपतियों द्वारा अपने २ क्षेत्रों में किया जाता है। परन्तु समाजवादी संगठन में ऐसा काम कहीं अधिक, सरलता से सीधे तौर पर लिया जा सकता है। क्योंकि वर्गों की भिन्नता तथा वैयक्तिक एकाधिपत्य को असुविधाओं से इसे छुटकारा मिल जाता है। काम में सर्वसाधारण की भलाई की भावना एक बार जागृत हो जाने पर अधिकतर काम बिना वैयक्तिक पुरस्कार की आशा के ही होने लगता है। और प्रायः कल समाज के रहन सहन की उन्नति के सब काम इसी विचार से ही किया जाने लगता है। यही साम्यवाद की

स्थापना का समय होता है। जबकि ऐसा वातावरण हो जाता है कि अधिकतर काम केवल सार्वजनिक भावनाओं की प्रेरणा से ही होने लगे। समाजवादी संगठन में काम के लिये वेतन का प्रबन्ध रहे हुए भी, अधिकतर काम इन सार्वजनिक प्रेरणाओं से होता है।

काम में स्वार्थ

नवम्बर १९३५ ई० को प्रमुख रूसी कार्यकर्ताओं की एक कान्फ्रेंस में भाषण देने हुए स्टालिन (Stalin) ने कहा था कि पूँजीवादी संगठन में काम करनेवालों को अपना एक निजो स्थिति रहती है, यदि वह अधिक काम करता है। उसे अधिक वेतन मिलता है। और वह जैसे चाहे रह सकता है। दूसरों को उसे जानने की न आवश्यकता ही है और न वे जानते ही हैं। वे पूँजीपतियों के लिये काम करते हैं और अपने काम से उन्हें ही धनो बनाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई काम उनका है नहीं। इसी के लिये वे नौकर रक्खे जाते हैं कि लुटेहरों को धनो बनावें। यदि वे ऐसा करने को सहमत नहीं होते तो निकाल दिए जाते हैं, और उनके स्थान पर दूसरे जो उनकी इच्छानुसार ही काम करते हैं रक्खे जाते हैं। फिर उन्हें बैकार होकर अपने जीवन निर्वाह के लिये किसी धन्य को खोज करना पड़ता है। और इसी कारण पूँजीवाद में मनुष्यों के काम का अधिक मूल्य नहीं होता। रूस में स्थिति दूसरी ही है। यहाँ मनुष्यों के काम का मान होता है वे पूँजीपतियों के लिये नहीं स्वयं अपने लिए, काम करता है अपने वगं तथा समाज के लिये करते हैं। इसमें मजदूर अपने को निकाला हुआ अपमानित नहीं समझता।

इसके विपरीत वह अपने को देश का एक स्वतन्त्र जोव मानता है, वह एक सार्वजनिक व्यक्ति होता है यदि वह अच्छी तरह काम करता है। और अपनी योग्यता और शक्ति भर समाज को सेवा करता है तो वह मजदूरों का नेता बनता है। उसकी प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है। दूसरे व्याख्यान में

स्टेलिन ने बतलाया था कि मजदूरों को समाजवाद में किसप्रकार की सहायता देना चाहिए ताकि वे अपने को परित्यक्त और एकाकी न समझें। उनका कहना है कि मनुष्यों की देखरेख ऐसी सावधानी से होनी चाहिये जैसे कि एक माली फल देनेवाले वृक्षों को करता है। समाज का काम है कि वह उसे शिक्षा दे, बढ़ने में सहायक हो, उन्नति के अवसर प्रदान करे, समय से उसे उच्च पदवी दे, अपने काम के लिये अयोग्य होने पर तुरन्त ही उसे उसके योग्य काम में लगावे उसके असमर्थ हो जाने का अवसर ही न आने दें। उसे पूरी सतर्कता और सावधानी से मनुष्यों को बढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने और उन्नति करने का प्रबन्ध कराना चाहिये इत्यादि ..।

अन्त

संक्षेप में, किसो भी आर्थिक संगठन में मनुष्यों से शक्ति भर काम लेने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें भिन्न भिन्न प्रकृतियों के स्त्री पुरुषों के लिए उनके स्वभावों तथा समय के अनुसार ही प्रोत्साहन हों। मनुष्य भिन्न भिन्न प्रलोभनों से काम करते हैं। समय समय पर उनके भाव भिन्न भिन्न रहते हैं। कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने निजी स्वार्थ के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। किसी दूसरे अवसर पर वे अपनी आदर्शवादिता के भावों में संसार को ही आश्चर्य में डाल देते हैं।

भावों में भिन्नता के कारण, काम को संख्या और गुण के अनुसार जन समाज में आय के बाँटने का समाजवादी ढंग ही वर्तमान संसार के लिए अधिक उपयुक्त है। क्योंकि इसमें वेतन के साथ प्रयोग की भावना से काम कराने की प्रेरणा का भी संमिश्रण रहता है। सोवियट रूस में ऐसे समाजवादी प्रोत्साहन बड़े शक्तिशाली सिद्ध हुए हैं। और पिछले कुछ वर्षों में ही उन्होंने संसार को जता दिया है कि उपज की उन्नति के लिए न तो लाभ की इच्छा का प्रोत्साहन ही अनिवार्य है और न पूँजीपति वर्ग का रहना ही। इन दोनों के बिना,

वैयक्तिक सहित समाज में, वैयक्तिक भाग को इच्छा न होते हुए भी समाज की उपजाऊ शक्तियों की उन्नति केवल सम्भव ही नहीं वरन् निश्चित है।

अस्तु, समाजवादी संगठन को प्रयाप्त संख्या में काम करने वाले मनुष्यों के न मिल सकने अथवा अच्छा और परिश्रमी काम न हो सकने की आशंका का तनिक भी भय नहीं। उसके विपरीत, यही नहीं कि समाजवाद में पूँजीवाद के समान ही काम के लिये प्रोत्साहित करनेवाले प्रलोभन हैं। वरन् परन्तु उससे कहीं अधिक तथा शक्तिशाली प्रलोभन समाजवाद में होते हैं। जिनके द्वारा केवल उपज की उन्नति ही नहीं होती वरन् सम्पूर्ण समाज उपजाऊ शक्तियों, का पूरा २ प्रयोग पाकर, दैशवासियों के जोदनों की आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त कराके शान्ति वातावरण में सुखी और उन्नतिशाली रहता है।

इसीलिए तो समाजवाद को विशेष आवश्यकता है। क्योंकि इसके बिना समाज की उन्नति हो ही नहीं सकती।



